(iv) Reported Power Crisis in West Bengal

PROF. SAMAR GUHA (Contai): The power crisis in West Bengal has created a near catastrophic situation in West Bengal leading to closure of industrial and engineering units, and educational institutions and trade and business markets. The economic and social life of Bengal, as a result of a crisis of unprecedented dimension is almost on the verge of collapse. This crisis will spill over into labour troubles and generate unrest in the State, causing serious law and order stuaton.

The Central Government must intervene immediately to save West Bengal from the impending chaos and extend all assistance for tiding over the crisis.

MR. SPEAKER: I have fixed a Calling Attention on this issue tomorrow.

RE. DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir, as the House is aware, rather painfully aware, so far as the Demands discussion is concerned, owing to circumstances mainly or largely beyond our control we are very much behind schedule and as the dreaded doomsday, 23rd April, draws near, there is growing apprehension that more and more Ministries will be laid low by that lethal weapon—the guillotine. I think the ministers concerned will be happy but the House, I am sure, will not be happy. So, I daresay the Hou[illegible] will agree that we must t[illegible] as many Ministries as po[illegible] execution—I mean not mi[illegible]ut Ministries Demands. We have less than forty hours....

MR. SPEAKER: To be exact we have only twenty-five hours and fifteen minutes.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: In that case it is more dangerous. I am sure the House will agree with me, to save as many Ministries as possible, to sit daily till 7 O'clock in the evening and also one Saturday.

MR. SPEAKER: I will put it before the Business Advisory Committee.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I would, however, like the Minister of Affairs Parliamentary and hard Labour—in a genuine democracy like ours Labour is not a soft portfolio—to give a firm and solemn assurance that the time allocated for the financial business till the passing of the Finance Bill will not be mis-appropriated or encroached upon or intruded into by legislative business.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, on the first part of the hon'ble Member's suggestion you have been pleased to say that you will put it before the Business Advisory Committee. On the second part where he has asked me to give an assurance that no legislative business will be introduced till the Finance Bill is passed, I can say that Government has no intention of appropriating any time that has been allotted for the Demands for Grants. If any inroads are made into this time it will not be by the government.

12.39 hrs

DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—*Contd.*

Ministry of Agriculture & Irrigation —*contd.*

श्री नाथू सिंह (दौसा) : परसों जब मैं कृषि पर बोल रहा था तो मैंने सिंचाई और बिजली की कमी की चर्चा की थी जिस के अभाव में कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति नहीं हो सकती है और किसान की दशा सुधर नहीं सकती

[श्री नाथ सिंह]

है । मैं उदाहरण देता हू । पूरे देश म जितनी बिजली पैदा होती है उसका केवल साढ चौदह प्रतिशत किसानो को दिया जाता है, कृषि पर खर्च की जाती है और बाकी सारी उद्योगो और शहरो पर खर्च कर दी जाती है । किसानो से रेट भी तीस पैसे की यूनिट चार्ज किया जाता है जबकि टाटा और बिडला की फैक्टरीज को तीन पैसे और पाच पैसे के हिसाब से बिजली दी जाती है । किसानो को क्यो यह महगी दी जाती है, उन्होने कौन सा पाप किया है जिस का खमियाजा उनको भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है ।

मै राजस्थान मे आता हू । राजस्थान का इलाका हिन्दुस्तान के गलिस्तान पर एक धब्बा है, काला धब्बा है, फोडा है । हिन्दुस्तान को गुलिस्तान कहा जाता है लेकिन उसका जो एक बहुत बडा भाग राजस्थान का रेगिस्तान है उसकी तरफ पिछले तीस साल मे ध्यान नही दिया गया है, वहा न बिजली की और न इरिगेशन की कोई व्यवस्था की गई है । तीसरी लोक सभा मे कामत साहब बैठे हुए है, एक मामला उठाया गया था और उस समय बजट डिवलपमेंट बोड बनाया गया था । उसने आज तक क्या किया है मुझे मालम नही है । उस समय सुब्रह्मण्यम साहब मिनिस्टर थे । तब उन्होने इस सवाल को टाल दिया था । कामत साहब ने इस पर जोर दिया था । उस मे कोई प्रगति नही हुई है । जितना रेगिस्तान उस समय था आज वह और भी ज्यादा बढ गया है । छोटे से देश इजराइल को आप ले । वहा भी भयकर रेगिस्तान था जिस को नैगेव कहा जाता था । उन्होने बडी खबसूरती के साथ उस पर काबू पाया और उसको गुलिस्तान बना कर रख दिया । अब इजराइल मे रेगिस्तान नाम की चीज नही है । दुनिया भर म रेगिस्तान के एक्सपर्ट बहा है । क्या भारत सरकार ने कभी उनको बुलाने की कोशिश की है और उनको हिन्दुस्तान का रेगिस्तान दिखाया है और उन से पूछा है कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है । 1965 मे इजराइल के कुछ एक्सपर्ट बधे आए थे और वहा तीन साल तक रुक कर उस इलाके की उन्होने कायापलट कर दी थी । तब से आज तक इजराइल के एक्सपर्ट्स से कभी सम्बन्ध स्थापित नही किया और न ही उनको बुलाया । समय आ गया है कि वहा से विशेषज्ञो को बुला कर उनकी सलाह ले कर राजस्थान के रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया जाए, उसकी कायापलट की जाए ।

तीस साल तक सरकार कृषि के प्रति उदासीन रही है उसने इसको निगलेक्ट किया है । यह चीज देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है । पचास प्रतिशत आय कृषि से होती है, अस्सी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है उसके बावजूद सरकार कृषि पर ध्यान नही देती है । परिणाम यह हो रहा है कि कभी महगाई बढती है, कभी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है । महगाई रोकने के लिए सरकार दूसरे उपाय करती है । किसानों के बारे में बाते बहुत ऊची ऊची की जाती है । यह कहा जाता है कि उन्हें सुविधाये दी जा रही है, फूड फार वर्क उनके लिए चला रहे हैं, गरीब लोगो के लिए चला रहे है, अन्त्योदय योजना चल रही है । काम के बदले अनाज देने की जो योजना आपने चला रखी है इसके अन्दर किसानो और मजदूरो का सडा हुआ अनाज दिया गया है । कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने मे जो अनाज भर कर रख लिया गया था और जो सड़ गया है और जिस को पशु भी नही खाते है, वह उनका दिया जा रहा है । आप इसकी जाच करे और देखे कि कही आपके अधिकारी आपको धोखे मे तो नही रख रहे है । इस योजना के अन्तर्गत जो काम हो रहा है, कच्चा हो रहा है, पाच सौ का काम कराते है तो एक हजार का काम हुआ है, यह दिखा दिया जाता है । जो कच्चा काम करवाया जा रहा है बारिश शुरू होते ही यह साफ हो जाएगा । सडके, रास्ते जो कच्चे बनाए जा रहे है इनको पक्का बनाया जाना चाहिये ।

जहा तक किसानो को लोन देने का सम्बन्ध है केवल ग्यारह प्रतिशत लोन ही बैंको से किसानो को दिया जाता है, कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है । किसान का सब्सीडी बहुत कम दी जाती है । अगर कोई इडस्ट्री लगाई जाये तो गवर्नमेंट 75 स 90 परसेंट तक लोन और सब्सीडी देती है, 75 परसेंट लोन दिया जाता है, लेकिन किसान अगर लोन ले तो उसे आसानी से लोन नही मिलता है । आज किसान कृषि का काम मजबूरी म कर रहा है, उसे आपने कृषि के लायक नही छोडा है । अगर कृषि का इडस्ट्री की तरह विकास किया जाये, तो काफी उन्नति हो सकती है । मै जानना चाहता हू कि क्या सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण कराया है कि गावो की दशा कैसे सुधारी जा सकती है ? मेरा निवेदन है कि गाव का इडीपैंडेंट बनाइये । गाव म जट, अनाज, रुई, तेल पैदा होता है, वहा आप छोटी-छोटी इडस्ट्रीज लगाइये । किसानो का सामान खेतो मे उपज और वहा छोटी-छोटी इडस्ट्री हो जिनमे उस कच्चे माल को पक्का माल के रूप मे परिवर्तित कर दिया जाये । उसमे से किसानो की आवश्यकता के अनुसार उनको दिया जाये और बाकी का शहरो मे भेज दिया जाये । अगर आप ऐसा नही करेंगे, तो मै एक उदाहरण देना चाहता हू । भगवान श्रीकृष्ण ने एक मटकी फोड़ आन्दोलन चलाया था और उनका वह आन्दोलन शहरो के विरोध में था । उसका रूप ऐसा था जैसे सत्याग्रह करते है । उनका वह आन्दोलन इसलिये था कि शहर वाले किसानो का शोषण करते है । शहर वाले गाव वालो का घी-दूध मक्खन खरीदते थे, लेकिन गाव वालो को उचित मूल्य नही देते थे । इसीलिए भगवान कृष्ण को मटकी फोड आन्दोलन की जरूरत पडी । इसलिये आज आवश्यकता है कि किसानो की दशा सुधारी जाये, उनका गावो मे इडीपैंडेंट बनाया जाये ।

MR. SPEAKER : Please conclude now

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : He is the youngest Member of the House, the baby of the House; so, he may be given some more time.

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): And this is the International Year of the Child, he should be given preference.

श्री नाथू सिंह : एग्रीकल्चरल एजूकेशन के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है। वहां राजस्थान में बार-बार फसलों का नुकसान होता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। राजस्थान में बहुत ओला पड़ा है, क्या सैंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी टीम भेजी है कि वह देखे कि इस से वहां कितना नुकसान हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा में तहसील हैडक्वार्टर में ओले से फसल चौपट हो गयी है, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। उनसे जो लगान लिया जाता है, राजस्थान सरकार ने केवल उसे आगे के लिये हटा दिया है। क्या आप केन्द्र से कोई इन्तजाम करेंगे कि उनको जो नुकसान हुआ है, उसका कोई मुआवजा उनको मिल सके ?

एग्रीकल्चरल एजूकेशन के बारे में एक समिति श्री रन्धावा के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसने अपनी 1978 में रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में बताया है कि उसको राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। राज्य सरकारें क्या जवाब देंगी ? कई राज्य सरकारें तो ऐसी हैं कि सदन में जो कई गालियां जाती हैं, उनके बारे में भी कोई जवाब नहीं देतीं क्योंकि ज्यादा-तर की सरकारें हमारे ऊपर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के बारे में सरकार की क्या नीति है, और आप कब तक उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने जा रहे हैं ? इसके बारे में कृषि मंत्री बताने की कृपा करें।

कृषि के साथ आने वाले औजारों और जो कृषि पैदा करते हैं उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आलू का भाव 5 रुपये क्विंटल वहां पर है, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। वहां आलू इतना पड़ा है कि 5 रुपये क्विंटल पर बिक रहा है और यहां दिल्ली के मार्केट में, आप तो शायद लेने नहीं जाते होंगे, डेढ़ रुपये किलो आलू मिल रहा है। वहां कोई खरीदने वाला नहीं है, यह कैसा मजाक किसान के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब कृषि के मामले में सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश सब से बड़ा प्रदेश है। कृषि तथा सिंचाई मंत्री पंजाब के हैं और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। इस समय मौका है कि वे किसानों का कुछ भला कर सकते हैं। अगर उन्होंने यह मौका खो दिया, तो मुझे किसानों का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। वे दोनों कृषि के एक्सपर्ट हैं, योग्य हैं और किसान हैं। इस लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के लिए कुछ करें और उनकी समस्याओं को हल करें।

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): I am very happy to participate in the discussions on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I want to make a few observations for the consideration of the Government.

When the Food Corporation of India was started in Madras in 1965, we expected that it will render good service to the public. But to our disappointment, from that year, our troubles have increased, even though we have produced more. Along with more production by the farmers, more troubles have also been created for the farmers by the policies of the Food Corporation. Even though the previous Government and this Government are sympathetic to the farmers, the officers and their policies are going on as before, as far as rural development is concerned. We were not satisfied even with what was happening during the period of the previous Government. I am not blaming this Government alone. As far as farmers are concerned, the same consideration and treatment are being given in the matter of price fixation and procurement.

As far as Andhra Pradesh is concerned, I have been told that recently 100 telegrams have been sent to the Food Corporation from the Kaikalur taluk in my constituency, which is a Kolleru area, about their not making procurement It is not about the price, even though price also has not been fixed. I have already said that agricultural classes, including agricultural labourers in the rural areas constitute 70 per cent of the people of India. We are pouring on them only slogans and sympathetic words. We are not helping them in any practical way If you see the other countries, you will find that the agricultural communities there are being given all facilities. Whatever our friend has said, is correct. You are procuring the produce from the villages, but you are spending money on industries located in Ghaziabad and Delhi. Because the officers are here, they will try only to give benefits to their children, and not to give benefits to villagers.

I am surprised to see that the banks are giving advances only to mill-

owners and not to the tillers of the soil. For the last 15 years, there is a rule. The Act has not been amended. The Reserve Bank has not been allowed to give a single rupee as produce loan to the farmers. The farmer is not being given a proper price; and the agriculturists are not given other facilities also.

Recently, to my surprise I have found that a circular has been issued by the Ministry of Labour, New Delhi. I asked the Labour Minister about it. He said it was not within his knowledge. It has been said that if rural development goes up, the agricultural labour will be harmed. But agricultural labour will be harmed only by urban people, because you are not paying a proper price for agricultural produce. You are developing industries only in urban areas. That is why I am blaming the officers and the Government. As my friend on the Government side said, the Government has failed, in fixing the sugar cane price, and it has not fixed the responsibility for the losses. Only in the matter of industrial, finished goods, they are taking into account the manufacturing costs while fixing prices.

Go to Korea or Japan; you will find that all the industries are not centralised in cities there, comparable to our Madras, Delhi or Bombay.

12.54 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

Having industries in places like Faridabad is not enough. I want to suggest to the government now or hereafter also, when they are fixing the cost of the finished goods, why they should not consider the price fixation of the products of the rice producer on the basis of the cost of production. Some officers, IAS or IFS who are handling the subject, they are not bothered about agriculture, they are bothered about free education, free transport, free guest houses for their comforts. I have seen the report of the agro-industries corporation which has come today. It shows that every institution lost Rs. 10 lakhs of rupees. People there have manipulated figures; they have manipulated import policy; they keep all the goods which are imported and are not selling them in the market immediately. In the last two months I have brought a case to the notice of the Minister of State in the agriculture ministry and he was kind enough to release the stocks of fertilisers. All high officers are sitting here. Who is responsible for this. In 1975 they imported chemical fertilisers; it is stored in my constituency for the last four years. It is Rs. 1500 only per ton. I think in the black market it is high. 1800—2000 tonnes are in the godown, a private godown. Every month they are paying Rs. 6,000 rent. All the ministers are here. Their departments are having people like this. In six years they have sold only 300 tonnes. When they were approached by the house owner, the godown keeper to vacate the godown they say: you must bear all the cost because it is not transportable, all the bags should be rebagged, and transport it at your cost. Even if the ministry ordered it, for two months it is only correspondence. But four days back I was told that at the cost of the building owner they have moved the stocks to some extent—about 200 tonnes. Is this the way? There is demand for good fertilisers, imported fertilisers. There is demand in my district which has the highest production and highest consumption also in Andhra Pradesh just like Punjab and Haryana. On the other hand, the entire agricultural community, is not satisfied about the government. Even both the Ministers have given so many assurances and both are coming from the agricultural community, we are not satisfied. What is the use of being a minister. We want benefits for their labour and material benefits from you to the agriculturists. Agriculture means what? After all the land reforms and all these things, still they say in their offices, officers drawing 10,000 and 5,000 that who are having 10 acres or 15 acres are called Kulaks, we are not for the kulaks. We are for the people who are without any earning capacity other than agriculture. We are not taking any contract from you to pro-

duce more paddy; we are producing without any contract. But in industry, only 10 or 15 per cent will be collected as share capital. About 80 per cent of the money they are borrowing from the Government. By the time they finish the construction, they are having 20 per cent back in other ways. But what about agricultural labourers? Unless agricultural labour also prospers the country cannot prosper. Please let me know. In the villages how many are without food? There are so many beggars in the cities, without food, round about your secretariat or office. Is there one man in the village like that? That is heriditary socialism or communism. We are feeding the country; we are producing without any hesitation. We, the farmers, are making so much sacrifice. Now this circular from Labour Ministry has been issued which creates a conflict between the agriculturists and agricultural labourers. They want to create an impression as if they are only for agricultural labourers.

13 hrs.

I have got reports here to show how prices are being maintained here and in other countries. In a small country like Korea, in 1970 the income of an agricultural family was 747 dollars per year as against $ 1112 dollars which was the income of a family of workers in the urban area. Within eight years, gradually the income of agricultural families has gone up and now they are getting $ 2876 dollars per year whereas a family of workers in the urban area gets an income of only 2379 dollars per year. In South Korea, in 1970 the price of 80 kg of rice was 7000 Wons. Gradually year by year it was increased without causing hardship to the consumers, whose purchasing capacity also has been gradually going up and in 1977, the price of 80 kg of rice was 26,260 Wons. They have brought the income of agricultural families to the same level as that of families in urban areas. No such thing has been done in our country.

The Food Corporation is a complete failure so far as Andhra Pradesh is concerned. Even the Chief Minister, of Andhra Pradesh, Dr. Chenna Reddy has blamed the Food Corporation. In my district of West Godavari alone, there is a surplus of 3.37 lakh tonnes of rabi crop lying with the farmers. The farmers are not allowed to get loans on their produce. Only the traders and millers are given loans. They are taking advantage of this to purchase the crops from the farmers at low prices. The farmers do not have even money to pay land tax. So, the rules should be amended to enable the farmers to get loans on their produce.

So far as sugar factories are concerned, some factories are making huge profits while others are suffering. Last time also I raised it. I had given a memorandum to Mr. Charan Singh, the then Home Minister, now Finance Minister, to appoint a Commission to enquire into the sugar industry. He told me that he had appointed so many commissions for which he was being blamed, so he wanted to forward my complaint to the Minister of Agriculture. But nobody is prepared to enquire. If there is some enquiry, I am prepared to give evidence. Even if you nationalise sugar industry completely, I have no objection. The Government is giving crores of rupees as loans to the sick mills. Whose money are you giving? You have duped the people. There are so many sugar factories running at losses. In the case of my own cooperative sugar factory at Bhimadole, the managing director is the Collector. The factory has incurred a total loss of Rs. 2 crores and not a pie of dividend has been declared for five seasons. We have paid Rs. 3 crores of excise duty in five seasons to the Government of India. It is not our fault. This year the farmer is not going to grow more sugarcane. The area under cultivation is going to be reduced. As a result, 100 factories would be closed in the country. Please look into the matter immediately and do something constructive.

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैडम चेअरमैन, आज कृषि विभाग की मांग हमारे सामने ज़ेरे-बहस है। इस में कोई शक नहीं कि किसी भी देश की जिन्दगी और सेहत के लिये कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के साथ जो सुलूक हो रहा है, वह कुछ ना-ज़ेबा है। इन मांगों का हमें समर्थन तो करना ही है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो दो मिनिस्टर इस काम को देख रहे हैं उन का कृषि से ताल्लुक रहा है, वे खुद किसान हैं, इस लिये किसान की जो समस्यायें हैं, उन से वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन उन की भी कुछ मजबूरियां हैं, लाचारी है। वे करना तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते और एक दफा इसी हाउस में हमारे भानु प्रताप सिंह जी ने साफ अलफाज में कहा भी था—इस के बारे में मेरे व्यूज स्पष्ट हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां भी इस के साथ हैं।

मैडम, 7–8 रोज की बात है। किसी सवाल के जवाब में हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किसी मेम्बर को कहा था—अगर आप मेरी जगह यहां पर होते, तो आप को भी ऐसा ही जवाब देना पड़ता। अफसोस यह है कि उस कुर्सी पर कोई भी बैठ जाये, चाहे कोई किसान बैठ जाय या कोई दूसरा आदमी बैठ जाय—उस का वही जवाब आयगा। पिछले 10 सालों में हम ने पिछले कांग्रेस हकूमत के अमालो-अफआल को कृषि के बारे में देखा और अब अपनी जनता पार्टी के अन्दाज को भी देख रहे हैं, मुझे तो कोई नुमायां फर्क मालूम नहीं दिया। हमारी हुकूमत कहती है कि हम को एक सब से बड़ा श्रेय यह है कि हम ने देश में एमर्जेन्सी का खात्मा कराया—यह बात ठीक है, लेकिन मैं अपने वजीर सहिबान से पूछना चाहता हूं—किसान के ऊपर तो आज भी एमर्जेन्सी लगी हुई है, आज उस की क्या हालत हो गई है, उस के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? यहां पर कुछ वेस्टेड इन्टरेस्टस हैं—मुझे बड़ा अफसोस होता है—जब कृषि के बारे में यहां पर बोलते हैं चाहे वे किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, यही कहेंगे कि हमें किसानों का भला करना चाहिये, लेकिन जब किसानों को कोई सहूलियत देने की बात आती है, तो वे उस का विरोध करते हैं। एक तरफ कहेंगे कि रिम्यूनरेटिव प्राइस दी जाय, लेकिन जब रिम्यूनरेटिव प्राइस देने का वक्त आता है तो सब खड़े हो कर कहते हैं कि सब मारे जायेंगे। महंगाई हो जाएगी और इस से लो इन्कम ग्रुप वाले मिडिल इन्कम ग्रुप वाले और कन्ज्यूमर मारे के मारे मर जाएंगे। इस किस्म की बातें हाउस के अन्दर करने लगेंगे। अगर किसानों को ज्यादा कीमत दी जाएगी, तो ये सब मर जाएंगे लेकिन हम ने देखा है कि आज तक तो कोई मरा नहीं। अफसोस की बात यह है कि कोई मरता नहीं लेकिन उन की लोबी जो है वह बहुत मजबूत है और किसान की लाबी जो है वह बटी हुई है। इन्डस्ट्रियलिस्टस के सहारे स्पोक्समैन ऊपर से कुछ बोलते हैं और होता कुछ और है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। किसानों के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं। कभी कभी यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, उस पर देश की खुशनामी, देश की खुशहाली निर्भर है और साथ में यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक इन्डस्ट्री है लेकिन हमारे वजीर साहबान जरा इस तरफ तवज्जह दें कि इन्डस्ट्री को जहां इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहां एग्रीकल्चर को क्या मिलता है। पावर के चार्जेज इन्डस्ट्रीज के लिए हरियाणा और पंजाब में बहुत सीगर हैं। वहां पर 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को, कारखानेदारों को मिलती है जबकि किसानों को 31 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है। यह हालत आज है। इतने सीगर चार्जेज इन्डस्ट्री वालों के लिए और इतने हाई चार्जेज किसानों के लिए हैं। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए इन्श्योरेंस भी होता है और किसानों के लिए क्या होता है। इन्डस्ट्रियलिस्टस को हर तरह का प्रोटेक्शन दिया

What about the kisan? He is entirely left at the mercy of the politician, at the mercy of the middlemen, at the mercy of thieves, at the mercy of pests, at the mercy of hailstorms, floods, droughts, animals, birds. He has to face lack of storage facilities, lack of transportation, so many things

जाता है। किसान के दुश्मन ही दुश्मन खड़े हुए हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों ओले गिरने लगे और पिछली बरसात के अन्दर यू०पी०, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देहली आदि जगहों पर फ्लड्स से सारी फसल बर्बाद हो गई। अभी जो ओले गिरे उस का असर हरियाणा दिल्ली और यू०पी० के अन्दर हुआ और शायद पंजाब के अन्दर भी उस का असर हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की दोनों फसलें, रबी की फसल और खरीफ की फसल खराब हो जाए, तो क्या वह जिन्दा रहेगा। कोई सवाल उस के जिन्दा रहने का पैदा नहीं होता। तो आज किसान की यह हालत है। वह जिन्दा रहता है और अनाज की कमी तो वह बर्दाश्त कर लेता है लेकिन चारे की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चारा न हो, तो किसान की तबाही ही तबाही है। इस के साथ ही दो तीन दिन से आलुओं का जिक्र किया जा रहा है। नाथू सिंह जी ने बताया कि राजस्थान में आलू 5 रुपये क्वींटल है और कपास का क्या भाव है। इस के लिए लोग नारे लगाते थे, पिछले कपास के सीजन में हरियाणा के अन्दर सरसे में मैं ने सुना कि लोग यह नारा लगाते थे 'देखा जनता राज का ठाठ, नरमा बिकता 260'। पहले कपास का दाम 400, 500 रुपये था और अब 260 रुपये हो गया। जनता पार्टी के राज में नरमा का यह भाव हो गया और फिर भी कपड़े के भाव को आप देखिये। गन्ने का पिछले साल क्या हाल हुआ। यू०पी० के अन्दर उस को

जलाना पडा और हरियाणा के अन्दर भी बरी हालत हुई। गन्ने का क्या दाम किसान का मिला और आज क्या हालात आलू की है, प्याज की है। जिस चीज की तरफ भी देखो, किसान की मदद किसी वक्त पर हुकूमत करने आई। गन्ना कपास आदि जो किसान पैदा करता है उन सब की कीमते इतना नीचे चली गई लेकिन किसान की मदद किसी ने नही की। मुझे एक शेर याद आता है :

कश्ती तूफान में डूब गई मगर किसी ने मदद न की
अल्लाह भी था मल्लाह भी था लगर को सहारा मिल न सका।

हकूमत भी थी हमारे वजीर साहिबान भी बैठे हुए थे, जनता पार्टी भी यहा पर थी इडस्ट्रियलिस्ट्स भी थे इनके नुमाइदे भी यहा पर थे लेकिन किसान जो आलू, गन्ने, कपास, प्याज आदि की कीमतो की गिरावट की वजह से तबाह होता चला जा रहा था तो किसी ने मदद नही की कोई उसको सहारा देने के लिए नही आया। मै चाहता हू कि आप जा कर किसान की हालत को तब देखे जब वह खेत मे काम कर रहा होता है। एक दिन एक शहरी आदमी जब मैं खाना कर रहा था तो मेरे खेत मे आ गया। मेरी हालत को देख कर वह मजाक मे कहने लग गया कि अगर किसान न होता तो शायद खेती इसान को करनी पडती। मै सभा महोदय से पूछना चाहता हू कि इस किसान को सजा किस चीज की दी जा रही है। बडे फख के साथ हाउस में कहा जाता है, हिन्दुस्तान मे ऐलान किया जाता है कि हमने इतना अनाज पैदा कर दिया है और इतना अनाज पैदा हो जाएगा। किसान का खून पसीना निकल चुका है वह सारा जोर लगा रहा है अनाज पैदा करने के लिए यह सब इसलिए कर रहा है ताकि आपका खिला सके। अगर आप उसको कुछ सहूलियतें दे तो शायद वह एक्सपोर्ट करके भी आपको दिखा दे और बहुत जल्दी दिखा दे। आप आलू का एक्सपोर्ट क्यो नही करते है। श्री माहन धारिया ने एक दिन कहा था कि पच्चीस हजार क्विंटल हम एक्सपोर्ट करेगे। उसी दिन मैंने कहा था कि इससे क्या होगा? आलू की फसल इतनी ज्यादा होने वाली है आप ज्यादा क्यो नही करते है। लेकिन कोई ध्यान नही दिया जाता है। मै पूछता हू कि किस चीज की सजा किसान को आप दे रहे है।

नहर के किनारे तीन मैंढक बैठे हुए थे, एक के ऊपर एक। सब से ऊपर वाला मैंढक जो था उसने आवाज दी टर्रमटर। इस पर खुशी के साथ दूसरे ने कहा जो उसके नीचे बैठा हुआ था दबा बैठा था, खुशी न गम। सब से ऊपर इडस्ट्रियलिस्ट था और उसके नीचे हकूमत थी। हकूमत ने कहा खुशी न गम। हकमत ने कहा कि मेरे नीचे भी तो एक दबा बैठा है और वह किसान था। इस पर तीसरे ने कहा मर वे हया। ऊपर वाला इडस्ट्रियलिस्ट, बीच वाली हकूमत और तीसरे किसान। किसान सब से नीचे था और सब का बोझ किसान के ऊपर था। यही हालत आज किसान की है। किसान को सभी दबाए बैठे है। यह नक्टो वाली बात हो जाती है। बजट मे किसान को क्या मिला है? पाच रुपये यूरिया के अन्दर कम हुए है, डीजल के अन्दर कुछ कम किया गया है। बाकी चीजो पर जो टैक्स बढा दिए गए है क्या उसका सारा बोझ किसान पर नही पडेगा? यहा पर इडस्ट्रियलिस्ट्स की लाबी बनी हुई है। यह तो नक्टे और लम्बी नाक वालो की बात है। जिस की छोटी नाक होती है उसके ऊपर यह नक्टे एतराज करते है। दूसरा को कहते है नाक आए नाक आए। इडस्ट्रियलिस्टस की जो लाबी है इसने कहना शुरू कर दिया मर गए मर गए, सारा बोझ मिडलमैन के ऊपर आ कर पड गया। जब से मैने जन्म लिया है या मियायत मे 45 साल पहले से आया हू मुझे यह पता नही चल सका है कि एम्पलायीज की जो डिमाडज है क्या ये कभी खत्म होगी भी या नही? टीचर्स की आज तक खत्म नही हुई, रेहडीवालो की नही हुई ड्राइवज की, डेसू वालो की खत्म नही हुई। एक के बाद दूसरी निकलती चली आती है, एक को मान लिया जाता है तो दूसरे साल चार और निकल आती है उनको खडा कर दिया जाता है। लेकिन किसान को एक ही डिमाड है, आप कम से कम या तो उसकी बेहतरी के लिये उसे प्रोटेक्शन दे उसकी फसल तबाह हो जाती है, ओले पड जाते है पानी की कमी की वजह से, बरसात की वजह से नुकसान हो जाता है, उसको कितने दिनो से यह डिमाड चली आ रही है कि उसकी फसल का इश्योरेंस किया जाये। आपने उसकी फसल का इश्योरेंस करने का कोई इतजाम नही किया है। यह सरकार जिन्दा को तो चिपके हुए है लेकिन अगर किसान मर जाये तो भी उसके पीछे लग जाती है। उस पर ऐस्टेट डयूटी और वैल्थ टैक्स लगा दिया। एक तरफ तो किसान की जमीन को एक्वायर करने है और दूसरी तरफ जब मर जाता है तो ऐस्टेट डयूटी के लिये यम के दूत और उसके घर पहुच जाते है कि उसकी जायदाद की कीमत क्या थी। यह एस्टेट डयूटी के लिये मरे हुए आदमी को भी चिपटना चाहते है। मै यह भी बताना चाहता हू कि हिन्दुस्तान के किसान के जिस्म पर आज कपडा नही है, सिर्फ एक लगोट उसके जिस्म पर है और ये वेस्टेड इटरेस्ट के लोग इडस्ट्रियलिस्टस उस किसान के लगोट पर भी चिपटे हुए है। अगर यह लगोट टूट गया तो फिर वह क्या करेगे? मुझे गोल्ड स्मिथ की "दी डैजर्टेड विलेज" पोयम का कुछ लाइनें याद आती है, जो कि इस तरह :—

"Princes and Lords may flourish or may fade, A breath can make them as a breath has made; But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed can never be supplied"

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस किसान ने हिन्दुस्तान में आज अपना सिर ऊंचा किया, आपका हजारों, करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, उसने बचाया जिसके कारण आज आप दूसरे मुल्कों के सामने फख्र के साथ अपना सिर ऊंचा कर के खड़े हो सकते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी में यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान आज अनाज के बारे में आत्मनिर्भर है, उस किसान के साथ इस किस्म का सलूक आप न करें।

मैं श्री बरनाला साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मेरा उनमें बहुत अन्ध विश्वास है, मैं जानता हूं कि वह बहुत काबिल हैं, कि वह एग्रीकल्चरल पालिसी, कृषि नीति निर्धारित करने के लिये कृषि का इसके साथ योग करें। आप स्कैंडेनेवियन कंट्रीज, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जायें, वहां एग्रीकल्चरल पालिसी किसान की कंसलटेशन से की जाती है, बल्कि किसान उसे डौमिनेट करता है। लेकिन हिन्दुस्तान में किसान के साथ क्या सलूक किया जाता है कि उसको पूछा तक नहीं जाता। किसान के नुमाइन्दे क्या हैं, उनका भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। नीति निर्धारित करते समय उन लोगों का योग करते हैं जो ठंडे कमरों में बैठकर, शिमले में या कहीं और बैठकर किसान की कृषि पालिसी का निर्धारित करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा।

SHRI PALAS BARMAN (Balurghat) : The Janata Government, particularly its Deputy Prime Minister and Finance Minister seems to be very much concerned regarding improving the lot of the rural people In a country where about three-fourths of the population live in the countryside, this is as it should be. The question, however, is who are these rural people, for whom the Janata Government or its Finance Minister is really concerned? What has been the lot of the rural poor—the landless and the poor peasants—the vast army of landless agricultural labour—during the two full years of Janata Rule? How many landless peasants have been given land during this period, what has been done to ensure even the fixed minimum wages to agricultural labourers, what has been done to eradicate the bonded labour system from the face of rural India? It is by this criteria that the concern of any government for the rural poor would be judged and not by parrot-like repetition of concern for the rural people.

The performance of the Agriculture Ministry would be judged not merely on the basis of increase in the agricultural production of the country. It is no doubt an important aspect of its job. However, no less important is the condition in which the production takes place Under what condition the vast majority of the rural people are engaged in agricultural production? The poor peasants having a small plot of land are unable to take advantage of the improved methods of cultivation because they have no resources The major portion of peasants in our country are in this category Though they form a large percentage of land-holding population, the land area occupied by them is a small portion of total cultivable land The largest section of the rural population is, however, without any land of their own They till the land of others Needless to say, they work in the land not of the poor peasant but of the big peasants These are the new aristocrats More often than not they have made nonsense of land ceiling laws and have managed to corner large area of agricultural land by means fair or foul It is they who get maximum benefit of improved agricultural inputs It is for them that Choudhary Charan Singh's budget is liberal it is common knowledge that it is this section of the rural people who have thrived most after the abolition of landlordism It is they who now lord over the country poor and keep them in abject poverty

The Agriculture Minister fails to hold out any hope of a change in this picture and to uphold the interest of the village poor. Have any active steps been taken by him to ensure that surplus land is recovered and distributed among the poor and landless peasants? Even the work of distribution of the existing surplus land has made little headway in most of the States. The Prime Minister's home State which receives more than a fair share of the Prime Minister's

time, is reported not to have distributed any surplus land during these two years of Janata rule. How is it that the Prime Minister with his high moral stature would not make his own Party government move in this matter?

Our country has no dearth of persons who roll in wealth. If our agricultural produces fatten only a small portion of the rural people it cannot be said to have improved the face of rural India The Janata Government seems to be committed to the service of the few rich—whether in the industry or in trade or in agriculture resulting in more and more impoverishment of the common man Unemployment is rampant in villages but, as most of them are illiterates, their unemployment or under-employment seems to go unnoticed The food-for-work programme has been much eulogised but it is no employment programme but a simple variation of test relief. At the end of two years of ten-year deadline set by the Prime Minister for the end of unemployment, more persons stand unemployed.

The village people require today not lip sympathy but concrete measures for their uplift. That would require certain drastic steps The entire agricultural land should be redistributed among those who are actual tillers of the soil. Capitalistic mode of production should be banished from the agricultural field Viable land units should be given to actual tillers of the soil. Cooperative system may be introduced to allow for large scale peasant cooperative forming with improved inputs. Agricultural people who won't be provided with land, should be provided with jobs in agro-industries and cottage and small-scale industries. The setting up of agro-industries and small and cottage industries in countryside should not end in mere talks, of which there have been no dearth. People now want them to materialise. There is no other way to change the face of rural India. As one coming from the village, I can say that the government will be judged by what it does for improving the lot of millions of rural people. I may warn the government that they cannot be fed on mere words much longer. Time is fast running out. If even now, the Government does not change its ways, the people would not take their acute exploitation lying down any longer.

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) आप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, तेज बहादुर सिंह नहीं।

मैं बरनाला जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय ने अभूतपूर्व तरक्की की है और इसकी हमें आशा भी थी क्योंकि जनता राज में देहात की ओर और किसानों की ओर यदि ध्यान नहीं जाएगा तो किस की ओर जाएगा? 70–80 प्रतिशत नागरिक हमारे देहातों में रहने वाले हैं और 70–75 प्रतिशत के बीच में जो किसानी का काम करने हैं उन की बहबूदी के लिए अगर काम नहीं किया जाएगा तो हमारे देश की कोई तरक्की नहीं हो सकती है उस की फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकती है। आप कुछ आंकड़ों को देखें—77–78 में 125 6 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जो कभी नहीं हुआ था। तो इसका श्रेय बरनाला जी को और जनता पार्टी की सरकार को मिलना चाहिए। 77–78 में. (व्यवधान)

सभापति महोदय आप कृपया किसी की तरफ ध्यान न दें, अपनी स्पीच चालू रखें, दस दस मिनट में दे रही हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह देखिए उन को बीस बीस मिनट दिया है। बुन्देलखंड के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय जब सभी लोग इस तरह बीस मिनट लेंगे तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह : अभी मैं बताऊंगा कि बुन्देलखंड कितना उपेक्षित है। उस की ओर आप नजर रखें। आप भी वहीं से लोक सभा की सदस्या हैं।

77–78 में 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स में सिंचाई अतिरिक्त बढ़ी जो पिछले दस वर्षों में 1.5 मिलियन हेक्टेयर के औसत से आगे कभी नहीं बढ़ी। यह कमाल देखिए। अगले वर्ष 79–80 में 3 2 मिलियन हेक्टेयर होने जा रही है। इस से साबित होता है कि बहुत कटिबद्ध हैं और कमर कस कर हमारे कृषि मंत्री जी और हमारी सरकार कृषि की तरक्की के लिए लगी

[श्री तेज प्रताप सिंह]

हुई है। आप ऐसा न समझें कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूं। जो औसत हमारी पैदावार बढ़ रही है, औसत अतिरिक्त जो सिंचाई के साधन मुहैया किए जा रहे हैं इस के लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर में हुआ है। बिना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए हुए हमारे देश की कृषि उन्नति नहीं कर सकती है, पैदावार नहीं बढ़ सकती है। उस में भी आप देखेंगे कि 43 लाख टन का इस्तेमाल 77-78 में हुआ है। यह करीब करीब 26 प्रतिशत बढ़ोतरी है पिछले वर्ष के मुकाबिले में। तो मैं बधाई देना चाहता हूं और यह सही है कि वह पंजाब से आते हैं, पंजाब पर हमें नाज है, पंजाब पर कई माने में हमारे देश के लोग नाज कर सकते हैं, लेकिन बरनाला जी जरा ध्यान देने की कृपा करें वे पंजाब से आए हैं हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और इस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं यह हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन एक शिकायत हम को है बरनाला जी से कि पंजाब को तो उन्होंने देखा और पंजाब की तरक्की को वह जानते हैं, हर चीज से अवगत हैं लेकिन देश के और किसी कोने में वह नहीं जाते हैं। कभी कभार जाते हों तो जाते हों। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बुन्देलखंड की ओर खींचना चाहता हूं जहां पर उन्होंने कृषि की तरक्की के लिए एक घास का फार्म खोल रखा है। भारत सरकार ने खाद्यान्न की तरक्की के लिए वहां पर एक घास के फार्म के अलावा और कोई फार्म नहीं खोल रखा है जबकि वहां पर केवल घास ही नहीं होता है। वहां पर अन्न पैदा भी होता है सरप्लस अन्न पैदा होता है। वहां पर ऐसी ऐसी चीज पैदा होती है जिनके लिए रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि अलसी है। तो वहां पर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

बुन्देलखंड में सिंचाई के साधनों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक वहां पर हाई ईल्डिंग वेरायटीज का इस्तेमाल नहीं होगा और सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाए जायेंगे तब तक कृषि की तरक्की नहीं की जा सकती है। इस देश का टोटल कल्टिवेटेड एरिया का 25-30 प्रतिशत सिंचित है जबकि बुन्देलखंड में केवल 10 प्रतिशत एरिया ही सिंचित है। अभी मैं वहीं पर गया तो लोग कह रहे थे कि सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन, वाटर बोर्ड से एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कौन आता है और क्या प्रोग्राम है। इसलिए ऐसे आदेश दिये जाने चाहिए कि कम से कम जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको पहले से अवगत कराया जाना चाहिए और अगर कोई अधिकारी अपना यह सूचना देने का फर्ज अदा नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये। तो अभी तीन-चार दिन हुए, मैं वहां पर गया था, हमारे पास सभापति यादवजी आए और कहा कि बिगहुना ग्राम में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल की ड्रिलिंग हुई है। उनको कुछ पता नहीं था कि उसका कितना डिसचार्ज है कितना नहीं है। मैं ने असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया जोकि उसी गांव में थे तो उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवेल को इसलिए फेल कर रहे हैं कि उसका केवल 15 हजार गैलन प्रति घंटे का डिसचार्ज है जबकि सरकार का नार्म यह है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटा का डिसचार्ज हो तभी उसको सरकार टेक-ओवर करेगी। लेकिन बुन्देलखंड ऐसा एरिया है जहां पर पानी की निकासी कम ही होगी। इस सम्बन्ध में मैंने लिखित रूप में भी प्रार्थना की है और प्रस्ताव भी पास करके भेजा है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटे के डिसचार्ज का जो नार्म है उसको घटा करके बुन्देलखंड के इलाके के लिए 10 हजार गैलन प्रति घंटा रखा जाए। इसके द्वारा वहां पर 100-150 एकड़ भूमि की सिंचाई तो हो सकती है। हमारे यादव जी बता रहे थे कि उस ट्यूबवेल में पानी खूब निकला है, हां उनको यह बात मालूम नहीं थी 30 हजार गैलन का डिसचार्ज है या नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बुन्देलखण्ड के लिए दो बातें विशेष रूप से की जानी चाहिए। बुन्देलखण्ड के 10-15 जिले हैं। वहां पर ट्यूबवेल के लिए 10 हजार गैलन का नार्म निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरे जो वहां का पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है वहां पर आपको स्पेशल रिग्ज भेजने चाहिए जोकि पत्थर को भी काट सकें। मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड के इलाके में कुछ ऐसा काम हुआ है और वहां पर 10-15 हजार गैलन तक पानी निकल आता है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन पर सिंचाई होती है तथा हाई ईल्डिंग वेरायटीज बोई जाती हैं। तो सिंचाई के सम्बन्ध में मेरे यह दो सुझाव हैं।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि जबतक संस्थाओं के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा ऋण नहीं बांटा जायगा तब तक किसान तरक्की नहीं करेगा। आपने 1977-78 में 2360 करोड़ बांटा है जिसमें मध्यकालीन और दीर्घकालीन 780 करोड़ है। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की बड़ी आवश्यकता है। आप जितना सालाना अल्पकालीन ऋण देते हैं उसके अलावा इसको और बढ़ाना चाहिये।

जहां तक नार्थ ईस्टर्न रीजन का सवाल है, मैं अभी जनवरी में गया था मनीपुर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर आप डेम बना रहे हैं जिससे एलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होगी लेकिन खेत सूखे दिखाई दे रहे थे। आप वहां पर सिंचाई के साधन भी बनावें। नागालैंड और मिजोरम में रेवेन्यू रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। वहां लेखपाल भी नहीं है। वहां के मुख्य मंत्री से जब हम मिलने के लिये गये तो हम को बताया गया कि वहां पर लैंड-रिकार्ड्स भी नहीं रखे जाते, क्योंकि सारी जमीन सामूहिक है कम्युनिटी लैंड है। इस में कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है वे अपने आप उस जमीन को आपस में वितरित कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन को उस जमीन पर ऋण नहीं मिलता है। मैं आप से यह अनुरोध करूंगा —नार्थ ईस्टर्न रिजन में जहां व्यक्तिगत टेनेन्सी की व्यवस्था नहीं है, उन के लिये ऋण की व्यवस्था कीजिये, वरना वह एरिया पीछे पड़ जाएगा, उस की तरक्की नहीं हो सकेगी।

अब मैं तिलहन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं—इस में सन्देह नहीं कि हमारे मंत्री जी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर चला जाय और हम विदेशों से तेल का आयात करें —यह बड़े शर्म की बात है। हमारे यहां पेस्ट्स

ज्यादा लगता है—हम देख रहे हैं पिछले तीन सालों से सरसों और लाही नहीं हो रही है, क्योंकि उस में "माहू" लग जाता है। इस के बारे में रिसर्च होनी चाहिये ताकि हम इस से छुटकारा पा सकें।

आप पांच सालों में 17 मिलियन हैक्टेयर में एडीशनल-इर्रिगेशन-फैसिलिटीज देने जा रहे हैं। लेकिन जब 90 या 100 मिलियन हैक्टेयर भूमि आप के पास असिंचित है तो आप को 10 सालों में हर खेत के लिये पानी देने की योजना बनानी चाहिये, 17 मिलियन हैक्टेयर में पानी पहुंचाने से काम चलने वाला नहीं है। आप इस के लिये कहीं से भी लोन लीजिये, वर्ल्ड बैंक से लीजिये—लेकिन 10 सालों में सारी भूमि को सिंचित कर सकें—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। आने-वाले सालों में 125 मिलियन टन अनाज पैदा करने का आप का लक्ष्य है—मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है, आप का लक्ष्य 500 से 600 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करने का होना चाहिये। इस तरह से जहां हमारे किसान तरक्कीशुदा होंगे, वहां हर गांव में 30 परसेन्ट लेंड-लेस लेबर है—उन को भी लाभ पहुंचेगा। मैंने आप की रिपोर्ट को पढ़ा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उस की प्रशंसा की जानी चाहिये, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें लेंड-रिफार्म्ज के बारे में बहुत ही काम्पलेसेन्ट रुख लिया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं हर गांव में जाता हूं वहां के किसान, हरिजन मुझ से अलग से आ कर मिलते हैं। 10 साल से दो-ढाई एकड़ के पट्टे दिये हुए हैं, लेकिन आधा एकड़ पर भी कब्जा करने को नहीं मिला—यह दुर्व्यवस्था है। आप कहते हैं कि 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित कर दी है, यह कागज पर वितरित हुई है, लेकिन उन का कब्जा नहीं मिला है। आप ऐसा कानून बनाइये—जो डी० एम० या तहसीलदार उन को कब्जा न दिला सके, उन को जमीन की बाउण्ड्रीज न बता सके, उस को सस्पेण्ड किया जाए, उन को सजा दी जाए। जब तक आप इतनी सख्ती से काम नहीं लेंगे, यह काम नहीं चलेगा।

आखिर में मैं एक बात फूड कारपोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा हजारों करोड़ रुपया इस में लगा हुआ है, यह भी सही है कि हम को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर गल्ला मिले—लेकिन यह बात भी सही है कि हजारों टन गल्ला गायब हो जाता है, चुपचाप बिक जाता है और पता भी नहीं चलता। इस में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं—एक साल हुआ उन के सम्मेलन में बरनाला साहब गये थे, उन से निवेदन किया गया था कि वहां पर जो बिचौलिये हैं, ठेकेदार हैं, उन को एलिमिनेट कीजिये—लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। एक बांध टूट गया था, मैंने वहां देखा कि ठेकेदार मजदूरों को 3 रुपया दे रहा था, लेकिन कागज पर 5 रुपये के लिये दस्तखत करा रहा था। इस तरह से ये ठेकेदार लूट करते हैं। पिछले तीस सालों में हमारा जितना रुपया इन कामों पर खर्च हुआ है, यदि ठेकेदार बीच में न लूटते तो आधा रुपया खर्च कर के हम उन कामों को करा सकते थे। इस लिये यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये।

आप की रिपोर्ट में एक चीज की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि अब गल्ले का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, तो उस के मार्केटिंग की प्राबलम पैदा होगी। अभी हमारे नाथूसिंह जी कह रहे थे कि हमारा आलू ? दामों में मारा मारा फिर रहा है। इसलिये हमको अभी से इस का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिये और यह काम कोआपरेटिव बेसिज पर होना चाहिये। आज हमारे यहां जो कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज हैं वे डारमेंट हैं, मरी जा रही हैं, उन के पास पैसा नहीं है उन का कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है। कैनाडा में वहां के किसानों ने मिल कर खुद अपना इन्फास्ट्रक्चर तैयार किया है, वहां पर बिचौलिये खत्म हो गये हैं। मुझे एक जगह ले जाया गया और बतलाया गया कि वहां पर जो महल खड़े हुए थे वे पहले बिचौलियों के थे, अब हम ने उन को खत्म कर दिया है। सारा काम किसानों के हाथ में है और अब उन को बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है यहां तक कि उन को 2 डालर प्रति बुशल के हिसाब से एक्स्ट्रा कीमत मिली है। जो गल्ले में प्रोफिट होता है, वे बिचौलिये खा जाते हैं। जो गल्ला सरकार का देते है, उस में वे एक्स्ट्रा प्रोफिट कर लेते हैं। मैं आप को बताऊं कि मैं 150 रुपए क्वीटल मसूर बेचता हूं और उस मसूर को बिचौलिये 250, 300 रुपये क्वीटल बेचते हैं और इतना ज्यादा मुनाफा वे कमा लेते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक कोआपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर आप तैयार कीजिए। उस से यह जो प्राब्लम गल्ले को बेचने की है या प्रोसेस करने की है, वह हल हो जाएगी। बुन्देलखण्ड की ओर मैं फिर से आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट): सभापति महोदया, कृषि मांगों पर जो बोलने के लिए आप ने मुझे अवसर प्रदान किया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि पिछले दो सालों से, नई सरकार के आने के बाद, कुछ तक अच्छी बातें सामने आई हैं और इस सरकार ने 80 फीसदी गांवों में बसे हुए किसानों की ओर ध्यान दिया है और कुछ नई व्यवस्था भी की है जिस के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए, किन्तु हम यह देखते चले आ रहे हैं कि कृषि का और किसानों का जो सीधा सम्पर्क कोआपरेटिव बैंकों और सोसाइटीज से है और उन को सहायता पहुंचाने के लिए, उन की उन्नति कराने के लिए पिछले शासकों द्वारा जो कोआपरेटिव बैंक, सोसाइटियां और पूंजी विकास बैंक आदि संस्थाएं बनाई गई थी, वे हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। कोआपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक, जिस दिन से इन की स्थापना हुई है, में भ्रष्टाचार निरन्तर पिछले दिनों से चला आ रहा है और आज भी वहीं जारी है। अगर कृषि मंत्रालय किसानों की मदद करना चाहता है और उस के यहां से एलाटमेंट होता है कि इतनी किसानों को सब्सीडी दी जाए या

[श्री कचरूलाल हेमराज जैन]

इतना ऋण दिया जाए, तो वह उन तक ठीक से नही पहुचता है । रसोई कोई बनाएगा और खाने का वितरण कोई करेगा । इसी तरह से यहा पर हो रहा है । अलग-अलग विभाग होने के कारण और कृषि विभाग का सीधा सम्पर्क न होने के कारण, जो लाभ ग्रामीण किसानो को मिलने चाहिए, वे उन्हे नही मिल रहे है । जो लोन उन को मिलना चाहिए, वह समय पर उन को नही मिलपा रहा है । अभी नई स्कीमो के अनुसार, ग्रामीण किसानो को पशुपालन के लिए और कई प्रकार के घरेलू उद्योग खोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उस म भी यह होता है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे उन को कहते है कि अगर सरकार 50 फीसदी पैसा माफ करेगी, तो तुम हम को 20 फीसदी दो । अगर 20 फीसदी पैसा देते हो, तो माफ करा देंगे । इस तरह की धांधलेबाजी चल रही है और मैं यह समझता हू कि इस देश के किसानो का सपना पूरा नही कर सकते जब तक कि पूरा नियन्त्रण इस मत्रालय के अन्तर्गत न आ जाए । इसलिए कृषि मत्रालय के साथ उन सब सम्बन्धित विभागो को जोड देना चाहिए नही तो पचास सौ साल तक भी जो हम उन को मदद पहुचाने की कल्पना करते है वह पूरी नही होगी और उस मे आप सक्षम नही होगे ।

हरिजनो और आदिवासियो को भूमि बाटी गई है और उस का कार्यक्रम भी चल रहा है और गावो म रोजगार देने की बाते भी चल रही है । अनाज के बदले काम का कार्यक्रम भी चल रहा है लेकिन हम यह देखते है कि जिन इलाको म भूमि उन लोगो को दस दस और पन्द्रह पन्द्रह साल पहले बाटी जा चुकी है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस का कब्जा भी उन को नही दिलाया गया है और अगर कब्जा भी मिल गया है तो कृषि योग्य वह भूमि नही है और उन म अपने म इतनी शक्ति नही है कि वे उस को कृषि योग्य बना सके । मैं ने लास्ट टाइम भी कृषि मत्रालय की मागो पर बोलते हुए कहा था कि कम से कम उन को कृषि योग्य भूमि दे और इतने सारे जो कार्यक्रम आप के चल रहे है, उन मे आप उन को रोजगार दे और अनाज के बदले काम दे । अगर ऐसा किया गया तो उन की खेती भी दुरूस्त हो जाएगी और हरिजन और आदिवासियो के पास जो भूमि है वह भी खेती करने लायक बन जाएगी । यह नही हो पा रहा है । कृषि मत्रालय ने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से अच्छी क्वालिटी का अनाज ऊचे रेट पर खरीदने के लिए कहा है । मैं दुखी भी हू और मैंने शिकायत भी की है कि जो अनाज उनके द्वारा मडियो से खरीदा जा रहा है वह घटिया किस्म का है और व्यापारियो के साथ उनकी खुली साठगाठ है और आराम से वे घटिया किस्म का माल खरीद रहे है और नियमित रूप से उनका उस मे दो रुपये या चार रुपये क्विटल के हिसाब से बधा हुआ है । इस तरह से जो माल खरीद कर गोडाउन में रखा जा रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है । मैं लिख कर देता हू या कहता हू तो आपके फूड कारपोरेशन के अधिकारी कहते है कि जनता के प्रतिनिधि हमारे काम मे दखल नही दे सकते है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं । मेरे जिले बालाघाट में आप जांच करवा कर देख ले कि वहा घटिया माल खरीद कर गोडाउन में रखा गया है या नही । मैंने आप से शिकायत की थी, आपने अपने शासकीय विभाग से कर्मचारियों को भी भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई । जिस किस्म का माल लेना चाहिये था उससे बहुत ही घटिया किस्म का अनाज लिया जा रहा है और लिया गया है । आप कोई जांच नही करवाते हैं । इस अवस्था मे कैसे आपका विभाग ढग से चल सकता है । पुन मेरा आप से निवेदन है कि आप ने रेट बढाया है तो आप क्वालिटी को भी देखे और इसको भी देखे कि उस क्वालिटी का माल आप के अधिकारी खरीद रहे है जिस क्वालिटी का माल आप चाहते है कि अधिक रेट दे कर खरीदा जाए ।

वायल्ड राइस जिस को कहते है उसकी खरीद के मामले म भी बड़े उद्योग वालो को ही मौका दिया जा रहा है । छोटे उद्योग या छोटे उद्योग चलाने वालो का माल नही लिया जा रहा है । आपके विभाग वाले कहते है कि यह चावल चलने लायक नही है । बड़े उद्योगो से उसकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी कहा जाता है कि इसको खरीदा नही जा सकता है क्योंकि यह चलने लायक नही है । मैं ने आपके विभाग को एक्सैनो मे भर कर उस चावल का सैम्पल भी दिया और उसको दिए हुए डेढ महीना हो गया है लेकिन उसका एनालिसिस रिजल्ट प्राप्त किया गया है या नही, मुझे पता नही है । उसका कोई उत्तर मुझे नही मिला है।

मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपके विभाग ने काफी तरक्की की है सिचाई म भी तरक्की हो रही है । लेकिन पुराने शासको के जमाने से जो रिश्वतखोरी और घूसखोरी इस विभाग म व्याप्त थी वह समाप्त हो गई है और अब इसको खानेवाला नही है इसको मानने के लिए मैं तैयार नही हू । आज भी व्यापारियो से धडल्ले से और खुलेआम रुपया लिया जा रहा है । घटियाकिस्म का अनाज गोडाउन म भरा जा रहा है । यह ठीक है कि अनाज के मामले म अब हम सरप्लस हो गए है और हम को विदेशो को भी अब अनाज भेजना पडेगा । इस वास्ते रेट ज्यादा दे कर हम अच्छी किस्म का अनाज गोडाउन मे रखे इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा ।

मैं यह भी चाहता हू कि हरिजनो आदिवासियो को जो पिछले शासको ने भूमि बाटी है और आप भी बाट रहे वह कृषि योग्य बना कर ही उनको दी जानी चाहिए । जब तक उसको कृषि योग्य बना करके उनको नही दिया जाता है उनका काम नही बन सकता है । उनके पास इतनी ताकत नही है, इतने साधन नही है कि वे उसको कृषि योग्य बना सके । अगर आपने ऐसा किया तो उन गरीबो की मदद होगी और हमारा देश भी उन्नति करेगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के विकास के लिए जो बजट सदन मे पेश है उसके सम्बन्ध में जो जनता पार्टी का घोषणापत्र है, उसको मै आपके सामने रखना चाहता हू । कृषि से आमदनी बहुत कम है और गांव के निजी

व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिये गांव में पूंजी नहीं बनती। इसलिए इसके विकास के लिये जनता पार्टी एक राष्ट्र-व्यापी नीति अपनायेगी और इस क्षेत्र में कम-से-कम 40 प्रतिशत खर्च करेगी। पहला बजट जब जनता पार्टी ने पेश किया तो वह 37.2 प्रतिशत था, दूसरा बजट पेश किया तो वह 40.29 प्रतिशत था और तीसरा बजट 43 प्रतिशत है। लेकिन अपने कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और कृषि राज्य मंत्री श्री मानुप्रताप सिंह के रहते हुए मैं सोचता था कि यह जो 40 प्रतिशत का प्रस्ताव आपने आज तक पूरा किया, यह देखने में 43 प्रतिशत लगता है। देखने में यह प्रस्ताव साधु है, लेकिन इसमें कुटिलता भरी हुई है। अगर इस कुटिलता के जाल-बट्टे को माननीय मंत्री जी काट सकें तो इस देश पर और देश की खेती के उत्थान पर बड़ी कृपा होगी। इस पूरे के पूरे बजट में जो 43 प्रतिशत का है, इसमें जो फर्टिलाइजर पैदा होता है और उसमें जो फैक्टरियों पर पैसा खर्च होता है, वह भी कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि फैमिली वैलफेयर पर जो पैसा खर्च होता है, उसका 75 प्रतिशत भी इसी ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर जोड़ दिया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री पर जो पैसा खर्च होता है, वह भी इसी बजट में जोड़ दिया गया है। सबसे मजेदार और नोट करने की बात यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो 15 लाख रुपये तक की फैक्टरी खड़ी करेगा, वह भी लघु उद्योग धंधे में आता है। आज गांव के किस आदमी की हैसियत है कि 15 लाख रुपये का उद्योग धंधा वह खड़ा कर सके? लेकिन उस मद को भी इसमें जोड़ दिया गया है।

जो आर्थिक उन्नयन की पूंजी है, जिसको कहा जाता है कि हमने क्रांतिकारी तबदीली की भूख जगाई है, हमने गांव की ओर जाने का महाप्रयाण किया है, जरा उसकी तरफ भी ध्यान दें।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिये रखे गये कुल पूंजी विनियोग के साधनों का कम से कम 40 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित किया जाना सरकार का अति आवश्यक लक्ष्य होना चाहिये। इन पूंजीगत साधनों में पक्की सड़कों, परिवहन और शिक्षा पर लगायी गई राशि शामिल नहीं होगी।

लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि काम के बदले जो अनाज योजना आज चल रही है और उसमें जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। यदि सब को मिलाकर देखेंगे तो और भी मजे की बात है कि चीनी, शुगरकेन, जूट और काटन की जो इंडस्ट्री है, उनको भी कृषि के अन्तर्गत जोड़ा गया है। यदि फर्टिलाइजर पैदा होकर खेत में इस्तेमाल हो, इसलिये उसको खेती में जोड़ा जाये, तो इन फैक्टरियों में जो चीजें पैदा होती हैं, जो कि खेती में इस्तेमाल नहीं होती हैं, उनको इंडस्ट्री में क्यों नहीं जोड़ा गया। दोनों तरफ कुशाग्र तर्क चलते हैं। एक मुंह में जिसकी दो जीभ होती हैं, वह जानवर बहुत ही खतरनाक होता है। यह पूरे का पूरा शुगर केन और जूट जो पैदा हो, उसको भी इसमें जोड़ दें और फर्टिलाइजर भी इसमें जोड़ दें, यह ठीक नहीं। अगर इन सारी मदों को इसमें से निकाल दें, तो मैं बड़े अदब के साथ कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली बार जो 31, कुछ और अब की बार 34, कुछ खर्च करने जा रहे हैं, तो 40 प्रतिशत की बात अधूरी रह जायेगी। आगे हालत इतनी खराब होगी।

कभी कभी शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि जनता पार्टी ने बड़ी शान के साथ कहा था कि हम गांव की ओर जा रहे हैं, महाप्रयाण कर रहे हैं और जब हमारे मंत्री और हमारी जनता सरकार के लोग कहते हैं तो गालिब का एक शेर याद आ जाता है :—

आ वफा ना-आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला,
बेवफा कहते हैं तुझको, और शर्माता हूं मैं।

बेवफा श्रीमान को कहते हैं, लेकिन शर्माना हमें पड़ता है। लेकिन शर्माकर भी काम करते चले जा रहे हैं। विचित्र स्थिति है। सारे के सारे कृषि जीवन में आज एक विष घुल रहा है, जरासा इन सब चीजों की तरफ नजर डालें।

14 hrs.

इस देश में चीनी का दाम तय होता है क्योंकि वह फैक्टरी में बनती है लेकिन गन्ने का दाम तय नहीं होता कि इसका लाभप्रद मूल्य क्या है, लागत मूल्य और समता मूल्य क्या है। आज तक इन तीनों मूल्यों—लागत मूल्य, लाभप्रद मूल्य, समता मूल्य—के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। चीनी का दाम तय होता है, क्योंकि उसको फैक्टरी और इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है—उसका लाभ प्राईवेट सैक्टर में उद्योगपतियों को मिलता है और पब्लिक सैक्टर में ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है। पूंजीपतियों, ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के इस त्रिगुट से गन्ने का दाम तय नहीं होता है, लेकिन चीनी का दाम तय होता है। यही हालत रूई की है—रूई का दाम तय नहीं होता है मगर कपड़े का दाम तय होता है। आज ही इस सदन में इस बारे में बहस चल रही थी, जिसमें उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीस, से सवाल किये गये। श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि जब पिछले साल रूई का दाम 355 रुपये प्रति क्विंटल था, तो कपड़े का दाम 5 रुपये प्रति मीटर था, लेकिन इस साल जब रूई का दाम 260 रुपये प्रति क्विंटल है, तो कपड़ का दाम 11 रुपये प्रति मीटर है। जब रूई का दाम घटे, तो कपड़े का दाम बढ़े, यह व्यवस्था कैसे चलेगी? इस व्यवस्था के बारे में हमें और आपको सोचना होगा।

14.02 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*].

इन चीजो को पैदा करने मे चार तरह के पानी इस्तेमाल होते हैं। कबीर ने कहा है :

माया महाठगनि मैं जानी,

केशव की कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी,

पंडा की मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी।

पानी का बड़ा महत्व है। लेकिन सरकार गेहू और अनाज पैदा करने के लिए जो पानी बेचती है, उस पानी के चार दाम है। राजकीय नलकूप से जो पानी मिलता है, उसके अलग दाम हैं। नहर से मिलने वाले पानी के अलग दाम हैं। बाध मे जो नहर निकलती है, उसके पानी के अलग दाम है। डाल सिचाई योजना, लिफ्ट इरिगेशन, के पानी के अलग दाम है। पाचवा पानी वह है, जो निजी नलकूप से निकाला जाता है, उस के दाम अलग हैं। लेकिन जब गेहू बाजार मे आयेगा, तो उसका एक ही दाम है। ऐसा नही है कि जो चावल और गेहू, 60 रुपये प्रति एकड के पानी से पैदा किया जाये, उस का दाम अधिक है और 15 रुपये प्रति एकड़ वाले पानी से पैदा किये गये चावल और गेहू का दाम कम है।

मेरे एक सवाल के जवाब मे राज्य मत्री ने बहुत पहले कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सभी पानियो के दाम एक हो जाये। इस बात को साल, डेढ साल हो गया है, आज तक उस योजना पर अमल क्यो नही किया गया ? पानी के दाम क्यो नही एक किये गये, जबकि पानी से उत्पादित चीजो के दाम एक है ?

हमारे देश मे 35 करोड एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। उसमे से 10, 11 एकड जमीन ऐसी है जहा एशार्ड इरिगेशन है और जहा उर्वरक का भी इस्तेमाल होता है। अगर फी-एकड डेढ टन भी मान ले तो 11 एकड जमीन से लगभग 16½ करोड टन का उत्पादन होता है। बाकी 25 करोड एकड जमीन बिना सिचाई की है, जिसे आसमान सहारे, आकाश आसरे या भगवान आसरे कहते है। अगर वहा का उत्पादन आध टन फी एकड़ मान लिया जाये, तो वहा 12 करोड टन का उत्पादन होता है। इस प्रकार हमारे देश मे कुल उत्पादन 28 करोड टन का हुआ। लेकिन सरकार की ओर से बताया जाता है कि पिछले साल 12.60 करोड टन का रिकार्ड उत्पादन था और अब 15 करोड टन होने की आशा है।

सवाल यह है कि ये आकड़े बनाने वाले कौन लोग है, किन एजेन्सियो द्वारा ये आकड़े बनाये जाते है ? इस देश में 60 करोड़ लोग रहते है। जेल मैनुअल के अनुसार एक आदमी को 750 ग्राम अनाज मिलना चाहिए। इस हिसाब से 60 करोड लोगो के लिए 16.20 करोड़ टन अनाज बैठता है, लेकिन 12 करोड़ टन उत्पादन बताया जाता है। इस स्थिति मे कहना पड़ता है कि या तो ये आकड़े गलत है और या हिन्दुस्तान के आधे आदमी आज भी भूखे रह रहे है। लेकिन मेरी समझ मे ये आकडे गलत है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। इस सरकार की निर्यात की नीति के कारण आज इस देश का किसान रोज बरोज दरिद्र हो रहा है। हम गांवो की ओर महाप्रयाण करने की बात करते है, नगर शहर की अट्टालिकाओ को ऊचा करने का काम कर रहे है। 1974 मे अनाज का निर्यात हुआ--48029 हजार टन, 1975 में 24496 हजार टन, 1976 मे 18250 हजार टन 1977 मे 18036 हजार टन--इस का अर्थ है कि निरन्तर घटता गया।

आप चीनी को लीजिये--1974 मे, 443 01 हजार टन का निर्यात हुआ, 1975 मे 996 01 हजार टन, 1976 में 843 07 हजार टन निर्यात हुई, लेकिन 1977 मे 251 08 हजार टन निर्यात हुई--इस का अर्थ है कि 1977 मे आध मे भी कम चीनी निर्यात हुई।

1973-74 मे गन्ने का मूल्य 10 26 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किया गया, 1974-75 मे 10 40 रु० प्रति क्विंटल, 1975-76 मे 11 रु० प्रति क्विंटल, 1976-77 मे 10 80 रु० प्रति क्विंटल और 1977-78 मे 10 80 रु० प्रति क्विंटल . ..

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) यह मूल्य कहा है ? यह तो सिर्फ कागज पर है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह यह बात ठीक है--10.80 रु० प्रति क्विंटल कागज पर है जब कि 4 से 5 रुपये प्रति क्विंटल मे गन्ना बिका या किसानो ने उस को दियासलाई लगा कर जला दिया। आप देखिये एक तरफ किसान की हालत यह है कि गन्ना उस को जलाना पड रहा है नई मन्दे भाव पर बेचनी पड रही है दूसरी तरफ आप जरा चावल के थोक सूचकांक को देखिये। यह हमारी अपनी सरकार है, यह सरकार आर्थिक नीति के हिसाब से समता मूल्य चाहती है, पैरिटी-प्राइस चाहती है, लेकिन जरा चीजो के दामो को देखिये। 1971 मे चावल का थोक सूचांक 103 3 था, 1974 में 174 7 था, 1975 मे 188 2 था, 1976 मे 154 9 था, लेकिन 1977 मे 163.6 हो गया। इस का अर्थ है कि 1975 मे 188 2 था लेकिन 1977 मे 163.6 पर चला गया, यानी 6-7 परसेन्ट

लगभग माइनस हो गया । यही हालत गेहूं की रही है ।

अब मैं आप का ध्यान खेती में इस्तेमाल होनेवाली चीजों के मूल्यों की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें खेती में पैदा होती हैं उन के मूल्य तो घटते जा रहे हैं लेकिन जो चीजें खेती में इस्तेमाल होनेवाली हैं-- उन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कृषि व्यवस्था रीढ़ से जुड़ी हुई है, आज हमारी रीढ़ टूट रही है, एक्चर होने जा रही है, इन्सान मरने जा रहा है । आज इन्सान खेती नहीं कर रहा है, आप उस को डांगर कहें, जानवर कहें, आज इन्सान के रूप में जानवर खेती में लगा हुआ है । मैं ने पिछले साल भी कहा था कि कुछ लोग कृषि को "कृषि मत्स्य जीवन" समझते हैं लेकिन मैं इस को 'कृषि मर्खन्न जीवन' समझता हूं । आज कृषि में सब लोग नंगे हुए हैं जो इतना अधिक परिश्रम करते हैं जो दोपहर को इतनी सख्त धूप में अपना हड्डियां को जलाते हैं लेकिन फिर भी उन को 1975 के मुकाबले में कम दाम मिलते हैं और दूसरी तरफ आप यह देखिये कि खेतों में काम आने वाली जो दूसरी चीजें हैं उन के दाम कितने बढ़ गये हैं । आप बैटरी को ही ले लीजिए । बैटरी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होती है और बैटरी का दाम कितना हो गया है । बैटरी में जो लीड और आक्साइड लगता है, उस के दाम एक वर्ष में चार दफा बढ़े हैं । सितम्बर 1978 में उस के दाम 8600 रुपये पर मैट्रिक टन थे और अक्तूबर 1978 में वे 9,100 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये । उस के बाद जनवरी में वे बढ़ कर 11000 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये और फिर 1 मार्च 1979 को वे बढ़ कर 14,100 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये । इस वर्ष के अन्दर दुगने दाम हो गये । 1971 में जो ट्रैक्टर 29 हजार रुपये का मिलता था, उस के बाद बढ़ कर 60 हजार, 61 हजार और 62 हजार रुपये हो गये यानी दुगने और तीन गुने उस के दाम हो गये ।

अब आप डीजल को देखिए । 1971 में जहां उस का इन्डेक्स नम्बर 104 5 था, वहां 1977 में वह बढ़ कर 213 9 हो गया । 1971 में 104 5 और 1977 में 213 9 और डीजल का मौजूदा दाम जो बढ़ गया है, उस को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो यह 213 9 बढ़ कर 240 हो जाएगा । आप ने यह भी देखा कि जिस गन्ने से चीनी बनती है, चीनी के दाम तो बढ़ गये लेकिन गन्ने का दाम नहीं बढ़ा बल्कि घटा है । कहीं कुछ बात नहीं हुई और चीनी का दाम 30 प्रतिशत बढ़ गया । पहले उस का दाम 2 20 रुपये किलो था और अब यह बढ़ कर 4 रुपये और 3 20 रुपये प्रति किलो हो गया । (व्यवधान) साढ़े चार रुपये की याद करते हैं, तो फिर इन्दिरा गांधी की तारीफ करनी होगी । हम तो आप की तारीफ करना चाहते हैं । 2 15 रुपये प्रति किलो चीनी आप भी देते थे । इसी तरह का बिजली का इन्डेक्स नम्बर आप देखें । 1971 में यह 101 9 था और 1977 में यह बढ़ कर 171 6 हो गया है । ट्रैक्टर का 1971 में 109 6 था और 1977 में यह बढ़ कर 203 हो गया है । फिर कृषि फावड़े का आप देखें, 1971 में जहां इस का इन्डेक्स नम्बर 113 6 था, 1977 में वह बढ़ कर 216 9 हो गया और अभी बीजू पटनायक साहब ने जो दाम बढ़ाए हैं, जो 265 रुपये प्रति क्वीटल हमें छड़ मिलती थी, उन से बने हुए फावड़े के दाम 360 रु० प्रति क्वीटल हो जाएंगे । इसी तरह से आप यह देखें कि पिन्ड लोहा, जिस का इन्डेक्स नम्बर 1971 में 100 था, वह 1977 में बढ़ कर 181 6 हो गया और फर्टिलाइजर्स का जो 1971 में 100 3 था वह बढ़ कर 186 5 हो गया, आप की महान कृपा के बावजूद । इस तरह से आप देखें कि सारी चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, खेती में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उन के दाम घोड़े की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और किसान जो इतना परिश्रम करता है और किसान जो चीजों को पैदा करता है, उस की उन चीजों के दाम अगर चींटी की रफ्तार से भी बढ़ते तो हम आप को मुबारकबाद देते लेकिन मुबारकबाद तो अब भी देंगे क्योंकि दाम माइनस की तरफ जा रहे हैं । आज किसानों को गोदामों की तरफ जाना पड़ता है, गोदाम किसान की तरफ नहीं जाते हैं । व्यवस्था यह होनी चाहिए कि उन के लिए गोदामों वहीं पर हों और जो उन की फसल है, उस का इन्शायरेंश हो । इस के साथ साथ जैसे गोदामों में रखे हुए माल के ऊपर शहरों में कैश-क्रेडिट मिलता है, एडवान्स मिलता है, उसी तरह से जो माल किसान रखे हों उन को भी एडवान्स मिलना चाहिए । अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो किसान हमेशा लुटता ही रहेगा । जब उस को पैसे की जरूरत होती है, तो उस को अपना माल बेचना ही पड़ता है और डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस से किसान को ऐसा न करना पड़े ।

काम के बदले अनाज योजना का जिक्र करते हुए, अन्त में मैं एक बात और आप की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं । 1 लाख 16 हजार मेट्रिक टन आन्ध्र प्रदेश में पिछले साल गेहूं आवंटित किया गया लेकिन कुल खर्च हुआ 23987 मेट्रिक टन और इसी तरह से हर प्रदेश में हुआ कि जितना आवंटित हुआ काम के बदले अनाज योजना में उस की एक-चौथाई भी खर्च नहीं हुआ । इस का कारण क्या है । इस के कारणों में जाया जाए, तो पता चलेगा कि जो गेहूं या चावल इस योजना के अधीन दिया गया, उस में से 50 से ले कर 75 प्रतिशत तक सड़ा हुआ था या खराब था । इस कारण से यह योजना ठीक से नहीं चल पाई और इस तरफ आप को ध्यान देना होगा ।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल 112 50 रुपये का समर्थन मूल्य आपने दिया था । इस साल के लिए अभी कुछ नहीं

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

किया है लेकिन आज गेहू बाजार में 80, 90 रुपया पर क्वीटल बिक रहा है और जहां समर्थन मल्य पर खरीददारी होती है, वहा बनिये की एजेन्सी रहती है या बिचौलिये की एजेन्सी रहती है और उन के जरिये मे गेहू लिया जाता है और वे ज्यादा मुनाफा कमा लेते है ।

एक माननीय सदस्य बोरे भी नही है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह . बोरो का तो इन्तजाम कर लेगे । अन्त मे मै इतना ही कहना चाहता हू कि कृषि का अगर उद्योग की तरफ माना जाए, तभी जा कर कृषि का विकास हो सकता है । इस मे जो शासन की कमिया है, उन को छिपाने से कोई फायदा नही होगा । इस सम्बन्ध मे मै एक शेर कहना चाहूगा ।

"इन्सान आज भी है गुलामी मे सरमगू
यह बात और है कि तरीके बदल गये ।।

केवल तरीके ही बदले है, और कुछ नही बदला ।

इन शब्दो के साथ मै यह कह कर समाप्त करता हू कि इतने बुद्धिमान, योग्य, सुशिक्षित सस्कारवा लोगो के मत्रालय मे रहते हुए भी अगर गावो का विकास नही हो सका, तो मै ऐसा ही नही मानता कि आगे यह हो सकेगा । यह श्रेय इन लोगो का जाये और श्रेय का लेने के लिए जहा भी लडना पडे, हमें लडना चाहिए । इन शब्दो के साथ मै कृषि मत्रालय की मागो का समर्थन करता हू ।

SHRI VENUGOPAL GOUNDER (Wandiwash): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I would be failing in my duty if I do not congratulate the Ministry for having raised the production of foodgrains to the extent of 125 million tonnes. Though we are proud of raising the prouction to that level, yet what about the man who has achieved this target, who has produced 125 million tonnes of foodgrains? What steps we have taken to take care of his interest? He is not expected any Bharat Ratna or any such thing from you. He wants food, cloth and a shed. We will be failing in our duty if we do not provide him with food, cloth and shelter. We are talking too much that we have achieved our target. But one thing the Minister should not forget. The monsoon was very very favourable to them and because of that, they have achieved this target. So, they should not be complacent about it. Otherwise, the situation would be very difficult. The Ministry should bear in mind the fact that if the monsoon fails what would be the position? And keeping that in mind, they should plan their strategy.

When the Ministry of Agriculture ask us to produce more, they should find markets for the produce in foreign markets. Otherwise, the person who produces will suffer more because the law of supply and demand will have greater force. Unfortunately, in Tamil Nadu and some other States the sugar cane growers have left their land fallow because a proper price is not paid to them. The agriculturists say that they are not getting their dues from the mills and the mill owners say that they are not able to get a proper market because there is no demand for sugar. The result is that the farmers are suffering a lot. The Ministry should come forward to help those farmers in such cases where the demand is less

Of course, organisations like the Food Corporation of India and the Civil Supplies Corporation are purchasing it. But they should not be guided by the rules about grades and so on Now what happens is that when they are purchasing from the farmers, they are guided by the rules about grade and so on. But when they are put to loss, they give some other reason for the loss I would say that the Ministry of Agriculture need not be strictly guided by the rules; at least in the matter of purchasing foodgrains let them be magnanimous. Let them find ways and means to purchase all the foodgrains that the farmers offer for sale Let them not make the farmer go back with his produce on the ground that it is not up to the quality or grade.

Coming to the question of marketing, a person who produces industrial goods fixes the price for his product while a person who produces foodgrains is not in a position to fix the price for his own produces. We should create conditions where a farmer can fix his price for what he produces. Now the price is fixed by a middleman, who

knows nothing about farming. As far as possible, we should try to eliminate the middleman so that we can do something for agriculture.

The FCI is functioning only in big cities like Madras. It has no offices at the taluka or zilla parishad level. There should be branch offices at every taluka so that the farmers can take advantage of it for the disposal of their produce.

Paddy can be cultivated only through irrigation whereas wheat can be cultivated with or without irrigation. The support price fixed for wheat is high, whereas that for rice is very low. There is a lot of discrimination here. There is a demand that the cultivation cost of paddy should be taken into consideration, as it is more on account of irrigation, whereas it is less for wheat because it can be cultivated without irrigation. So I am at a loss to understand why wheat is fixed a higher price in comparison with paddy. This discrimination should be removed and both wheat and paddy should be given the same price.

Now there are Commodity Boards to look after the interests of those commodities like the coconut Board, Coffee Board, Tea Board, Cashewnut Board and so on. In the same way, there should be boards for groundnut, paddy etc. consisting of real farmers, and not those who know about farming only from books. The Board should consist of people who know the practical difficulties and it should look after the interests of the farmers and make necessary recommendations to the Government.

The Agricultural Prices Commission was appointed in 1965. From then onwards there was no further Commission. Of course, it was revived or reintroduced in a different form. So, I suggest that a Price Commission may be appointed so that the cost of the paddy, groundnut, chillies etc. is taken into consideration and a support price is given to these crops.

Another point is that wheat was purchased and it was given to the public at subsidised prices. In these same manner the paddy may be purchased at a higher cost and it may be given to the public at a subsidised rate. Suppose, the prices of industrial goods have increased, nobody bothers. For example, if the price of cloth has gone up more than 20 or 30 times, nobody bothers, not even the Government bothers. But they should bother very much if the prices of foodgrains have increased. People will be interested to see that the prices are reduced. But the Government should take into consideration the fact as to how far the farmers could be benefited by the increase in the price. If there is so much increase then the Government should come forward to subsidise these things.

There is one more important thing which I would like to mention here. I would like the Minister of Agriculture to allot more funds for irrigation because we have got a vast source of water. Particulary, we have got perennial rivers in the North. There is a lot of dispute regarding the sharing of river waters. Each State is quarreling with the other on who should be benefited. Ultimately neither is benefited, the entire water goes to the sea. So, the inter-State waters should at least be nationalised or the Minister should take care to see that the disputes are settled immeditely.

There is a big and ambitious plan for connecting the Ganga and Cauvery rivers, for which the World Bank has agreed to give assistance and the experts have also pointed out that it is feasible. If the two rivers are connected, definitely the farmers will be benefited. Not only that. The employment possibilities are also greater. You can give employment to both educated and uneducated agriculturists. There is a lot of potentiality for employment. In respect of agriculture, definitely there is a chance to increase all such potentialities. So, kindly take interest and consider whether it is possible to unite the Ganga and the Cauvery. You take

[Shri C. Venugopal]

the water to the South so that the southern people will also be benefited. Then not only the South but the entire North also will be benefited.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Now, there is agrarian unrest throughout the country. If the problems of agriculturists are not solved, and if we fail to give proper attention to agriculture, then we will be failing in our duty.

With these words, I conclude.

श्री भारत भूषण (नैनीताल) सभापति महोदय, आज हम कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस वातावरण में हम आज रह रहे हैं, उसमें मैं इस मंत्रालय के मंत्रियों के भाग्य की सराहना करना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि सभी मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाली चीजों का अभाव है--देश में खनिज तेल, कोयला, बिजली और लोहा नहीं मिलता है, सब चीजों का अभाव है--, मगर कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्नों की बहुतायत है। वे सब जगह मिलते हैं, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।

लेकिन इसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाये, किसको बधाई दी जाये? प्रकृति को, जिसमें समय पर वर्षा हुई, या उस किसान को जो भूखा रह कर भी, अभाव में रह कर भी, जमीन को जोतता है?

वह हड़ताल नहीं करता है, अन्न पैदा करता है और उस को उपज जो भी भाव मिले बेचना पड़ता है। इस के लिये मैं किस को धन्यवाद दूं--किसान को धन्यवाद दूं या प्रकृति को धन्यवाद दूं, लेकिन इस मंत्रालय को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है। किसान के द्वारा ज्यादा पैदा करने के बाद, देश में खाद्यान्नों की बहुतायत के बाद भी आज किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यदि आप कारखानों में देखें, वहां जब उत्पादन बढ़ता है, उन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है।

मैनीफेस्टो की बात मैं इस लिये नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे मंत्री जी का सम्बन्ध जनता पार्टी के मैनीफेस्टो से नहीं रहा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं--किसान होने के नाते उन्होंने भी अपने किसानों से वायदा किया था कि किसान को बोआई के दिनों में मूल्य की घोषणा कर देंगे। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के तौर-तरीकों के बारे में अब तक चिल्ला रहे थे कि वह गलत है, उस को हम ठीक करेंगे---लेकिन क्या हो रहा है? आज गेहूं कट रहा है---मंत्री जी यहां बैठे हैं, आज तक वे किसानों को उसकी कीमत नहीं बतला सके हैं कि वह क्या भाव बिकेगा। आज किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली तमाम चीजों की सही लागत निकाली जानी चाहिये और उस पर उस को उचित नफा दिया जाना चाहिये, ताकि वह जीवित रह सके। लेकिन होता क्या है--शहरों में रहने वाली 20 प्रतिशत आबादी की जेब को देखा जा रहा है, उस का बजट क्या एलाउ करता है, वह किस भाव पर खरीद सकता है--उस को दृष्टि में रख कर हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं ---यदि मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा तो कारखाने का उत्पादन गिर जाएगा, वह हड़ताल करेगा, शहरों में रहने वालों की बिल्डिंगों को तोड़ेगा, मंत्रियों के घरों पर धरना देगा, ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा करेगा, ब्यूरोक्रेट्स आराम से नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन बेचारा किसान क्या करेगा--किसान यह सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिये किसान के बारे में उन को कोई चिन्ता नहीं है। किसान खेती छोड़कर हड़ताल नहीं कर सकता, वरना वह क्या खायेगा? वह प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति उस को तनख्वाह का एरियर नहीं दिला सकती। यदि उस ने हड़ताल कर दी और बोआई का मौसम निकल गया, तो वह खाने को कहां से लायेगा। इसलिये, सभापति महोदय, इस नौकरशाही को, इस अफसरशाही को, पूरा अधिकार है कि उस का शोषण करे और हमारे मंत्री जी उन्हीं अधिकारीवर्ग द्वारा दी गई रिपोर्टों का समर्थन और हिमायत करते हैं।

मुझे आश्चर्य हुआ---एक दिन मैं मंत्री जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा---मैंने भी बहुत हड़तालें की हैं, नारे लगाये हैं। इन सब बातों को मैं जानता हूं--क्योंकि हम लोग अपोजीशन में रह चुके हैं। इसलिये अब जब कि मैं मंत्री बना हूं तो हड़तालों और नारों से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी मुर्दाबाद कहा था, हम ने भी धरने दिये थे इसलिये अब यह हमारे दरवाजे पर भी हो जाय, तो इस से क्या अन्तर पड़ता है।

किसान की आज जो स्थिति है---अनेक वक्ता उसके बारे में बतला चुके हैं---आज पैदावार से लेकर उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु---चाहे खेती में लगने वाली वस्तु हो या उस के शरीर पर लगने वाली वस्तु हो---सब महंगी होती जा रही है, लेकिन उस के द्वारा जो वस्तुयें पैदा होती हैं, वह यदि अधिक पैदा कर दे तो बाजार में बिखरी बिखरी फिरती है, उन की कोई कीमत नहीं होती, कोई उन का खरीदार नहीं होता। आज आलू की यही हालत है, पिछले साल गन्ने की यही हालत थी। हमारे मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आप को एक्सपोर्ट करने की छूट है। किसान को कहते हैं कि तुम एक्सपोर्ट कर दो। इसका यही मतलब हुआ कि कमरे के सारे दरवाजे बन्द कर दिये और ताली अपनी जेब में रख ली, फिर कहते हैं कि तुम पर कोई बन्धन नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। विदेशों को माल तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक सरकार दूसरी सरकार से बात कर के निर्यात का प्रबन्ध नहीं करती। किसान स्वयं बाहर नहीं ले जा सकता, यहां पर बिक्री की व्यवस्था नहीं है। कृषि मंत्रालय अगर किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन ठीक से नहीं करा सकता है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिला सकता है तो उसने किसान की

बहबूदी की जो जिम्मेदारी अपने कंधो पर ली हुई है उसका वह निर्वाह नही कर सकता है और बधाई का पात्र नही हो सकता है ।

कृषि मंत्रालय के साथ सिंचाई जुड़ी हुई है । यह सराहनीय चीज है कि इस को कृषि मंत्रालय के साथ ही रहना चाहिये । सिंचाई के मामले मे पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार ने कम समय मे अधिक सिंचाई की सुविधायें जुटाई हैं और आगे के लिए भी उसकी बड़ी भारी योजना है । किन्तु काम किस प्रकार होता है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं । इस सदन के अन्दर पहली बार बोलते हुए भी मैंने इसकी चर्चा की थी । आज दो वर्ष बाद फिर से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं । मेरे क्षेत्र मे 1974 मे शिवगानी डैम बनाने के लिए उसका शिलान्यास कर दिया गया है, योजना आयोग से वह एप्रूव हो गया है । 62 करोड़ उस पर लागत आएगी । 1974, 1975 और 1976 निकल गए। 1977 मे निर्वाचन आए । मैं निर्वाचित हो कर आया । तब इस डैम का कुछ पता नही था । एक करोड़ रुपया हर साल उसके लिए रखा जाता था जो उसके डिविजन पर खर्च होता था, व्यवस्था पर खर्च होता था । रिवर बैड तक जाने के लिए सड़कें बना देते थे, छोटी छोटी टम्पोरेरी पुलिया बना देते थे और बाढ़ आती थी तो सब नष्ट हो जाता था, सब बह जाता था । अगले साल फिर बना देते थे । डिपार्टमैंट ठीक चल रहा है जो उस में काम करते हैं उनकी नौकरी पक्की है लेकिन डैम क्यों नहीं निकल कर आ रहा, किसान को खेत के वास्ते पानी क्यो नही मिल रहा है, परेशानी क्या है, जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि डिजाइन अभी एप्रूव नही हुआ है, एक नया डिजाइन कोई अमरीका मे बना है उस प्रकार का बनाया जाए तो 62 करोड़ खर्च आएगा और अगर अपने परम्परागत डिजाइन के मुताबिक बनाया जाए तो सत्तर करोड़ खर्च आएगा । यह जो खर्चा है यह तब होने की बात थी । जो बड़े इंजीनियर थे वे कहते थे कि खतरा मोल लेना नही चाहिये, आठ करोड़ कम खर्च करके अगर बना दिया गया और अगर कल को टूट गया तो क्या हो । भारतीय इंजीनियरो की या तो बुद्धि पर विश्वास नही या ईमानदारी पर विश्वास नही । ईमानदारी पर विश्वास कैसे हो क्योंकि चोरियां हो रही है, बेईमानी हो रही है । इसका नतीजा यह हुआ कि आज चार साल तक डैम नही बना और बनना शुरू नही हुआ । फीडर चैनल्ज बन गई है, बरेज का प्रबन्ध हो गया है लेकिन डैम कही नही है, चार साल हो गए है डिजाइन ही नही तैयार हुआ है । 62 करोड़ की जगह अब अस्सी करोड़ में भी नही बनेगा क्योंकि इस बीच कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है । कल को एक अरब खर्च होगा । इस तरह से आप जो रुपया खर्च कर रहे है वह किसान तक पहुंचेगा, उसका लाभ उस तक पहुंचेगा इसका विश्वास नहीं होता है । यह कागजों मे ही पड़ा रह जाएगा जैसे पिछले पांच साल से यह डैम पड़ा हुआ है । यही हाल सब जगह है ।

कृषि मंत्रालय के अन्दर एक खाद्य विभाग आता है । उसने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की थी । किसान को उसकी फसल मार्किट मे आने पर जो परेशानी होती है, उसके दाम जो गिर जाते है, उसके पास होल्डिंग कैपेसेटी जो नही होती है, अपने माल को रोके रखने की शक्ति नही होती है, उसको होल्डिंग कैपेसेटी प्रदान करने के लिये बैंको से वह जो माल इन गोडाउज में रखेगा उसके अगेंस्ट कर्जा दिलाने के लिये वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की गई थी । इस तरह से जब भाव ठीक होंगे तब वह बेच देगा इस वास्ते इन गोडाउज की व्यवस्था की गई थी । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने पिछले वर्षों मे कितने परसेंट माल एफ० सी० आई० का अपने गोदामो में रखा है और कितने परसेंट किसानो का रखा है । यह कारपोरेशन तो आपका कमाऊ पूत बन गया है और इसने चार करोड़ कमा कर भी आपको दे दिया है लेकिन कितने प्रतिशत माल किसानो का रखा है अपने गोडाउज मे इसके आंकड़े तो आप जरा देखें । एफ०सी०आई० के लाभ के लिए वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का क्या निर्माण हुआ था ? क्या किसान के लाभ के लिए नही हुआ था ? अगर किसान का गल्ला नही रखेंगे उसको अगर अग्रिम राशि नही दिलायेंगे और एफ० सी० आई० को दे कर उन मे रुपया कमाया जाएगा और ईस इस तरह से बना जाएगा और चार करोड़ का लाभ दिखाया जाएगा तो क्या नही इन गोडाउज को एफ० सी० आई० को ही ट्रांस्फर कर दिया जाता है ? तब इस कारपोरेशन की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नही है । एफ०सी०आई० ने एक करोड़ बीस लाख टन का व्यापार किया उसके पास सत्तर हजार कर्मचारियों की फौज है, पच्चीस हजार मजदूर उस में काम करते है इन मजदूरों का शोषण करने के लिए उन्होंने ठेकेदार खड़े कर रखे है और ठेकेदार और कर्मचारी मिल कर आप से अनुदान लेते चले जा रहे है । गत वर्ष 570 करोड़ का अनुदान आपने दिया था । क्या यह अनुदान उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये दिया था ? आप देखें कि उसके खरीद मूल्य और इश्यू मूल्य मे 18 रुपये का अन्तर होता है यानी 180 रुपये टन का अन्तर होता है और उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते वह 250 रुपये प्रति टन हो जाता है । इतना डिफ्रेंस होने के बावजूद एफ०सी०आई० अपना खर्चा नही चला सकती है । उसने पिछले साल 456 करोड़ की मांग की थी जो बढ़कर 570 करोड़ हो गया यानी सवाया हो गया । क्या उसका व्यापार घटने वाला है कि इस साल 560 करोड़ की मांग की जा रही है ? बाद मे चल कर इसको बढ़ाया जाएगा और मैं समझता हूं कि इसको सात सौ करोड़ कर दिया जाएगा । देश में एक करोड़ बीस लाख आपके अपने आंकड़ो के हिसाब से लोग बेरोजगार है । अब इनको अगर यह रुपया दिया जाए तो हर एक को साठ रुपए महीना दिया जा सकता है । यह विभाग कितना भ्रष्ट और इनएफिशेंट है यह आप जानते ही है । इसके द्वारा खरीदे गए चावल का नमूना आपके पास भी पहुंचा चुका है । रायकोट गोदाम मे यह गल्ला रखा हुआ है । इस में दस प्रतिशत भी चावल नही है । किसान छान छान कर एफ०सी०आई० का गल्ला देते है गेहूं ला कर देते है तीन तीन छलनियां लगाई जाती हैं लेकिन जब वह कंज्यूमर के पास आता है तो उसके अन्दर कूड़ा मिला होता है ? कूड़ा कौन मिलाता है ? आपके एफ०सी०आई० के कर्मचारी मिलाते है । आप का जो क्वालिटी इंस्पैक्टर होता है उसका एक प्रतिशत सवा प्रतिशत मिला रहता है और वह एक साल में इस तरह से चार पांच लाख रुपया कमा लेता है । आपकी

[श्री भारत भूषण]

तनख्वाह से कई गुना अधिक आय उसकी होती है। एक दो साल के बाद उसको अगर निकाल भी दिया जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती है।

रुद्रपुर में जो इनक्वायरी हुई है मैं नहीं समझता हूं कि उस में किसी को कोई सजा होने वाली है। वहां लोग मिले हुए हैं। वे आप से अपनी बात का अनुमोदन करा लेते हैं। हमें आप से यह आशा थी कि कोई बात होगी आपके विभाग की तो मंत्री जी जज बनेंगे हमारी बात भी सुनेंगे और विभाग की बात भी सुनेंगे और जजमैंट देंगे। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि मंत्री महोदय भी वकालत करने लग गए हैं अपने विभाग की और अपने अधिकारियों की जज होने के बजाय। यह हमारी बदकिस्मती है। कुरप्शन का नमूना मैं दे ही चुका हूं। इसके अन्दर दस परसेंट भी चावल नहीं है। नब्बे परसेंट चावल निकाल लिया गया है और ठेकेदारों से कूड़ा मिलवा दिया गया है और गोडाउंज में इसको लगवा दिया। इस सब बेईमानी को छिपाने के लिए करदाताओं से इन्हें सैंकड़ों करोड़ रुपया चाहिये ताकि ये जो माल खराब हो गया है बरबाद हो गया है डैमेज्ड हो गया है इसको छिपा सकें। आपने गांवों में फूड फार वर्क चलाई है। अंधे के हाथ बटेर आ गया है। एफ.सी.आई. द्वारा सारा वह डैमेज्ड माल खराब माल उस में भेज दिया गया है और बांट दिया गया है और सारे गोडाउंज क्लीयर किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एफ०सी०आई० को आप वाइंड अप कर दें। बाजार में माल वैसे ही काफी मिल रहा है और किसी को इस की जरूरत नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रालय को एफीशियेंटली चलाना है किसान के हित में चलाना है तो कागज पर स्कीम देकर नहीं केवल कागजों में लिख कर नहीं बल्कि किसान को हित पहुंचाने की देखभाल करनी चाहिये। आप किसान और वर्कर के कस्टोडियन बनिये भ्रष्ट अधिकारियों से नजात पाइये। 3 वर्ष से अधिक जहां अधिकारियों को हो गये हैं उनका तबादला कीजिये।

मैं समझता हूं कि फूड कार्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी खूबी के साथ फूड कार्पोरेशन के अन्दर सड़े हुए गल्ले को फूड फार वर्क के लिये बाहर भेजकर फूड कार्पोरेशन को बचाया है। अब उनको विभाग का सचिव बनाया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने मंत्रियों को खुश किया है डिपार्टमैंट को ठीक चलाया है और आपके फूड फार वर्क के काम को खूबी से अच्छा सेहरा पहना दिया हैं।

जो आप के द्वारा हो रहा है इसके लिये तो आपको बधाई है फिर भी मैं मजबूर हूं इस संसद् में आपका साथी हूं इसलिये आपके अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस प्रार्थना के साथ कि बजट में जो प्रावीजन दिये गये हैं वह कागज में न रखकर जमीन पर ले आइये और व्यावहारिक रूप में चलाइये ताकि देश की जनता खुशहाल हो सके।

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): I would like to congratulate the Minister for achieving 4½ million tons additional food-grains last years as compared to the year 1975-76. But I would like to remind him that this maximum production has been the result of the labours put in the last 30 years by the previous Government. If Mr. Barnala would refer to the figures of production in earlier years, he will find that in 1950-51 the production was 55 million tonns, it jumped to 104 million tons in 1973-74, in 1974-75 it was 100 million tons and in 1975-76 it was 121 million tons. As compared to 121 million tons he has achieved an increase of 4½ million tons. Certainly this is something to be congratulated upon but, while congratulating the Minister, I would also like to use this forum to send my fervent prayers to the Heavens that the weather Gods may continue to shower their grace and favour cultivation with favourable seasons. More than anything else, in the last two or three years, the Government and the people have been fortunate in having very favourable weather conditions. That, in fact, has contributed to higher production more than anything else.

While there is reason for satisfaction there is no ground for complacency on his part, I would also like to remind him that we in this country have to plan for the future. It is time now that we begin planning for the future. While we have been able to achieve more than a 100 per cent increase in production in the last 30 years, we should be aiming at another 100 per cent increase in the coming twenty years or so because our population is going to be nothing less than 1000 million by the turn of the century and our need for foodgrains would be about 230 million tonnes. How are we getting ready to meet that situation? Are we only going to pat each others back saying we have achieved two million or three million tons more? That sort of thing will not do. We have to plan for a substantially higher rate of increase in production in the coming 20 years or

so. That fact, I don't think, has been properly brought out in the Budget. The seriousness of the problem will bring to our mind what the hurdles are in trying to achieve this substantial increase in production.

The hurdles are many. Firstly, as many friends have emphasized, the peasants of this country, the Kisans of this country feel alienated. They feel they are orphans They feel the Government is against them, that the entire society is against them and that they have to slave for the country. In fact, about 20 per cent of the population is dictating terms to the peasants The peasants are at the mercy of the consumer, of the city man, of the town folk, of the bureaucrats of the officers of the middle-class people, and ultimately, of the merchants. All these people sit on his head and they are reducing the life of the peasant to one of slavery so much so he does not get his dues He is labouring like a slave. Each man in the city is having at least four persons as slaves for him in the villages. All his luxuries and comforts and the high standard of living are being maintained by the city man at the cost of the kisans. That is how the system is functioning Now, what is the solution? It has been said by the Members in this House and I would also say that the solution has to come from the peasants themselves: kisan organizations have to come up Mao-tse-Tung once said that the villagers should encircle the towns; he urged on the under-industrialised countries to encircle the industrialised countries The peasants have to encircle the towns and try to dictate their own terms. Now, as it is, their produce is at the mercy of the traders and consumers. The entire system has to be changed. Of course, that will take a long time, but the process has to be started. Ultimately the time will come when the actual producers, the sons of the soil, will begin dictating their terms to the city-man who is now leading the artificial life of glitter.

Coming to the problem of price-fixation, we have a machinery here, the Agricultural Prices Commission. I do not know what is the standard that they are following. They claim to aim at fixing a uniform price for the produce for the whole country But the cost of cultivation, the labour involved and the inputs involved do not bear out or substantiate their claim that a uniform price can be fixed For example, in 1975-76—I would read out certain figures—the yield per hectare of paddy in different States was as follows: Andhra Pradesh, yield per hectare, 2,485 kilograms, Tamil Nadu 3,225 kgms; Punjab 3,867; and now coming down, in Bihar the yield per hectare was only 1382. Then if you come to my own State, namely, Kerala, the yield will not be more than 1,200 kilograms per hectare. Therefore, what is the philosophy in trying to apply a uniform price for the entire country? The cost of production is different in various States For example, in our own State, Kerala, the wages are higher than in most other States; in Kerala, the agricultural workers get Rs 10 per head per day and the women workers get about Rs. 7 per day While this is so, how can you have a uniform price for the produce for the whole country? The cost of production is entirely different in various States. About fertility and other things, of course, there is no solution; there can be no uniformity I would suggest therefore that there should evolve some method of subsidising the production in high-cost areas In our State, Kerala, we have to pay high electricity charges for pumping out water. That may be subsidised. In high-cost areas, fertilisers, for example, may be supplied at subsidised rates. Without some such method of trying to equalise or make uniform the cost of production, we cannot just fix a uniform price for the whole country.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude in two minutes.

SHRI B K NAIR: I would like to emphasize certain aspects about Kerala.

One is this There is a reference in this Report to the difficulties in Kuttanad In Kuttanad the cost of production is high, and Mr Barnala is advising Why not diversify to some other crops?' For diversification also, the land has to be prepared and money has to be spent Will you subsidise this to some extent? People are prepared to diversify in certain areas Kuttanad measures about 60 000 to 65 000 hectares One part can be separated from the other But certain people have to continue with paddy cultivation because the Government of Kerala is insisting on paddy cultivation being continued because all these years there was shortage of paddy in Kerala and they could not depend on the Centre's supply Now of course the supply position has improved The Central Government has to persuade the Government of Kerala to do away with the Land Utilisation Act That is hanging on the neck of the cultivators Once the Land Utilisation Act or that burden is removed the peasants will be free to go in for their own crops and the peasants will be getting a better return and also the country will be benefited to that extent That is one aspect

The Minister is also in charge of Fisheries We have got about 6 million fishermen employed all along our coast What do we do for these fishermen? Have the government taken any serious note of their plight? Many of them go out into the sea in the monsoon season and die in accidents Serious cyclones are there Have the Government ever thought of having some sort of insurance for them or giving some compensation to them? In Kerala the practice is that the Minister goes to the man's house and gives Rs 500 to the wife of the dead fisherman photos are taken everything is displayed properly and the chapter is closed We have to go in for a serious project for helping the fishermen My suggestion in this, we are getting about Rs 180 crores from exports of fish products Why not have some sort of a cess say 1 or 2 per cent, on the exports? It will easily fetch you about Rs 2 crores and with some contribution from the government also, you can draw up a welfare scheme and help these fishermen families during their days of distress or during the days of unemployment and when fatal accidents take place And then the Food for Work Programme It is not a success in Kerala You supply half wheat and half paddy You have announced that the entire quantity will be given in paddy but that has not been implemented The quantity supplied is very low compared to the wages the agricultural labour gets in Kerala They get Rs 10 per day and you give only 2 1/2 kgs of foodgrains and that is nowhere as a fair compensation Some higher quantum of rice may be given for the day's work and some share of it may also be given in cash While discussing the Sugar Mills take-over Bill I said a portion of the wage may also be given in the form of sugar When you are giving food why not add some sugar too? Why not give them say 1/2 kg of sugar as part of the wage?

There is another aspect The Minister is also in charge of Food There is a lot of complaint about the quality of foodgrains supplied in our State The rice supplied there is fine and superfine which do not sell After all it is meant for the poor people and they cannot pay Rs 1 87 or Rs 2 for your rice So it is lying there and nobody wants it Whenever the wholesaler takes it from the depot he is not able to sell it People insist on having only coarse and medium quality rice If that can be arranged that will go a long way to meet their needs

There is one more aspect A lot of this rice is lying there Why not pass it on to the open market or the superbazar where the well-off people can go and buy it?

Sir, our people are not used to the Punjab boiled rice. A lot of it is lying there unsold. It takes 2 to 3 hours to cook. I suggest the entire thing should be taken away.

Then, a word about land reforms. Kerala Government has been constrained recently to go in for amending the Land Reforms Act. It is a very unfortunate development. We have been claiming all these days that Kerala is the foremost State in the matter of land reforms and we have set up model land reforms. But they have been constrained to go in for amending it, as a result of which 9 per cent of the surplus land is to be retained by the land-owners in the name of gift lands and gift lands are sought to be excluded from the operation of the Land Reforms Act. This is a highly retrograde measure and the Government of India should not give its approval to this Bill particularly because this land should be assigned to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. CHAIRMAN: Shri R P. Das.

SHRI R P. DAS (Krishnagar): Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion....

15 hrs.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN (Tindivanam): Sir there is no translation.

SHRI R. P. DAS: Translation is going on.

MR. CHAIRMAN: Translation is there. Mr. Das you may carry on.

SHRI R. P. DAS: Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion on the Demands of the Ministry of Agriculture many hon. friends have already put forward their views. I would like to say my say perhaps in a slightly different way. Sir, during the last two years weather was very kind to us. There was good rain and because of this and because of the millions of the cultivators, the country had a record production of food grains and other crops. It is no doubt an event for which the government should be congratulated and along with the government I would like to congratulate those who were engaged in cultivation and also the fine weather which could make this record production possible. But this record production has also created some difficulties and I would like to deal with them now. One of the foremost problem of bumper production is the sharp fall in the prices of the food grains and other cash crops. The agriculturist's main problem today is how to market his produce at a remunerative price. It may sound paradoxical but it is true that even though there is such good crop, every section of the population has not been equally benefited by it. You will be surprised to know Sir, that more than 30 crores of population do not have any purchasing capacity. This lack of purchasing power is a matter which should be taken a serious note of because we have seen when production of sugarcane was more the price of the sugar had gone down to Rs. 2.10 to 2.15 a Kg. but the consumption of sugar had increased from 37 lakh tons to 45 lakh tons i.e. only an increase of 8 lakh tons. This amply proves that unless the purchasing power of the people is raised, mere good production will not help the poorer sections of the population, on the other hand, it will help only the capitalists and a limited few who control the trade. I would therefore say that if the Government which stands by its promise to uplift the lot of the peasants and poorer sections of the society is really able to fulfil its promise then the problem can be solved as otherwise the over production is a danger signal which will create catastrophic situation in the country particularly in the field of agriculture.

*The original speach was delivered in Bengali.

15.04 hrs.

[SHRI M SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

While on the one hand, the vast majority of the rural population is suffering from the lack of purchasing power on the other hand there has not been no real redistribution of land among the landless The tenancy system in our country today despite various legislations passed both by the Central Government and the States continue to be semi-feudal and capitalistic in pattern According to agricultural census figures 15 per cent of the land owners own 31 per cent of the cultivable land, 5 per cent of the land owners own 37 per cent of the cultivable land and the 4 per cent of the top land owners own 60 per cent of the cultivable land These figures more than amply show how in the matter of land ownership the rich continue to have their stranglehold over the poorer sections and how the real tiller of the soil live in a state of hopeless exploitation The natural consequence of this phenomena is the fast capitalist penetration in the sphere of agriculture which is apparent in the States of Punjab Andhra Coastal areas of the South and to some extent in some blocks and talukas of Maharashtra UP Bihar and West Bengal I may mention here that the characteristic feature of this capitalist penetration arises out of better availability of irrigation facilities, possession of better technological equipment and know-how massive capital investment and accumulation of land in a few hands Although a total capitalistic domination over agriculture has not taken place yet the prevalence of spread of semi-feudal capitalism in the sphere of agriculture is clearly discernable What is the result of this capital penetration? The result obviously is that these very few persons are cornering and arrogating to themselves the benefits of good agricultural production which ought to have been transferred to the actual cultivators As a result of this the poor cultivators marginal farmers landless labourers, share croppers and the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being exploited continuously The rich is becoming richer and the poor poorer As I have already stated the purchasing power of a vast majority of the cultivators and the rural population is dwindling very fast Their condition is so pathetic that they get full meal for 130/140 days in a year They have no work for the whole year and their wages are far from remunerative And all these have caused a disastrous effect on the purchasing power of the common man who has no shelter to live no food to eat no clothes to wear and cannot afford the necessities of life like his brethren in the cities The number of such deprived population is no less than 30 to 35 crores When the production increases and the people have no purchasing power a demand is usually made by the capitalist lobby that the surplus foodgrains should be exported or the Government should buy all the surplus We know that the FCI is purchasing the surplus foodgrains and they have built a buffer stock But one who is aware about the functioning of the FCI knows it too well that there is rampant wastage in the process of collection and storage by the FCI The people and the toiling masses I must warn the Government will not tolerate a paradoxical situation where in the midst of plenty there should be colossal wastage resulting in starvation of the people Unless the Government is able to bring about a rapid change in the whole situation the results are bound to be dangerous

Mr Chairman Sir towards the end of February and early March this year under the leadership of Andhra Kisan Sabha nearly 75 000 cultivators had launched an agitation This agitation had spread rapidly over the 9 districts of the State including Nellur, Wrangal, Krishna West Godavari and other places The agitators took possession of 8000 acres of land held illegally and they distributed it amongst 20,000 cultivators The most remarkable feature

of this agitation was that more than 50 per cent of the agitators were women. In this struggle two cultivators were shot dead. The matter was raised in the Andhra Assembly and the Minister assured the House that all land illegally occupied would he recovered and an enquiry into the matter has been ordered. I am referring to this glorious struggle only to suggest that the above incident is a red signal which tell to the nation that unless land is properly distributed, unless cultivators are given remunerative price for their produce and unless their wages are reasonable, the exploited multitude will not tolerate the exploitation for ever. They will unite and will rise all over the country to take possession of the land from those who hold them in illegal possession as in Andhra and will force the Government to change their agricultural policy Before the situation comes to a point of explosion it becomes a political and moral responsibilities of all the political parties of the country that they should bend their energies to end the present exploitation of the landless and the poor cultivators that is rampant all over the country today.

I would like to touch upon another matter of importance. It is irrigation. When we talk about irrigation in the House an impression is created that irrigation is a new creation which has lived only for the last 32 to 35 years. But everyone of us know that it is not so. All the early civilization of the world had an elaborate system of irrigation but with the afflux of time and because of willfull neglect these systems got destroyed and were replaced by modern techniques. The tragedy of the matter is that while we discorded the old we could not implement the modern schemes of irrigation either completely or fully. As a result of this we still find in our country that only 25 per cent of the cultivable land is irrigated and the rest of the 75 per cent is denied irrigation. During the last 20 years, out of 146 major irrigation projects only 20 could be implemented and the Damodar Valley project in West Bengal is one of them. So far as the medium irrigation projects are concerned out of 756 projects only 447 could be completed. So far as the DVC is concerned it was proposed that 7 dams will be constructed but this was not done. Out of these 7 only 4 were constructed and 3 still remains to be done. As a result of this last year the heavy water discharge. in the catchment area due to heavy rains created such a terrific depression that the surplus water which could have been contained if the proposed 3 bands were constructed, broke through its banks and devastated villages, roads, rail lines, and caused untold sufferings to the inhabitants. It is very unfortunate that such an incidents should occur because we know it can be averted. The flood cannot be described as an accident and it is quite likely that under similar circumstances an equally devastating floods may occur in the State and to remedy the situation I would urge upon the Government that the 3 dams should be constructed without further delay, afforestation should be done on the hills and tributaries made out of the main stream to channel out the surplus water in times of need. The West Bengal Government have been persistently suggesting to the Centre about these needs but the authorities that be do not seem to bother or attach any importance to these measures and the result is that hundreds and millions have suffered last year and may be many more will suffer in future.

A word about the Ganga basin water resources organisation. Circle Office No. 2 of this organisation has been located at Varanasi, without much justification and as a result it, is causing a lot of inconvenience in its operation. This office has to oversee the agreement that India has entered into with Bangladesh regarding distribution of water through Farrakka. The Circle Officials have to come Farrakka and Calcutta every now and then to hold talks with their counter parts to watch the joint observation work. They have

[Shri R. P. Dass]

also to run to Calcutta for purchasing spare parts, hold discussions with Calcutta Port authorities regarding hydrological observations, to deal with the disputes arising out of Teesta water and also their location in Calcutta for the purposes of forecasting floods would be very helpful. For all these reasons it is very necessary that the Circle Office should be shifted from Varanasi to Calcutta and I would urge upon the Government to take immediate steps in this matter.

Finally, I would conclude by saying that I have just now received intimation from Dandakarnaya that the flour supplied by FCI is of very poor quality and I am laying on the Table a specimen of the same and will urge that something should be done in this regard also.

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): Mr Chairman, Sir, I am thankful to you for this opportunity that has been given to me to speak on the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Sir, Agriculture is the main industry of the country. I congratulate the hon. Minister and the farmers who have produced wheat, rice and jowar in abundance so as to surpass all the previous records. But at the same time I feel sorry on the ground that sugar production has fallen. So is going to be the fate of potatoes which have got a poor market and no provision for storage etc. I need not go into details but I share what other hon Members have said.

Sugar and Potatoes need a policy. There should be a common agricultural policy in toto so that the people who produce will not suffer in the matter of marketing, price etc. The country demands that, as in the case of the success in rice, wheat, jowar etc. so also we should have success all round and the present suffering or shortage of oilseeds, cotton and pulses should be reserved. Heavy expenditure is being incurred on the import of oil etc. which can be saved by being self-sufficient in these things. Our farmers have been under a delusion and a confusion. Sometimes they are asked to produce wheat, but when there is some shortage of sugar, they are asked to produce sugar and so on, without any specific policy in this connection So, what is needed is that the hon Minister should take care to see that the farmers are helped by guiding them in these matters as well. Deforestation is going on unabated in this country due to which floods and soil erosion take place in those places where rivers are flowing. This should be stopped. Necessary land reclamation and soil conservation programme should be undertaken for creating an infrastructure for agricultural production in the country In this connection, I may mention about the J&K State, more particularly Jammu region where four rivers—Chenab, Tawi, Ravi and Basantar—are flowing. Due to deforestation these rivers cause erosion in and around so many areas of the villages in this region. If these rivers are tamed by constructing bunds over them, I think hundreds of acres of land can be brought under cultivation and we can increase the agricultural production More agricultural production means more progress in the country. Therefore, the Government should give thought to these problems so that there is more and more agricultural production in the country.

Now, I come to the modern village. If our country is to advance and progress, we should modernise our villages. As it is, in whatever field the country advances, the benefit does not go to the villages and the villagers are continuing in the same old way of living. I would therefore call upon the hon. Minister concerned to kindly look into these matters and see that in the village the block developmental work is entrusted to the Gram Panchayats or B.D.O's.

There is another important point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. In my own

home town, that is, Kathua in J. & K. State, which is 1025 ft. above the sea level, Morchila known as Guchhi is produced. Normally it is produced in the hilly areas at a higher altitude. But now the experiment has shown that it can be produced 1026 ft. above the sea-level. It is a very good commercial crop and it can be produced in large quantities, especially after this experiment has been successful But I am very sorry to say that nothing has been done by the Ministry concerned so far in this direction and early action in this regard is called for.

Now, recently, the Jute Technology Research Laboratory at Calcutta has been successful in developing the technology of commercial utilsation of agricultural waste produced from cotton and jute Out of these waste materials we get fibre like things. If these waste products are put to proper use, I think it can supplement the income of the farmers They will thus be benefited. Now, it has also been revealed that this fibre-like material can also be got from pineapple and bananas. The hon. Minister should pay attention to this aspect so that things like hard-board, paper board, kraft paper, etc can be manufactured from these waste materials and this can be an additional income to the farmers. I hope the hon. Minister will take special care and in this very budget he would make prosion for this. If the hon Minister is not aware of these things, it is high time that the hon. Minister, in his reply, made positive statement on this point.

Much has been said with regard to Food Corporation of India. I would call it 'Food Corruption of India' Mr Bharat Bhushan has already demanded immediate overhaul of this organisation. If the closure of this organisation is attempted, it will benefit the farmers and the nation to the tune of crores of rupees which are at present being wasted. There are about 25,000 labourers in the F.C.I. and these poor people are being exploited by the contractors and the middlemen. The contractors and the middlemen are the beneficiaries. Every year, more than 5.0 crores of rupees are wasted on account of this organisation. And who is earning? It is only the Food Corporation of India employees who are earning and to which they would not be entitled otherwise. This can be utilised for the nation in other ways gainfully. I hope the hon. Minister incharge of this portfolio will take early steps in this direction and the contract labour system would be abolished and the labourers concerned would be given the best benefit.

The other day, the hon. Minister for Agriculture was kind enough to take part in the meeting of the Food Corporation of India, Workers' Union held on 31st March, 1979. There they voiced their grievances and among others their demands are abolition of contract labour, abolition of private storing agency system, doing away with discriminatory treatment to FCI's direct payment workers, equal pay equal work, evolving a scientific system for good of labour welfare scheme, workers participation in management etc. I am sure, the hon. Minister will consider very sympathetically the genuine demands of the FCI workers who have been clamouring for such a long time. These workers have been facing difficulties at the various depots. The hon Minister was pleased to say some time back that direct payment would be introduced to the labourers working in the FCI. I am sure, in keeping with that assurance given to the labourers in the FCI, he will implement this at the earliest and fulfil his promise. The direct contract labour system should go away and direct payment system to the labourers which will benefit the workers and others should be introduced immediately.

With these words, I support the demands for grants of this Ministry and I hope, the hon. Minister will take due notice of the points made by me.

SHRI DAJIBA DESAI (Kolhapur): Mr. Chairman, Sir, a large number of hon. Members have already participated in the discussion and they have pleaded the case of cultivators and agriculturists and have voiced their grievances. Last year also, a number of hon Members advocated the same line of attitude, but we got no response from the Government. Even in the last year, the hon. Minister for Agriculture announced in this House that he would have a fresh look about the terms of reference of the Agricultural Prices Commission and the personnel of the Agricultural Prices Commission, but after six months actually nothing has happened. In his speech even the Finance Minister and the Deputy Prime Minister realised that agriculture has the largest potential for generating employment and for providing purchasing power to the large majority of people and there cannot be any let up in the task of development of agriculture. But can the Minister for Agriculture and Irrigation say that this approach is reflected in the demands for grants, or the programme of agricultural development, programme of irrigation, programme of rural development or the food programme In fact, this requires a large investment and a greater effort in a number of directions and a better organizational set-up.

As I said, the sentiments or the approach expressed by the Finance Minister and Deputy Prime Minister are not reflected in the demands for grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Take for instance the question of procurement and agricultural price policy. What has been the experience during the last year?

Last year, in spite of demands from every section of the House that remunerative prices should be fixed and Government should come into the market to purchase all available market surplus, Government insisted that the Food Corporation of India and some other agencies will purchase in the open Mandis, paying only a support price. Actually, the result was that the marketing machinery with the Food Corporation or with bodies like NAFED could not reach the Mandis, and the cultivator had to sell his produce at distress prices. All the cultivators in India who were producing wheat, paddy, sugar-cane, potato and jute had to sell their produce in the market at distress prices, price lesser than the support prices Even the Government could not give the support price to the cultivators That is the plight of the cultivators

It is not that the prices of agricultural commodities are going down, that those of industrial commodities are going up, and that there is a big gap between the two. But it is the act of omission on the part of the Government i.e because of Government's policy that this gap has been widening day by day. The result, next year, is going to be the same. The Food Corporation or any other authority or machinery of the Government of India cannot reach every Mandi and every cultivator; and they cannot purchase all the agricultural produce offered by the cultivators. And the Government has dumped the cultivator in the lap of the traders; and the traders have amassed a lot of profits. So, this is the policy of free trade.

Government is taking credit, saying that because of free trade, there is a surplus of agricultural produce, foodgrains etc. and that in every market, you can purchase anything at a reduced or reasonable price. But what is the result? This is the result of free trade which I want to tell the Janata members: this is the policy by which the Government has reduced the cultivators to a pitiable condition.

One hon. Member has just described the working of the Food Corporation. But what is the attitude of the

Government here? Government has calculated the subsidy to the Food Corporation as a subsidy to the cultivators. It is an anomaly, Food Corporation spends Rs. 17 per quintal for just keeping the stock; and again, it spends Rs. 32-80 per quintal for carrying the stock. All these Rs. 560 crores have been debited or credited to the account of cultivators. Is it justice? In fact, this is not given to the consumers. No subsidy is given to them. The only subsidy given to the consumer is Rs. 2.50 for wheat and Rs. 5 or Rs. 7 per quintal for rice. But actually, the carrying cost of buffer stock is supposed to be Rs. 560 crores—or it is there for maintaining the stock. It is not a subsidy given either to the consumer or to the cultivator. It is just a trading account.

In the matter of rural development, Government has come forward now with an Integrated Rural Development Programme. The name appears big. And some voluntary agencies are to be approached and taken into this movement. This Integrated Rural Development Programme is a combination of 5 previous programmes, viz. Small Farmers' Development Agency, DPDA, Desert Area Development Programme, Drought-Prone Area Programme and lastly the Food for Work Programme. Already, out of 5005 blocks, some 2,000 blocks have been covered under these 5 schemes.

Now 300 blocks are to be taken up this year under the integrated rural development scheme, because the Agricultural Department says that financing of these 2000 blocks will be on an old pattern. But the small cultivators—people holding below 5 acres of land—landless labourers, workers will get subsidy at the rate of 25 per cent, 33 per cent and 50 per cent. Is the Government aware that these small cultivators are eligible for getting loan because they are in arrears of loan? Unless they clear their previous loan, they are not eligible for getting further loan. In a number of districts and blocks, the banks are not prepared to finance these projects because of this. The project officers just complete the forms for minor irrigation, for land development and so on and forward them to the banks. If the banks agree to finance them, they are eligible to get subsidy. It means the banks cannot give them loan because they are defaulters. Then the Government has no reason to give them subsidy.

Under the integrated rural development scheme, they have to identify the cultivators. In that process, one or two years ago. Then the proposals have to be submitted to the project officers. That takes one year. For the last three years, I ask the Government to give the estimate of expenditure on this scheme. It is a small scheme. In India, the cultivators who are holding less than half an hectare of land, their number is 2.31 crores; the cultivators who are holding less than one hectare of land, their number is 1.25 crores; and the cultivators who are holding less than 2 hectares of land, their number is 1.34 crores. Then there are six crores landless labourers. It means there are 10 90 crores eligible people. Out of them, they have identified 1.60 crores. This is the report of ten years. In 10 years, they have completed this thing

If you want to take up this scheme, these people must be given the facility of finance and the defaulters must be treated as new applicants. Their loans must be cancelled. This is a good scheme. But if it has to be implemented, then the Government should come forward with definite proposals and take all the people into confidence.

We oppose voluntary agencies, because they are sponsored by Tatas and Birlas. These agencies will play havoc in the rural areas and therefore we oppose them. With these words, I conclude my speech.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्री किसान का बेटा हो और दोनों कृषि मंत्री ही किसान हों फिर भी कृषि और किसान की यह हालत हो कि जो वह पैदा करता है, उसका मूल्य उसे न मिल सके, तो कारखानेदारों की लाबी कितनी ताकतवर है कि बजट पर उन्होंने तूफान मचा दिया है कि यह किसान का बजट है, यह शहरियों के खिलाफ है, यह सिर्फ देहातियों के हक में है। किसान को मिला क्या है ? उसे सिर्फ एक बोरे खाद पर 5 रुपये का मुनाफ़ा हो गया है। एक बोरे खाद पर सिर्फ 5 रुपये की कीमत में कमी हो गई है और उसका जो आलू था, जिसे सरकार ने 50 रुपये खरीदने का हुक्म दिया, कि इससे कम होगा तो सरकार खरीदेगी, इस हाउस में इस बात का एश्योरेंस है, और वह आलू जो कि 50 रुपये वाला है वह 5 रुपये बोरा बिके और यही नहीं बल्कि 3 रुपये बोरा बिके। पौने चार रुपये का बोरा आता है और पौने 3 रुपये का आलू बिके। आलू की छंटाई पर भी 3 रुपये लगते हैं और मण्डी तक पहुंचाने का पैसा भी लगता है।

यह बात अचानक नहीं हो गई है, मंत्री जी को याद होगा कि जब यहां दिसम्बर में इजलास हो रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आलू का इंतजाम कीजिए। आलू पैदा करने वाले बेचारे उल्लू बन गये हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करें। लाखों रुपये का नुक्सान उन्हें हुआ है छोटे-छोटे ज़मीदार का जिसको पैदा करने पर 20, 20 और 25, 25 हजार रूपये खर्च हो चुका है और अब उस आदमी को उसके 2 हजार रुपये नहीं मिल हैं। वे लोग बिल्कुल तबाह हो गए हैं।

मैं एक वार्निंग और आपको देना चाहता हूं कि जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें इतना गेहूं आ रहा है कि वह आप संभाल नहीं पायेंगे। बीच के दलाल सत्यानाश कर देंगे, फूड कार्पोरेशन वाले।

जनता पार्टी ने मैनिफैस्टो में कहा था कि किसान जो भी पैदा करेगा, उसको जब वह बीजेगा, उस वक्त उसे बता दिया जायेगा कि उसे यह मोल मिलेगा। यह मैनिफैस्टो अकाली दल और जनता पार्टी का है। हम जितनी देर विरोधी दल में रहे, लगातार इस बात के लिए सरकार की टीका-टिप्पणी करते रहे कि किसान को पहले बता देना चाहिये कि उसकी चीज का क्या भाव होगा। आज मार्केट में गेहूं आना शुरू हो गया है लेकिन सरकार ने अभी तक भी जिस भाव पर गेहूं खरीदा जायेगा, उन भावों का एलान नहीं किया है। तय हो गये हों तो पता नहीं, लेकिन ऐलान नहीं किया है।

यह कितनी बड़ी बात है कि किसान जो पैदा करे, उसका भाव सरकार मुकर्रर करे और सरकार भी उस वक्त मुकर्रर करे जब उसका माल मंडी में आ जाये। एक तरफ तो किसान की चीजों की कीमत सरकार मुकर्रर करती है और दूसरी तरफ कारखानेदार हैं जिसके माल की कीमत वह खुद मुकर्रर करते हैं। वह अपने माल की कीमत जब मर्जी आया बढ़ा लेते हैं।

अम्बेसेडर कार सन् 1970 में 17 हजार रुपये की थी आज उसी कार के दाम 53 हजार रूपये हैं। 1970 और 1979 के बीच में 3 गुना दाम ज्यादा बढ़ गये हैं। आपको शायद याद होगा कि कार की कीमत बढ़ाने के लिए जब जस्टिस हिदायतउल्ला के पास गये तो उन्होंने मज़ाक में कहा था कि इस कार की हर चीज़ बजती है, लेकिन हार्न नहीं बजता है। हार्न के बगैर सब चीज बजती हैं। कार की कीमत 17,000 रुपये से बढ़ कर 53,000 रुपये हो गई है। इसी तरह ट्रैक्टर की कीमत 19,000 रुपये से बढ़ कर 60,000 रुपये हो गई है। कारखानेदार की बनाई हुई हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है।

आज सवालों के जवाब में उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फ़र्नाण्डीस ने कहा है कि कपास की कीमत कम हुई है और कपड़े की कीमत बढ़ गई है।

हम लोग, जनता पार्टी वाले, इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने प्राइसिज़ को काबू में रखा है। श्री बरनाला और श्री भानु प्रताप सिंह बतायें कि क्या उन्होंने किसान को मार कर प्राइसेज़ को कन्ट्रोल में रखा हुआ है ? कारखानेदार की चीजों की कीमत कहां है और किसान की चीज़ों की कीमत कहां है ? जिन चीजों की कीमतें कम रखने के बारे में सरकार क्रेडिट लेती है, वे तो किसानों की पैदा की हुई चीजें हैं। जो चीज़ किसान पैदा करता है, उसकी कीमत कम है, और जो चीजें वह खरीदता है, उनकी कीमत ज्यादा है, जैसे लोहा, कोयला, और सीमेंट वगैरह।

सीमेंट की कीमत पहले 11, 12 रुपये थी। जब जनता पार्टी ने राज्य सम्भाला तो उसकी कीमत 17 रुपये के करीब थी। लेकिन आज सीमेंट की कीमत 26 रुपये से ऊपर होने वालीं है। ब्लैक में उसकी क्या कीमत है यह कहने की ज़रूरत नहीं है।

किसान जो चीज़ पैदा करे उसको उसका मोल न मिल सके यह इन्साफ़ की बात नहीं है। मैं फिर वार्निंग देना चाहता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी को तरतीब दे, उसको कसे। किसान का गेहूं मण्डी में आ जाये और भाव मुकर्रर कर दिया जाये 115 या 120 रुपये और मण्डी में किसान को 90 या 100 रुपये से भी कम मिले। मिनिस्टर साहब मण्डी में जा कर इस बात की एनक्वायरी करें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : आप एनक्वायरी क्यों नहीं करते हैं और उसकी रिपोर्ट मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं देते हैं ? पब्लिक के रिप्रेज़ेन्टेटिव क्या करते हैं ? क्या सिर्फ मिनिस्टर ही एनक्वायरी करेगा ?

चौधरी बलबीर सिंह : हम तो करते हैं--हम अब भी कर रहे हैं। आपकी जुबान बंद थी। आप बोल नहीं सकते थे। हम करते हैं और मंडी में जा कर भी लड़ाई करते हैं कि इस ढंग से नहीं होगा।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इसकी एन्क्वायरी करायें। मण्डी में नाफेड वगैरह सरकार की एजेंसियों ने आलू दस रुपये बोरी के हिसाब से लिया है, और वही आलू 50 रुपये बोरी दिया है। किसान को उसकी कीमत नहीं मिल सकी। जो सहूलियत सरकार ने दी, उसका फ़ायदा फिर उस आदमी ने उठाया, जिसके पास पैसा था, जो खरीद सकता था और जो किसान को एक्सप्लायट कर सकता था।

किसान की बातें हर एक सदस्य ने कही है। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव यह है कि सरकार फूड कार्पोरेशन के खर्चे को कम करे। एक बोरी को सारा साल रखने का 32, 33 या 37 रुपये का जो खर्च है, वह बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाये। सरकार किसान के घर में अनाज रखे और उसको खर्च दे। इस खर्च के बारे में एक बार 32 रुपये का ऐलान हुआ था और दूसरी बार 37 रुपये का। पता नहीं कि असली खर्च कितना है। मिनिस्टर साहब मुझे बता दें, तो मैं उसके मुताबिक बात करूं। अगर फूड कार्पोरेशन के गोदाम में 35 रुपये खर्च होते हैं, तो सरकार किसान से कहे कि वह उससे गेहूं 115 रुपये + 25 रुपये, यानी 140 रुपये में लेगी, और फलां महीने में लेगी। इससे सरकार का खर्च कम हो जायेगा और उसे गोदाम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। किसान को सरकार कुछ एडवांस रुपया दे दे, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वह अपने माल को रोक नहीं सकता है और उसे एकदम मंडी में बेचना पड़ता है। सरकार अपना माल गोदाम में रखती है। वह समझे कि उसका माल किसान के स्टोर में पड़ा है। किसान इस माल को सम्भाल कर और ठीक तरह से रखेगा, बीमारियों से महफूज रखेगा। सरकार उसको खर्चा दे। इससे किसान को पैसा मिल जायेगा, सरकार स्टोरेज की शार्टेज की समस्या को हल कर सकेगी और किसान को अपनी मेहनत का कुछ मोल मिल सकेगा। यह सुझाव मैंने दिया है--इस पर अमल किया जाये।

मैंने पिछले साल भी कहा था---जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने कारखानों में काम करने वाले मुलाजिम हैं---इन सब लोगों को एक साल का राशन दिया जाय और उस की कीमत 12 किस्तों में उन से वसूल की जाय। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन की तनख्वाह से हर महीने उस की कीमत का बारहवां हिस्सा काट लिया जाय, इसी तरह से कारखाने के कर्मचारियों के वेतन से काटा जाय। इस से यह फ़ायदा होगा कि करोड़ों मन अनाज जो मंडियों में पड़ा रहता है, लोगों के घरों में पहुंच जायगा और हमारे यहां जो स्टोरेज की दिक्कत है, वह दिक्कत हल हो जायगी।

दूसरा सुझाव यह है कि हमें माल बाहर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहां बहुतायत-कावकाइसिज हैं। पिछले 30 सालों के कांग्रेसी राज में हम कासा-गदाई ले कर कभी अमरीका के पास, कभी रूस के पास जाते रहे

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमने 1 करोड़ टन अनाज आप को दिया था।

चौधरी बलबीर सिंह : रेड्डी साहब तो हर वक्त जवाब देने के लिए रेडी हैं। लेकिन वह अपनी बात भूल गये। मैं आप को एक कहानी सुना दूं। एक राजा शिकार पर गया, अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। एक जगह उस का एक बाग नजर आया, वह अन्दर चला गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया बैठी थी। उस ने कहा---मां, पानी पिलाओ। बुढ़िया ने कहा---बेटा, पानी की क्या बात है, मैं तुझे रस पिलाती हूं। उस ने दो सन्तरे पेड़ में से तोड़े और उस का रस निकाला। दो सन्तरों से गिलास भर गया। राजा ने रस पिया और आगे चला। रास्ते में उस ने सोचा कि दो सन्तरों से गिलास भर गया, इसलिए इस पर टैक्स लगाना चाहिए। जब वह वापस लौटा तो फिर उसी जगह पर गया और बुढ़िया से रस पिलाने को कहा। बुढ़िया ने फिर दो सन्तरे तोड़े और रस निकालने लगी, लेकिन इस बार उतना रस नहीं निकला। राजा ने पूछा---माई, क्या बात है, सुबह दो सन्तरों से गिलास भर गया था, इस दफा नहीं भरा? बुढ़िया ने जवाब दिया---बेटा, यहां के राजा की नीयत में फर्क आ गया है।

आप की नीयत खराब थी, इसी लिए लगातार आप के राज्य में कमी रही। वरना आप बतलाइये---आप के जितने प्लान थे, क्या उन का असर 1977 के बाद ही होना था, पहले उन का असर क्यों नहीं हुआ? आज किसान ज्यादा पैदा करता है---तो आप उसे ज्यादा पैदा करने से मत रोकिये। लेकिन हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि उस चीज की फसल कम कर दो। गन्ने की फसल कम कर दी जायगी तो फिर क्राइसेज आयेगा, उस के बाद आप फिर कहेंगे कि ज्यादा पैदा करो। इसी तरह से गेहूं की बात है---अगर गेहूं की पैदावार कम होगी, तो फिर दिक्कत पैदा होगी। इस लिए यह गलत पालिसी है। आप मेहरबानी कर के किसान को ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दीजिए और जो सामान ज्यादा पैदा होता है उस को विदेशों में, दूसरे देशों में भेजने का प्रबन्ध कीजिए। अपने माल के लिए विदेशों में मंडियां तलाश कीजिए, बाहर की मंडियों में मुस्तकिल ग्राहक ढूंढने की जरूरत है। बाहर के लोग यह कहते हैं कि जब हमें माल की जरूरत होती है, तब तो आप देते नहीं हैं, लेकिन जब हम दूसरा इन्तज़ाम करने जाते हैं, तब हमारे पास उसे बेचने के लिए आते हैं।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं---हरियाणा और पंजाब में आप सब्जियों को बहुत तेजी से पैदा कराइये और साथ ही गल्फ-कन्ट्रीज में ऐसा इन्तज़ाम कीजिए कि उस को वहां बेचा जा सके। उन के साथ इन्तज़ाम करें ताकि सामान बाहर भेजा जा सके। जब आप का पैटर्न बदल जाएगा, तो यहां के आदमियों को पैसा मिलेगा, किसानों को अपनी मेहनत का दाम मिल सकेगा और बाहर के देशों को भी अनाज भेजा जा सकेगा।

सभापति महोदय : श्री ए० सी० जार्ज।

चौधरी बलबीर सिंह : सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री ए० सी० जार्ज

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Mr. Chairman, Sir, at the very outset when I participate in this discussion on Agriculture Ministry, instead of going through the normal ritual of either congratulating him or decrying him I only want to say how lucky he is. During the past two, three years, the agriculture in this country has been fairly good, because of God's grace and nature's kindness. Weather is fairly good. The monsoon is rather favourable. The farmers are basically hard-working. Mr. Barnala is lucky and this Government is now fairly on a good footing.

When he took over, we had a stock situation which was unique and unprecedented in the history of independent India. So, he inherited one of the best stocks of foodgrains this country ever had. I particularly congratulate him because unlike the other Ministers, he did not spoil what he got in a Government where almost all other Ministers, whatever they inherited like a prodigal son or like a spoilt child, they were in a spree of frenzy to friter away everything that they got. Here I mention the Finance Ministry. They inherited a foreign exchange reserve of nearly 4000 crores which was accumulated with hard labour of our boys in foreign countries, in which the contribution of Keralites is not very small. Now, the Finance Ministry has tried their level best to see how to empty the coffers. About Commerce Ministry, the same thing applies. For the first time since independence we have record adverse balance of payment of nearly Rs. 1600 crores. I am proud to say because I was the junior Minister of Foreign Trade that we handed over a surplus balance of payment.

About Industry Ministry, the less said the better. The speeches which the Minister makes at lunch, after lunch and at dinner, all are contradictory. And the officers say that they do not take them seriously. So, they blow hot and cold. One day it is nationalisation, the other day it is denationalisation.

About External Affairs Ministry, we know how an aggression was committed under the very nose of our External Minister.

Mr. Barnala, I thank you very much. You did not atleast spoil what you got. I am reminded of a small story which has its bearing on the Agriculture Ministry. In a congregation the cap of the priest was sent for contribution. It was a misers' congregation. In that crowd the cap went round without contribution of a penny. Finally, from that congregation the cap came back to the parson. He took it up, looked into the cap and found there was nothing; he just turned it up and shook it; there was nothing. Then he raised his hand up and said "Oh! Lord I thank thee from his congregation I got back at least my hat." This is the case of the Agriculture Ministry. From the Ministry of Agriculture we got back our hat. So, I congratulate him for not spoiling it.

Of course, he did something in Kerala. Perhaps, he was under the evil influence of the Kerala Government at the time of the constitution of the Coconut Board. Of course, I know that it has been passed in a hurried manner. It has not only been concentrated, but super-concentrated with bureaucracy. It is not going to serve the purpose which he has in mind.

I never question in *bona fides*, because I know that in his heart of hearts he is a son of the soil, he is a farmer and the blood of a farmer is in him. So, I never question his *bona fides*. Kerala is a State where the name of the State itself is inherited from a tree. I was trying in my own limited way to find out whether there is any other instance throughout the world of a country being named after a three, but I could not find one. It is only in Kerala it was known as the land of Keras, which means coco nuts. Of course, some of our friends

in the north pronounce it as Kerala, which means bittergourd.

The production of coconut is our mainstay. The other day we were reading that in spite of the efforts made by the Government to increase the acreage under coconut cultivation in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa and Bengal, the production of coconut has gone down by about 7 per cent in a decade. Here I want to make a specific suggestion for his consideration. In the Kuttanad area, which is the main coconut producing area, we are facing one of the biggest attacks of a disease by insects because of which the coconut production is going down. Since none of us has found a solution for this virus so far, I want to make a suggestion. Just as we did once for rubber, we must go in for a complete removal of the trees In rubber what was done was slaughter tapping after which the emaciated trees were cut off. We gave both subsidy and loan so that there will be an incentive for the farmer to cut down the old trees Instead sticking to his meagre income, since we have not found a solution for this virus, we should encourage the farmers to cut down the trees and replant them. I would request the Agriculture Minister to take immediate measures to create a fund for coconut replantation. In order to encourage the farmers, we have to give the incentive of a loan as well as subsidy so that the farmer will be forced to cut down his trees, which are virus-ridden, and plant new trees. For that a coconut Development Fund has to be created so that the present virus may be fought and production may be increased with a new variety of plantations.

So far as the Coconut Board is concerned, even at this stage I would say that the Minister must take measures to re-vamp it, to regroup it and make it more popular-based rather than bureaucracy-based.

Then I come to another point. We have now got a regulated market, cooperatives and so many other methods to see that the farmers get a proper remuneration for their work. In the hilly slopes of the Malabar area, known as the *Malayora Pradesam*, people from the plans have gone to the mountain slopes, cultivated the virgin land and made a paradise out of it. Even though in a State like Kerala we have got a lot of transportation facilities, in the slopes of the hills there are no proper roads The realisation of the farmer for any crop is directly related to the accessibility to the market In a State like Kerala, where virgin land has been cultivated and many cash crops have been grown, where there is cultivation of the hill slopes of Kerala, there should be a connecting road from Quilon via Kottayam, Idiki, Ernakulam, Trichur, Palghat, Calicut, Malappuram to Cannanore There is a proposal for a hill side road, which should be looked into by the Transport Ministry All these areas should be directly linked so that the farmers can get a reasonable realisation upon their efforts I would urge upon the Government to take steps to see that a specific allotment is made for this type of facilities for the farmers who have gone to the inaccessible areas and created wealth there for the benefit of the country.

16 hrs.

Sir, in my constituency there is a proposal for a sluice-cum-bridge in Elanthikkara Kanakkankadavu across Chalakudy river It is a multi-purpose project. It is a project which will create a bund and save at least 13,000 acres of good paddy land from erosion by saline water This proposal is jointly funded by the State Government and the Central Government. It is a bund-cum-bridge It will serve the purpose of bridging the river and at the same time the bund will serve the purpose of preventing the paddy land from being eroded by saline water for which purpose there is this proposal. So, I urge upon the Minister to kindly fish out the old files and see that it is sanctioned immediately. I understand the sea-erosion is also coming under the

[Shri A. C. George]

purview of the Agriculture Ministry. These days when we talk about disarmament and peace and preventing war, there is a regular war going on at the coast of India, at the western coast especially the south western coast coming down from Karnataka to Kerala and the eastern coast of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This coast has to be protected by anti-sea erosion measures. The funds allotted to Kerala are only a pittance, if not meagre. So, I hope the anti-sea erosion measures will be taken to protect the coast.

श्री अर्जनसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मंत्री ने इस विभाग की जो मांगें सदन के सामने रखी हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। गत 2 साल में कृषि सिंचाई मंत्रालय ने अन्न उत्पादन, सिंचाई क्षेत्र और डेरी उद्योग में काफी प्रगति की है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जब कृषि राज्यमंत्री श्री भानुप्रताप सिंह जी राज्य मंत्री नहीं थे, संसद् सदस्य थे, तब उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उसके कुछ उद्गार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कृषि साधनों पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष-कर उनके उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैं :—

उर्वरक पर 41.99 प्रतिशत कर है, कीटनाशी दवाओं पर 55.00 प्रतिशत, बिजली की मोटरों पर 26.73 प्रतिशत, ट्रेक्टर पर 44.74 प्रतिशत, ट्रेक्टर पुर्जों पर 26.93 प्रतिशत और डीजल तेल पर 74.47 प्रतिशत कर हैं।

मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि क्या उनके मंत्रालय में कोई योजना है जिससे इन अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सके? वह अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए क्या करना चाहते हैं?

भारत का राजपत्र जो 9 मार्च का प्रकाशित हुआ है इसमें फर्टिलाइजर के दाम लिखे हैं। 19 प्रकार के फर्टिलाइजर इसमें लिखे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए सभी को पढ़ता नहीं हूं, लेकिन 3, 4 के बारे में बताना चाहता हूं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट ट्रिपुल, डायमोनियम फास्फेट के बारे में बताता हूं कि इसमें लिखा है कि इनका प्रति टन का भाव इस प्रकार है :—

अमोनियम सल्फेट 890 रुपये, यूरिया का 1450 रुपये, सुपरफास्फेट ट्रिपुल का 1600 रुपये और डायमोनियम फास्फेट का 2200 रुपये, एन० पी० के० का 1800 से 2000 रुपये और सुपर फास्फेट ट्रिपुल (पाउडर) का 1500 रुपये है।

आज अनाज का दाम क्या है, 20 रुपये किलो का दाम 20 रुपये है। एक टन पर 1 हजार किलो होता है, उसके हिसाब से लगाइये तो एक किलो फर्टिलाइजर का दाम 2 रुपये पड़ता है और अनाज का दाम 1 रुपये आता है जब कि खाद का दाम 2 रुपये होता है। यह बात अच्छी नहीं है। अनाज का जो दाम होता है, उससे ज्यादा दाम फर्टिलाइजर का नहीं होना चाहिए।

जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, हमारे देश में पांच मुख्य तिलहनें पैदा होते हैं : मूंगफली, तोरिया-सरसों, तिल, अलसी और अरण्डी। कुल मिला कर तिलहन का उत्पादन 1973-74 में 80.85 लाख मीट्रिक टन, 1974-75 में 80.53 लाख मीट्रिक टन, 1975-76 में 90.91 लाख मीट्रिक टन, 1976-77 में 70.83 लाख मीट्रिक टन और 1977-78 में 80.93 लाख मीट्रिक टन हुआ। 1978-79 में वह 88 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। सभी तिलहनों में मूंगफली की पैदावार 70 प्रतिशत है। पिछली सरकारों ने तीस सालों में मूंगफली के बारे में कुछ नहीं किया। क्या हम भी कुछ नहीं करना चाहते हैं?

गुजरात, और गुजरात में खास कर सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में खास कर जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली और भावनगर वैगरह जिले देश की एक-तिहाई मूंगफली पैदा करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया है और क्या करना चाहती है? मैंने सुना है कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र खोला गया है। लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हुआ है। मैं जूनागढ़ में रहता हूं। मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र में तुरन्त काम शुरू करें।

सभापति महोदय, कृषि विभाग की 1978-79 की रिपोर्ट, पेज 9, पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 1978 से 1983 के अंत तक कृषि-जिंसों का निर्यात 3125 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। वह किस तरह बढ़ाया जा सकता है? बार बार कृषि-जिंसों की निर्यात-बंदी की जाती है। बार बार नहीं होनी चाहिये। कृषि-उत्पादन की किसी भी जिंस पर किसी प्रकार का निर्यात-शुल्क नहीं होना चाहिए। निर्यात पर एस० टी० सी० और नाफेड की मानोपली नहीं होनी चाहिए। उत्पादकों, किसानों, व्यापारियों और परिसंस्करणकर्ताओं की सलाह और सेवायें सक्रिय रूप से लेनी चाहिये। कृषि-जिंसों पर निर्यात-शुल्क रद्द करना जरूरी है।

विभिन्न कृषि-जिंसों पर प्रतिटन के हिसाब से निर्यात-शुल्क इस प्रकार है : एच० पी० एस० मूंगफली की गिरी : 1500 रुपये, मूंगफली साबुत : 1150 रुपये, रुई: 2500 रुपये, मूंगफली की खली (डीआयल्ड)केक : 125 रुपये। क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से बात-चीत कर के इस निर्यात-शुल्क को रद्द कराना चाहते हैं? 3125 करोड़ रुपये का निर्यात सरकार किस तरह करेगी?

करेगी ? जब उत्पादन होगा, तभी वह निर्यात कर सकेगी । लेकिन निर्यात-शुल्क को कम नहीं किया जाता है, बल्कि उसको बढ़ाया जाता है । पांच सात दिन पहले एक सवाल के जवाब में बताया गया कि एच० पी० एम० और मानुल मूंगफली और रूई का निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है । यदि मंत्री महोदय एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वित्त मंत्रालय से मिल कर निर्यात-शुल्क को रद्द कराना चाहिये ।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग का सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि वह भाव कैसे तय करता है । कृषि-उत्पादन के मूल्य तय करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिये (1) कृषि की जमीन की कीमत, (2) जमीन की कुल कीमत का बैंक रेट के हिसाब से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज, (3) किसान व कुटुम्ब द्वारा की गई मेहनत, (4) खेत-मजदूरों को दी गई मजदूरी, (5) आयल इंजिन, बिजली के पम्पस, ट्रेक्टर, ट्रेलर वगैरह औजारों और यंत्रों का खर्च, (6) बैलों की कीमत, (7) बिजली, डीजल आयल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाओं का खर्च, (8) लिया गया कर्ज और उसका ब्याज, (9) जमीन महसूल और उपकर ।

यह सब हिसाब लगा कर लागत तय होनी चाहिये, जैसा कि उद्योग और व्यापार में होता है । इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग में कोई किसान नहीं है । उसमें सब एयर-कण्डीशन में बैठने वाले लोग हैं । किसी ने खेती देखी नहीं है, नदी भी नहीं देखी है शायद हवाई जहाज से देखी होगी । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में किसान के प्रतिनिधि को रखिए ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं —

1 कृषि उत्पादों की लागत—सभी प्रकार का खर्च गिन कर उनका भाव तय किया जाये ।

2 मूंगफली एच० पी० एम० डी० आयल्ड केक्स (मूंगफली की खली) रूई वगैरह इन सब कृषि उत्पादों का निर्यात शुल्क रद्द किया जाये ।

3 सिंचाई और ग्रामीण मार्गों में पिछड़ा हुआ—गुजरात को खास प्रकार से—आर्थिक सहायता दी जाये ।

4 कृषि भाव पंच (एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन) में किसानों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

5 फसल और पशु बीमा योजना को शीघ्र अमल में लाये ।

6 गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के समुद्रतटीय जमीन के कुओं का पानी खारा हो गया है । माधवपुर, पेड, पोरबन्दर, मियाणी, ओखा, नवलखी, मांडवी तक "क्षार प्रवेश अवरोधक योजना" के लिए वित्तीय सहायता दी जाये ।

7 फर्टिलाइजर डीजल, कृषि आयल और कीट नाशक दवायें, कृषि उपयोगी यन्त्रों, मशीनों का उत्पादन शुल्क रद्द किया जाये ।

8 मूंगफली जैसी मुख्य तिलहन के लिए जूनागढ़ में मन्जूर किये गये "अनुसंधान केन्द्र" का कार्य शीघ्र चालू किया जाय ।

9 मूंगफली का न्यूनतम सहायक मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये ।

10 किसानों के लिए 5 प्रतिशत की दर से कर्जा दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

11 नर्मदा योजना का कार्य शीघ्र चालू किया जाये और इस योजना में केन्द्रीय सरकार पूरी वित्तीय सहायता दे ।

12 गुजरात के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए पूरा अनुदान मन्जूर किया जाये ।

13 कृषि जिन्सों का निर्यात बढ़ाया जाये और कई तथा खाने के तेलों का आयात बन्द किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें ।

SHRI A. R. BADRI NARAYAN (Shimoga) I rise to oppose the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Irrigation for the reasons that have been reflected by my cut motions, several in number I hope the hon Minister for Agriculture will go through these cut motions and try to afford as much relief as is possible

With regard to the Central Budget, we are all happy that the Budget is now rural-oriented, a departure from the usual practice of its being urban-oriented I am glad that the hon Finance Minister has provided considerable money for the development of rural areas, from the point of view of agriculture, rural industries, roads and things like that, which go to make up the prosperity of the villagers I am very happy that the Agriculture Ministry is headed by a son of the soil, who is himself a practcal and pragmatic farmer and

[Shri A. R. Badri Narayan]

who has abundant sympathy for the agriculturists. I hope that the red tape of the bureaucracy would not come in the way of implementation of the pious intentions of the Central Government. The Janata Government has solemnly pledged to end the neglect of agriculture and solve the problems of poverty and unemployment within ten years by adopting the strategy of according the top most priority to agriculture and cottage industries. With all the pious intentions of the Government, the agricultural production in this country has been characterised by extreme instability resulting in chronic shortage of foodgrains and also of raw materials, necessitating massive imports which in foodgrains alone is more than Rs. 6,000 crores and in edible oils, it is about Rs 1400 crores. This lag in agriculture has restricted the expansion of the home-market, has hampered the industrialisation of the country, has caused repeated crisis in the formulation of the plans and has also made us increasingly dependent on the imperialists' aid, undermining the economic independence of this country.

Even the limited wealth that is produced by the farmers is all nequitably distributed in the country. The States have drained a part of the income by its taxes and duties; the monopolies and the multinationals have drained through price loot in the capital market; the landlords, the usurers, the hoarders, the profiteers and the bureaucrats have drained through rent, interest, profit, bribes, etc. The peasants produce plenty and suffer while the exploiters fatten, prosper and flourish.

Under the land reforms, only 1.29 million acres of surplus land out of available 21.52 million acres have been distributed. About 20 million acres are yet to be distributed. The Janata Government has put land reforms in the reverse gear. Though I belong to Karnataka, I must in fairness say that practically the tenancy is abolished in the State of Karnataka and the tiller of the soil is now the owner of the land. I would request the Janata Government to see that, in various States, instead of aiding and abetting the landlords to snatch away the tiny patches of land distributed to the poor peasants, this must be put an end to. Several Janata State Governments are shamelessly seeking to enact reactionary amendments to ceiling laws as a legal cover in the marauding of land reforms. Equally shameful is the record of subjecting the peasantry to intensified price loot.

The *Economic Times*, index says that the prices of agricultural commodities have fallen and the prices of manufactures have risen further. The agricultural production has declined by 10 per cent whereas the production of manufactures has increased by 6 per cent, thus causing 15 per cent loss to the agricultural sector. It amounts to roughly about Rs. 2500 crores in a year. This is the annual tribute that is paid by the farmers to the capitalists, the industrialists and the monopolists. The agricultural inputs over 1970-71 output have gone up as follows: diesel—116.6; lubricating oil—209.3; electricity—95.6; cement —87.8, iron—89; fertiliser—75.9; pesticides—131 and tractor—118. While the output of wheat has gone up only by 48 per cent, paddy by 51 percent, jowar by 54 per cent, jute by 40 per cent, cotton by 79 per cent, sugarcane by 33 per cent, the general index of all commodities has risen by 86 per cent. Since 1970-71 the prices of agricultural in-puts, except fertilizers, have risen much higher than the prices of agricultural outputs. The fall in agricultural prices has not been passed on to the consumers. Thus, while raw materials are cheaper, the manufactured items are dearer, for example, cotton and cloth, jute and gunnies, tobacco and cigarettes, oilseeds and edible oils. The fall in whole-sale prices has not been reflec-

ted in retail prices; for example, the wholesale price index for food articles has fallen by 10 per cent but the index of consumer prices has risen by 10 per cent. In December 1978 it was 340 and in March 1977 it was 312. The peasants who are the majority consumers have lost both as producers and as consumers and the gainer are industrialist and traders and the big capitalists, the sharks of the so-called free market. Firstly, they dismantled controls, demolished food-zones and have withdrawn restrictions on forward trading speculation, hoarding land profiteering and, secondly, they have liberalised the credit for hoarding, profiteering and speculation, while restricting the same to State Trading agencies like the FCI, the CCI and the JCI. The increase in bank credit to the private commercial sector has gone up to 2275 crores during 1977 as against 1592 crores in the previous year. There is liberalised import of raw materials in which our production is sufficient to meet our domestic requirements, *viz.*, cotton, rubber, copra and jute. They imported 14 lakh bales of high-priced cotton, paying a subsidy of 72 crores, and 100 crores for staple fibres

Fourthly, there should be a comprehensive distribution system and a widening up of the existing one whereby we are left to the mercy of big traders and mill-owners. Salt, cement, paper, coal, diesel, Kerosene, cooking gas, soda, edible-oils, etc. are all disappearing from the market.

Again, the sugarcane price has been reduced from Rs. 12.50 and Rs. 16.50 per quintal to Rs. 10/-, though the cost of cultivation has gone up. It should not be less than Rs. 12.50 per quintal.

Apart from these things, I wish to say that the farmer is the producer for the country and he deserves the same attention as industrial workers now get. Concentration hereafter should be not only on the industrialists but also on the farmers. The human facilities that have got to be given to the farmer should not be delayed.

MR. CHAIRMAN: Please conclude

SHRI A. R. BADRI NARAYAN: One more point, Sir, and I will conclude. You must conquer the adverse effect of floods on the one hand of delayed and reduced monsoon on the other. I would also refer to unharnessed river waters and linking of the rivers. I am very happy that the Prime Minister has been pleased to announce some days back that the Garland Canal scheme has been under the consideration of the Central Government and that the USSR and the World Bank are likely to finance us, assist us with money as well as with technical knowhow. Leave alone the Garland Canal scheme, there are the South Indian rivers which flow to the west without being utilised in any manner; the water is unnecessarily flowing into the Arabian Sea. A method must be found out to link these various rivers of the South so that we may utilise the waters properly.

Hon. Chairman has been very good to me. He has been asking me to stop. I have got quite a number of points to speak on, but I do not wish to transgress the ruling of the Chair. So, I conclude by appealing to the hon. Agriculture Minister to bear in mind the several points which I have been trying to give in a very constructive manner. I hope he will apply his mind and do the things which are the most dear to his heart in the agricultural sector.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): अधिष्ठाता महोदय अब तक कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कुछ ने हमारी प्रशंसा की है, बधाई दी है और कुछ ने हमारी आलोचना की है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : निन्दा नहीं की है।

श्री भानु प्रताप सिंह : जिस ने निन्दा की है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उसका कारण बताता हूं ।

आज जो देश में कृषि की स्थिति है उसका एक सुनहला पहलू है और एक काला पहलू है । जिसने केवल सुनहला पहलू देखा है उसने बधाई दी है और जिस ने सिर्फ काला पहलू देखा है उसने निन्दा की है । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि एक संतुलित बैलेन्स्ड व्यू ले लेना चाहिये । हमने कुछ उपलब्धियां की हैं ऐसी उपलब्धियां जिनके बारे में दूसरे देश वाले हमारी आज प्रशंसा कर रहे हैं । लेकिन हममें कुछ अभी कमियां भी हैं उससे मुझे इनकार नहीं है । मैं दोनों पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा ।

जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उसकी चर्चा तो दूसरे ही करें तो ठीक होगा । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो देश 2 वर्ष पहले तक दूसरों के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ फैलाता था आज वह दूसरों का पेट भरने योग्य बन गया है । अभी थोड़े समय पूर्व हमारे जार्ज साहब उधर से बोल रहे थे उन्होंने भी लैफ्ट हैण्डेड कम्प्लीमेंट दिया उन्होंने कहा कि सब मंत्रालयों को तो नहीं कह सकता मगर कृषि मंत्रालय को कह सकता हूं कि जैसा उन्होंने चार्ज दिया था उसको बिगाड़ा नहीं है । इसको मैं लैफ्ट हैंडिड काम्प्लीमेंट इस लिए कहता हूं कि ठीक है उन्होंने एक अन्न भंडार दिया था लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं--- वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं---कि वह अन्न भंडार किस प्रकार से बना था । क्या वह अन्न इस देश में पैदा हुआ था ? विदेशों से मंगा कर अरबों रुपयों या विदेश भेज कर वह अन्न भंडार बना था । उस अन्न भंडार को बनाने का दूसरा तरीका यह था कि अपने देश के किसानों के घरों से जबर्दस्ती पुलिस भेज कर उनकी मर्जी के खिलाफ़ बहुत कम कीमत पर जब्रिया गल्ला वसूल किया गया ।

आज हमारा अन्न भंडार न तो विदेशी अन्न से भरा है और न हम ने किसी किसान से उसकी मर्जी के खिलाफ़ जब्रिया वसूली की है । जो कर्जा उन्होंने लिया था उस कर्जे को हम ने उतार दिया । सोवियत रूस से जो 20 लाख टन गेहूं लिया गया था वह करीब करीब उनको वापस दिया जा चुका है । उलटे हमने उनको दो लाख चावल देने का टन अभी फैसला किया है । अगर इन दोनों परिस्थितियों में जार्ज साहब को कोई अन्तर नपर नहीं आता है तो मैं तो यही कहूंगा कि देखने का दोष है ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जहां तक किसानों का प्रश्न है कांग्रेस के शासन और आज के शासन में उनको कोई अन्तर नज़र नहीं आता है । याददाश्तें बहुत छोटी हुआ करती हैं इस लिए मैं बहुत संक्षेप में केवल कुछ पायंट्स बता देना चाहता हूं कि क्या अन्तर हुए हैं ।

पहला अन्तर तो यह हुआ कि पहली पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए व्यय की गई धनराशि 19 से 23 प्रतिशत होती थी मगर अब उसको करीब करीब दुगना कर दिया गया है । इसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं । पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में सिचाई पर जितना व्यय हुआ था उससे अधिक इन पांच वर्षों में सिचाई पर व्यय होने जा रहा है । पिछले वर्ष 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई पहुंचाई गई । यह बिना धन को लगाये हुए नहीं हो सकता था । इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगानी पड़ी है ।

अभी कुछ दिन पूर्व सोवियत यूनियन के डिपुटी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, मुझ से मिलने आये थे, जब मैंने उनसे कहा कि भारत में 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की व्यवस्था एक साल में की गई है, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि हमारे इतने बड़े विशाल देश में किसी एक साल में दस लाख हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई ।

जब इस सरकार ने चार्ज लिया था, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्न नहीं जा सकता था । राज्य तो छोड़िये, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को अन्न नहीं जा सकता था । और मेरा ज़िला तो ज़िला तो इतना बदकिस्मत था कि नदी के इस पार आधे ज़िले से नदी के उस पार भी अन्न नहीं जा सकता था । इमर्जेन्सी से पहले भी और इमर्जेन्सी के दौरान भी चारों तरफ किसानों को घेर कर उनको लूटने की व्यवस्था बनी हुई थी । वे अपना माल कहीं बेच नहीं सकते थे, सिवाये सरकारी एजेंसियों को । उसके दुष्परिणाम भी थे, परन्तु उसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती थी ।

जनता सरकार ने पहला काम यह किया कि इस देश में एक बाज़ार कायम किया "एक राष्ट्र एक बाजार" का जो उद्देश्य था, उसको प्राप्त किया । दिल्ली के निवासी भले ही इसके लाभ को न समझते हों, लेकिन जा कर बम्बई और पूना के लोगों को पूछिये कि उनको कितनी राहत मिली है---केवल इस कारण से कि खाद्यान्नों के आवागमन पर से सारे प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं । जिन लोगों को दस बारह रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता था, आज उनको दो रुपये किलो के हिसाब से चावल मिल रहा है ।

चीनी की दोहरी नीति थी ---चीनी दोहरे मूल्य पर बिकती थी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो चीनी 2-90 रुपये पर आ गई । लेकिन वह भूल गये कि पहले क्या स्थिति थी । अगर फ्री-चीनी और लेवी-चीनी की वेटेड-एवेज ली जाय तो आज की चीनी से भाव ऊंचा था । जहां तक उपलब्धि का प्रश्न है---गांव वालों को चीनी नहीं मिलती थी और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि चीनी की उस दोहरी-मूल्य-नीति के कारण इस देश में कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपये की ब्लैक मनी जैनरेट होती थी, उस को हमने समाप्त किया और इस का एक लाभ अभी भी स्पष्ट है कि चीनी की खपत देश में एक दम बढ़ गई ।

पिछले दिनों हमारे सामने एक सब से बड़ी समस्या यह थी कि चीनी उद्योग में उत्पादन खपत से ज्यादा था, वह समस्या प्रायः सुलझ गई है। जिस गति से चीनी की खपत बढ़ी है—डी-कण्ट्रोल होने के बाद से—आप देखेंगे कि 60 लाख टन चीनी की खपत इस देश में हो जायगी और साथ ही साढ़े-छः लाख टन हम विदेशों को भी भेजेंगे। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जितनी चीनी बनेगी; उस से कुछ ज्यादा ही देश के अन्दर खपत होने वाली है तथा विदेशों को भेजी जाने वाली हैं। इस तरह से चीनी उद्योग की जो सब से बड़ी समस्या थी, उस को हम ने हल किया है।

अब मैं "फूड-फार-वर्क" के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप को मालूम है—पीछे "फूड-फार-हंगर" नाम की एक स्कीम चली थी, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्कीम थी, परन्तु जितना उस स्कीम के अन्तर्गत सारे संसार में अनाज व्यय होता था, उस से ज्यादा "फूड-फार-वर्क" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पिछले वर्ष व्यय किया है। जो लोग भूखे रह जाते थे, जिन को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे यहां खेतों में चन्द महीने ही काम होता है, ऐसे लोगों को बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ता था, आज उन्होंने हमारी इस योजना के कारण भर-पेट भोजन पाया है। हम लोग यह चर्चा करते हैं और वह ठीक भी है कि खेतिहर मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिये। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं—फूड-फार-वर्क योजना में काम करके आज जो उन को मिला है, वह मिनिमम-वेज दिलाने से उन को नहीं मिल सकता था। आज इस योजना में एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं मिल रहा है, तब फिर वह 2 या 3 रुपये की मजदूरी करने नहीं जायगा। इस तरह एक तरफ हम ने लोगों को रोजगार दिया, लोगों का पेट भरा और दूसरी तरफ बहुत सारे निजी-इयूरेबिल एसेट्स भी खड़े हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रण देता हूं—वे चल कर देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में किस तरह से काम हुआ है और गांव वाले इस योजना से कितने खुश हैं।

एक शिकायत यह की गई कि "फूड-फार-वर्क" योजना में सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। श्रीमन्, यह नितान्त असत्य है, क्योंकि राज्य सरकारों को मैंने बारम्बार स्वयं लिखा है कि इस गल्ले को उसी प्रकार से स्वीकार करें जिस प्रकार से "फेअर ब्राइस-शाप्स" का गल्ला स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि गल्ले का चार्ज लेने से पहले उस की क्वालिटी को चख सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कोई भी रद्दी माल जबरदस्ती नहीं थोपा जायगा, यह बात बारबार स्पष्ट की जा चुकी है और उन को भी अपना अधिकार मालूम है। जहां तक फूड-फार-वर्क का प्रश्न है, उस के लिए मैंने विशेष रूप से लिखा है कि यद्यपि उन को यह गल्ला मुफ्त में मिल रहा है लेकिन इस की कीमत करल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चुकानी है। इस-लिये इस गल्ले को देख कर लें और इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार ने आज तक मेरे पास गल्ले की क्वालिटी के बारे में या कम से कम फूड-फार-वर्क के गल्ले के बारे में लिख-कर नहीं भेजा बल्कि उल्टे आज उस की मांग इतनी ज्यादा है कि हम को सोचना पड़ता है कि क्या हम उस की मांग को पूरा कर सकेंगे। पहले तो, प्रारम्भ में यह योजना शुरू की गई थी, उस समय हम को यह कहना पड़ता था कि आप इस काम को करवाइए लेकिन आज यह इतनी लोकप्रिय हो गई है कि हमारे लिये मुसीबत हो गई कि हम किस हद तक उन की मांगों को पूरा कर सकेंगे।

रोजगार बढ़ाने के लिए दुग्ध योजना भी चालू की गई है जिस पर अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सात सालों में।

श्री भानु प्रताप सिंह : इस से मैं समझता हूं कि छोटे किसानों को और भूमिहीनों को बहुत राहत मिलेगी।

फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कीमत पिछले 2 वर्षों में 200 रुपये टन गिराई गई है... (व्यवधान)... आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि इस के भाव पेट्रोलियम से तय होते हैं। 1970-71 के मुकाबले में पेट्रो-लियम किस भाव पर मिल रहा था।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले वर्षों के अन्दर जो कर्जे दिये जायेंगे, उस का सूद भी 2 प्रतिशत गिराया गया है। पिछले कई वर्षों से देश में जो तम्बाकू पैदा करने वाले किसान हैं, उन को एक्साइज ड्यूटी वगैरह में परेशान किया जाता था और उन की संख्या बहुत बड़ी है, आज वे राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि इस से सरकार ने उन से एक्साइज ड्यूटी की वसूली बन्द कर दी है।

अब तक हम क्या कर चुके हैं, उस के बारे में मैंने 10, 11 प्वाइण्ट्स के बारे में बताया है। जो पहले नहीं होता था और जिस के बारे में इस सरकार ने कुछ किया है, वह मैंने आपको बताया है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं। यह मैं मानता हूं कि जो खरीददारी की योजना बनती है, बहुत से किसान अपना गल्ला सपोर्ट प्राइस पर भी नहीं बेच पाते। यह बात सही है परन्तु उस में जो कठिनाइयां हैं, उन की ओर भी आप ध्यान दें। सारी खरीददारी एफ० सी० आई० नहीं करती। वास्तव में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों को बारम्बार लिखा जा चुका है कि जो भी गल्ला वे खरीदेंगी अगर वह स्पेसीफिकेशन के मुताबिक है तो, उनका खर्चा अदा कर के भारत सरकार उस को ले लेगी। अगर कहीं कोई भी कमी होती है, तो उस के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एफ० सी० आई० की अपने एरिया में आपरेट नहीं करने देती। तरह तरह के उन के पैटर्न हैं। कहीं

[श्री भानु प्रताप सिंह]

पर राज्य सरकार और एफ० सी० आई० दोनो खरीदती है, किसी राज्य में केवल एफ० सी० आई० खरीदती है और किसी राज्य में केवल राज्य की अपनी एजेन्सी खरीदती है। तो इस चीज को भी आप समझें। यह सब होते हुए भी हमारा यह बहुत स्पष्ट फैसला है और इस फैसले से हम ने सभी मुख्य मंत्रियों को अवगत करा दिया है कि अगर कहीं भी कृषि पदार्थ की सपोर्ट प्राइस घोषित होगी और उस को अगर वे अपने राज्य में खरीदेंगे और वह हमारी एफ० सी० आई० के स्पेसीफिकेशन के मुताबिक होगा, तो उस की कीमत दे कर और उस के खरीदने का खर्च भी दे कर भारत सरकार उस को ले लेगी। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि जहां आप हमारे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं कुछ राज्य सरकारों पर भी दबाव डालने की कृपा करें। नायडू साहब बार बार नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी मेरी समझ में नहीं आती है। हम ने आन्ध्र प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहे जितना भी चावल और धान खरीदें सब एफ० सी० आई० लेने को तैयार है। इस वास्ते वह इस नाराजगी को कुछ उधर भी करने की कृपा करें।

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए एक नई योजना चलाने का फैसला किया गया है जिस का जिक्र हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था और वह ग्रामीण गोडाउन बनाने की है —

श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा (पुरी) : फूड-फार-वर्क में आप उड़ीसा को चावल क्यों भेजते हैं वह तो वहां पहले से ही काफी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह उन से आप कहें कि हम को लिख कर भेज दें। जबर्दस्ती हम किसी को नहीं देते हैं। मांगेंगे तभी देंगे।

रूरल गोडाउंज की नई योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 5–6–7 गांवों के बीच में एक डेढ़ या ढाई सौ टन के लिए गोदाम बने और वहां छोटे किसान नजदीक से आ कर अपना गल्ला रख सकें और वहां दोनों ही काम कर सकेंगे, अगर बेचना चाहें स्पोर्ट प्राइस पर तो बेच सकेंगे और अगर रखना चाहें तो रख सकेंगे और अगर रखना चाहेंगे तो रख कर उसके मुकाबले से उनको नकदी काम चलाने के लिए बैंक से एडवांस दिला दिया जाएगा। यही किसान हैं जिन को सब से ज्याद रक्षा की आवश्यकता है। यह केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं है। अब तो हम चाहते हैं कि किसान भी स्वयं संगठित हों। हम दावा नहीं करते हैं कि हमने सब ठीक कर लिया है और कुछ करने को बाकी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरा हमारी कठिनाइयों पर भी गौर करें। पहली तो यह है कि खेती का कारोबार ऐसा नहीं है जिस को तत्काल दुरुस्त किया जा सके। एक फसल अगर इस साल मारी जाएगी तो अगले साल आप उस में कुछ संशोधन कर सकेंगे। फैक्टरी में अगर कोई काम गड़बड़ दिखाई देता है तो एक सप्ताह और दस दिन में उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन स्विच दबाने से जैसे एक पंखा चलने लगता है उस तरह से खेती के बारे में नहीं हो सकता है। अब तक की जो व्यवस्थायें थीं वे कमी का मुकाबला करने के लिए थीं। देश में कमी का एक वातावरण था। उद्देश्य यह था कि गांवों से अधिक से अधिक गल्ला निकाल कर, जबर्दस्ती या जैसे भी हो उपभोक्ताओं को खिलाया जाए, उनकी रक्षा की जाए। यह आवश्यक भी था। आज परिस्थिति बदल गई है। आज की परिस्थिति में मैं समझता हूं कि गांवों में गोदाम बनने चाहियें ताकि छोटे किसान को दूर जा कर परेशान न होना पड़े और वे अपना माल रख कर उसकी कुछ कीमत पा कर जब भाव बढ़े तो उसका लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य से रूरल गोडाउंज बनाने की योजना रखी गई है।

यहां मांग की गई है जिस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि जो खाद्यान्न किसान स्वयं रखे रहें और बाद में सप्लाई करें गवर्नमेंट को तो उसका भी जो खर्चा एफ०सी०आई० वगैरह का आता है वह अधिक दे कर उससे ले लिया जाए। डैफर्ड प्रोक्योरमैंट के लिये ऊंची कीमत दीजिये इसमें सभी का लाभ है। आप इस बात को इस प्रकार से समझें कि जिस वक्त गेहूं प्राप्त होता है पंजाब और हरियाणा में मई के शुरू में आयेगा कई बार 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो उस वक्त हमारे पास रखने की जगह की कमी होती है ट्रांस्पोर्ट की कमी होती है। सभी प्रकार से मंडियों में भी जगह नहीं रहती है। इस प्रकार से यह सोचा गया है कि कुछ तो माल रखा जायेगा पंजाब रूरल गोडाउन्स में और कुछ किसान अपने घर पर ही रख लें तो उसको बरसात के बाद अक्तूबर नवम्बर में और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में सरकारी भाव देकर ले लिया जाये। लेकिन आज किसान क्यों रखें ? जब पूरे वर्ष तक एक ही भाव रहना है तो उसका परिणाम यह होता है कि हरेक यह चाहता है कि दुकान खुलते ही पहुंचा दिया जाये। तो इससे जहां एफ०सी०आई० पर बहुत बड़ा भार आता है वहां यह भी होता है कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। लेकिन उस भार को कम करने के लिये मैं समझता हूं कि यह दो योजनाएं सहायक सिद्ध होंगी।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है अब तक सिंचाई के लिये सिर्फ 2 हेक्टर तक के किसानों को सब्सीडी मिलती थी अब सोचा जा रहा है कि यह 4 हेक्टर तक के किसानों को सब्सीडी दी जायेगी। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक छोटे नल कूप बनाकर किसान स्वयं स्वावलम्बी बनें।

मैं एक कृषक के नाते कह सकता हूं कि खेती अच्छी वही कर सकता है जिसका पानी का स्रोत उसके अपने कंट्रोल में हो। यह तभी सम्भव है जब अधिक से अधिक किसान अपने नल कूप बनायें। अपने देश में बहुत बड़ा उत्तर भारत का भाग है जहां नीचे पानी की कमी नहीं है जहां आसानी से पानी निकल सकता है। तो उस जल का हमें लाभ उठाना चाहिये। प्राय: लोग कहते हैं

कि मौसम। मौसम की कृपा से कुछ हुआ" इस बात पर मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा वह अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि हम सिंचाई के साधनों को बहुत तेजी से बढ़ा सकें, तो इस मौसम के उतार चढ़ाव से इस देश को मुक्ति मिल सकती है। आज मौसम पंजाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप विश्वास रखिये, चाहे जैसा भी मौसम होगा, पंजाब और हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल होगी। तो हम उसी स्थिति में पहुंचने के लिये किसानों की सहायता करना चाहते हैं कि वह अधिक से अधिक नलकूप बनायें।

एक बात की मैं और चर्चा करना चाहता हूं। गरीबी दूर करने की सब की स्वीकृति है, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी? गांव की गरीबी दूर करने के लिये दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पूंजी और दूसरे कुछ नया ज्ञान विज्ञान। अगर कोई समझता हो कि केवल इस बात की चर्चा कर के कि बड़े किसान छोटे को लूट रहे हैं, या इस प्रकार की बातें कर के कोई गरीबी दूर करने की कोशिश करे तो वह राजनीतिक लाभ तो उठा सकता है, लेकिन देश की गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिये पूंजी और नई जानकारी का पहुंचाना बहुत जरूरी है। जहां तक पूंजी का प्रश्न है, मैं बतला चुका हूं कि भारत सरकार जितना व्यय करती थी, उसका दुगना व्यय अब करने जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी यह भी कोशिश होगी कि हम वहां कुछ थोड़ी जानकारी भी पहुंचायें। जब मैं कभी किसी कृषि अनुसंधान केन्द्र पर जाता हूं तो ऐसा लगता है कि यहां जानकारी का ऐसा जखीरा है कि अगर हमारा इस्तेमाल हो तो इस देश का चित्र बदल सकता है। लेकिन दुःख की बात है कि वह जानकारी, जिससे दूसरे देशों के लोगों ने फायदा उठाया है, हमारे देश के लोगों ने उससे लाभ नहीं उठाया। हां बीज जरूर कुछ बिखर गए हैं, लेकिन बाकी जानकारी वहीं की वहीं रह गई है।

एक योजना, जिसका निवारी जी ने जिक्र किया—लैब टु लैण्ड—उसका उद्देश्य है कि जितने अनुसंधान केन्द्र हैं वे अपने पड़ोस में सबसे गरीब लोगों को छांट कर अपने विज्ञान के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। 150 हजार परिवार छांटे जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक योजना यह भी है कि गांवों से कुछ पढ़े लिखे लड़कों को लेकर उन केन्द्रों पर दो तीन महीने रखकर किसी एक काम के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा—चाहे आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन हो, सेरिकल्चर हो, पोल्ट्री कीपिंग हो या इंजन रिपेयर, मोटर रिपेयर का काम हो। जितने भी धंधे गांवों में चल सकते हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इन्टेसिव डेवलपमेन्ट ब्लाक्स में पहले से ही यह योजना लागू है लेकिन दुःख की बात है कि लोगों को यह मालूम नहीं है। मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य है, यद्यपि एक साल में गाइडलाइन्स लिखी गई हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। 2300 ब्लाक्स से बढ़ाकर 2600 ब्लाक्स में लागू किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यह योजना सारे देश में लागू की जाए। गांवों के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नया काम सिखाया जायेगा। नौकरी देने के लिए हम उनको यह काम नहीं सिखा रहे हैं बल्कि तीन, चार, पांच महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी जिसमें वे काम सीख कर गांवों में जायें और सेल्फ एपलायड पर्सन की तरह से अपना कारोबार शुरू करें। इसमें एक तो उनका अपना रोजगार हो जायेगा और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। (व्यवधान)

दो एक बातें मैं और कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कही जिनका उत्तर देने से यद्यपि नतीजा नहीं निकलना फिर भी मैं निवेदन करूं, जैसे चन्द्र शेखर सिंह जी ने यहां पर कहा कि जेल में जितना राशन दिया जाता है उसके हिसाब से देखा जाये तो इस देश के लिए कम अनाज पैदा हो रहा है फिर भी कहा जाता है कि अनाज फाजिल है इसलिए सरकार के सारे आंकड़े गलत हैं। माननीय सदस्य केवल यह भूल गए कि जेल में बच्चे नहीं रहते। बालिग की खुराक और दूसरी तरफ सभी की खुराक में थोड़ा फर्क है। (व्यवधान)

इस बात की चर्चा भी की गई कि पहले चीनी बहुत एक्सपोर्ट होती थी और यह सरकार निकम्मी है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें नहीं मालूम कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का क्या भाव है। जिस समय का माननीय सदस्य जिक्र करते हैं उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य 700 पाउंड प्रति टन था और आज 100 पाउंड प्रति टन है। उस समय की सरकार ने चीनी बेच कर भुनाफा कमाया था हम आज भी बेचते हैं लेकिन घाटे पर बेचते हैं।

एक्सपोर्ट की बात भी कही गई। इस विषय में मझे ज्यादा नहीं कहना है मैं भी एक्सपोर्ट का बड़ा हिमायती हूं लेकिन साथ ही मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट भी ऐसे नहीं हो सकता है कि आज आपने फैसला किया कि एक्सपोर्ट होगा और कल एक्सपोर्ट हो जाये। दुनिया के लोग मह बाये बैठे नहीं रहते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हर एक को अपने कन्टमर बनाने पड़ते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रवेश नया होगा और उसको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी—यह देखना है। हमारा यह है

17 00 hrs

श्री चन्दन सिंह (कैराना) मेअरमैन साहब मझे एक बात कह लेने दीजिये। रात मेरे बच्चे ने टेलीफोन किया कि पिताजी 20-25 किलो मूंग लेते आना। बड़ी मश्किल से मूंग मिली, मैं मूंग लेने गया तो वह अफसर मीटिंग में था। मेरे बच्चे ने कीट-नाशक दवा भी लाने के लिये कहा था, जब मैं उस के केन्द्र में पहुंचा तो मालूम हुआ कि यह कानून है कि आर्डर देने के एक महीने बाद मिलेगा। मैंने कहा कि सोइंग का टाइम तो अब है, मैं तीन दिन बाद सोइंग करने जा रहा हूं, दवा एक महीने बाद मिलेगी तो उस से क्या फायदा होगा। मंत्री जी इस तरह के कानून को बदलिये, जरूरत आज है एक महीने बाद मिलेगी, इस से क्या फायदा है।

श्री भानु प्रताप सिंह यह शिकायत सुन कर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है। मैं तो चौधरी साहब को बहुत अच्छा किसान मानता आया हूं। जिस टीक की आप बात कर रहे हैं—वह इन आकयुलेशन है, जब किसान पहली बार मूंग बोता है तब उस को डालनी होती है। जब वह तिलहन या दूसरी फसलें उस से ले चुका है तो उस को दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती है।

श्री कमल सिंह खेत की मिट्टी को बदला नहीं जा सकता है।

श्री भानु प्रताप सिंह आप उसकी बात मानते क्यों हैं।

अन्त में केवल एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह मान कर चलना कि केवल भारत सरकार या भारत सरकार के मंत्री कृषि की स्थिति को सुधार सकते हैं—यह एक गलत धारणा है। इस काम में बहुत सारे फरीक हैं। सब से बड़ा फरीक तो राज्य सरकार है, उस के बाद स्वयं किसान है। बढ़िया से बढ़िया योजनायें बनाई गई हैं, लेकिन अगर मौके पर डीजल न मिले, फर्टिलाइजर न मिले तो दिक्कत होती है—हम ने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया है लेकिन सब के सहयोग से ही यह काम सफल हो सकता है।

आलू की चर्चा की गई। आलू के बारे में मैं कहना चाहता हूं—सरकार की पूरी सहानुभूति होते हुए भी किसानों की समुचित मदद नहीं की जा सकी और उस का मुख्य कारण यह है कि मदद करने के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये वह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त कोल्ड-स्टोरेज होने चाहिये, रेफ्रीजरेटेड-वेगन्ज होने चाहिय—लेकिन वाना नहीं है। जो थोड़े-बहुत कोल्ड स्टोरेज हैं——वे सब भर चुके हैं। हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में कोल्ड-स्टोरेज बनाये जाने चाहिये। अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर बात करने के लिये मैं वेस्ट बंगाल गया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात को माना और कहा कि हम 100 नये कोल्ड-स्टोरेज बनायेंगे, लेकिन अब उन के मुख्य मंत्री जी का पत्र हमारे पास आया है कि उन के पास सीमेन्ट नहीं है। आप इस बात पर विचार कीजिये—कृषि की समस्या का बहुत ज्यादा सम्बन्ध बिजली, सीमेन्ट, डीजल और लोहेवालों से है। हम सारी अर्थ-व्यवस्था में इन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कभी-कभी थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पुराने ढर्रे पर खेती करें, छोटे-छोटे उद्योग हों, तो उन से देश का भला होगा। मैं कहता हूं—उद्योग की बात तो छोड़ दीजिये, खेती भी उस तरह से नहीं चल सकती है, जब तक हमारे उद्योग ऐसे न हों जो हमारी खेती की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

17.04 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*].

इसलिए आप हम को जब जाचें, आंकें, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आंकें। यह कहना आसान है कि सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन की तरफ भी आप ध्यान दें।

आलू की बात बहुत की जाती है पर आलू का क्या किया जाए। मैं पिछले साल से पूछ रहा हूं कि हम को यह तो कह दिया जाता है कि किसानों की मदद कीजिए मगर जब मैं यह पूछता हूं कि किस प्रकार से मदद की जाए, तो कोई उत्तर नहीं मिलता।

अन्त में मैं कुछ एफ०सी०आई० के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्वयं यह दावा नहीं करता कि यह एक बहुत बढ़िया और एफिशियेन्ट आर्गेनाइजेशन है, परन्तु जिस प्रकार से आलोचना की गई है वह भी सही नहीं है। सब से पहले तो मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० का काम केवल खरीद कर उपभोक्ताओं को गल्ला पहुंचाना नहीं है। यह एक प्रकार से इन्श्योरेन्स है। जो आप 570 करोड़ रुपये की बात करते हैं कि इतना घाटा होता है, उस में से आधे से ज्यादा बफर स्टाक के लिए है पर यह तो एक पालिसी मैटर है कि क्या हम को बफर स्टाक रखने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत है तो उस को आप इन्श्योरेन्स मानिये, उस को नुकसान में मत गिनिये। संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ आदि के आर्गेनाइजेशन हैं और यू०एन०ओ० में जो एफ०ए०ओ० का आर्गेनाइजेशन है, उन सब का यह कहना है कि रिजर्व फूड स्टाक होना चाहिए, न केवल अपने लिए स्टाक फूडस्टफ का होना चाहिए बल्कि और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अब अगर हम बफर स्टाक रख रहे हैं, तो वह न केवल अपने देशवासियों के लिए मुसीबत के वक्त काम आएगा बल्कि और जो हमारे पड़ोसी हैं उन के काम भी आ सकता है और इस के रखने पर जो खर्चा होता है, उस को अगर आप हमारी नालायकी गिनने लग जाएं, तो यह हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एफ०सी०आई० में भी उसी प्रकार के लोग हैं, जैसे कि और दूसरे सभी विभागों में और सभी वाक्स आफ लाइफ में हैं। इस देश में ईमानदारी का क्या स्टैन्डर्ड है, यह सब को मालूम है लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज तक किसी माननीय सदस्य ने एफ०सी०आई० के किसी कर्मचारी या अधिकारी के बारे में मेरे पास शिकायत नहीं भेजी है। हां, पचासों माननीय सदस्यों ने उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पैरवी की है, जिन के बारे में यहां खड़े हो कर उन को नालायक और बेईमान कहते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी रिकमेंडेशन करते हैं पैरवी कोई नहीं करता है। . . (**व्यवधान**) . . .

श्री भानु प्रताप सिंह : जिनको यहां कहते हैं कि भ्रष्ट हैं उन्हीं की पैरवी करते हैं. . . (**व्यवधान**) . . मेरे पास शिकायत लाएं या प्रमाण लाएं, तो

मैं देख सकता हूं लेकिन मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नही लाई गई है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की हो, वे पूरी सहायता किसानों की नहीं कर सकती जबतक कि किसान संगठित हो कर खुद अपनी सहायता न करें। दुनिया का कोई भी मुल्क मैं ऐसा नही जानता जहां के किसान अपने माल को बेचने के लिए स्वयं संगठित न हों। यहां पर ही ऐसा है कि सारी बातों की आशा सरकार द्वारा करने की की जाती है। कोई काम हो, वह केन्द्रीय सरकार की मदद से करना चाहते हैं और अगर केन्द्रीय सरकार से छुट्टी मिल जाए, तो राज्य सरकारों की मदद चाहते हैं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ने उत्पादन किया है क्या उस का कोई फर्ज नहीं है उस को अपने आप बेचने का। बेचने में कुछ मदद तो हो सकती है लेकिन दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, वे अपने सहकारी संगठन बनाते हैं और अपने माल को बेचते हैं। दूसरे देशों में जाने की जरूरत नही है। आप अपने यहां ही गुजरात को ले लें। उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरी जगहों के लोग भी यह कहते हैं कि धान का जो समर्थन मूल्य आप ने 85 रुपये निश्चित किया है, वह कम है लेकिन गुजरात के किसी किसान को इस के बारे में शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने किसानों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उसी धान को वे 85 रुपये की बजाए 100 रुपये पर किसानों से खरीदती है और उस धान को खरीद कर उस का चावल बनाती है और बगल में ही, फेयरप्राइस शाप के पास, उस को बेचती है। तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि लोग कुछ अपने कर्त्तव्य को समझें, जो जनता के नेता है और जो गांव वालों के प्रतिनिधि चुन कर आए है, वे उनको सुझाव दें, उनको संगठित करें।

यहां पर भ्रष्टाचार की काफी चर्चा की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भैंसों के लेन-देन में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय में एक दिन पूरी मीटिंग की गई, कुछ एम०पीज० भी थे लेकिन कुछ हल नही निकल सका। पूछा गया कि कोई हल हो तो बताया जाए लेकिन कुछ हल नही निकला। अन्त में इतना ही हल निकल पाया कि किसानों का कोई संगठन हो जो उनके हितों की वहां रक्षा करे तभी उनकी रक्षा हो सकती है।

अपने देश में क्या होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। गोंडा जिले में नलकूप बनाने के लिए एक संगठित प्रयास चल रहा है। उस में तो भ्रष्टाचार नही हो सकता है। बजाय इसके कि केवल शिकायतें करते रहें हम को देखना चाहिये कि आखिर हम भी प्रतिनिधि है, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है, वहां जा कर हम देखें और इसको दूर करवाएं....
(इंटरप्शंस)

एक माननीय सदस्य : संसद सदस्यों की बात कोई सुनता नही है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं नही मान सकता हूं कि संसद सदस्य अगर ध्यान दे तो उनके देखते हुए भ्रष्टाचार हो सकता है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Madam Chairman, at the outset I congratulate both the Ministers for having done good work and I support their demands from this side of the House for they have done good work in the field of sugar industry; they have reduce excise duty; they have decontrolled sugar and they have given freedom to the sugar factories to export sugar. This is a good thing which they have done.

The Food Corporation of India has done its best to accommodate as much foodgrains as possible and the procurement is more than the capacity of the godowns. Now the Minister says that he is going to construct some godowns in the villages. I want to know how much time he will take to complete that scheme. He wanted some cold storage. He must not put this scheme into cold storage; he must put it into action.

I also want to congratulate our scientific officers who are doing very good research work. They have produced high yielding and disease resistant variety; for which the Minister has not congratulated them; I want that at least his senior colleague Mr. Barnala should pay good compliments to scientists who have done excellent work. Nowhere in the world has such a phenomenon occurred. Our yields have gone up on account of the efforts of the government plus our scientific research work. They are doing good work in this country, which is comparable to any other country including America or Russia. It should not be forgotten. The worry in this country is not on how much we produce but now the fertility of the soil is decreasing; desert is advancing. I want to know from the Ministers what they are going to do, when they are going to complete the Rajasthan canal that can *stop* the advancement of the desert. It is a national prob-

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

lem; it is not the problem of Rajasthan. If anybody thinks that it is the problem of Rajasthan he is not doing justice to this country. Rajasthan canal must be completed in the shortest possible time and all the green patches that are to be developed must be developed. In this country we are mercilessly and wrecklessly cutting the trees; that is causing inundation by rivers which take away the fertile soil to the Bay of Bengal or to the Arabian Sea. That must be stopped. It is a national problem. I want that the fertility of the soil must not only be maintained but improved. One Minister is coming and another Minister is going. In between, whether the fertility of the soil is increased or not? This is important for this country and not how much we are producing?

Now the per acre yield will go down because you are producing more with the application of inorganic fertilisers. Inorganic fertilisers are destroying the fertility of the land. We want manure—cow dung and other organic matter. We want green leaves. The trees have been cut. In Haryana and in Punjab many trees have been planted and protected. In this country if 100 trees are cut, not a single tree is planted. Trees must be planted which will protect the fertility of the soil and prevent soil erosion. If there are no trees, soil erosion occurs. Due to soil erosion river belt is filled up. That is why floods are caused. Brahmaputra is eating away good soil of that area. Similarly soil erosion by sea is causing great havoc in all the coastal areas. Day by day our country is becoming small because of soil erosion by sea and rivers. What has been done in Bombay Marine Drive, such sort of thing must be done in this country. Then alone we can protect soil erosion by sea and wind. We must grow trees. We must have a plan. Formerly, our Shri K. M. Munshi had planned for tree-planting. That plan was not properly implemented for various reasons. I want to know from the Ministers how they are going to protect forests. The minimum requirement of the forest is that about 33 per cent o fthe total area of the land should be under forest. Now it has gone to 24 or 22 per cent. Day by day, it is decreasing. That is the greatest danger. Now the fertility of the soil has gone down. The production of the soil also will go down. It is a serious thing. This point has not been made by anybody.

It is very good that the Janata Government, for whatever it may be, they are paying attention to the kisans. In Andhra Pradesh our Chief Minister has exempted the land revenue on 2 1/2 acres and below. Will similar instructions be given to the other States—at least to the Janata ruled States? That must be implemented. If you protect the small farmers, then alone there will be prosperity. Of course, in your younger days you might have sung:

मेरी माता के सिर पर ताज रहे,

तो ताज तो आ गया है,

Now we are independent.

घर-घर में आदमी के अनाज रहे।

मगर घर-घर में अनाज नहीं है। तो आपके गोदाम भरने से लोगों का पेट नहीं भरना है। लोगों का पेट भरना है तो उनमें खरीदने की शक्ति पैदा करनी चाहिये। शक्ति पैदा करने के वास्ते आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास सरप्लस अनाज इस वास्ते है कि आदमी खरीद नहीं सकता है। आप फूड फार वर्क में खाना देकर उससे काम लेना चाहते हैं। यह स्कीम अच्छी होगी, मगर इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिये। देश के बाहर यह बात नहीं जानी चाहिये कि यहां के लोग इतने गरीब हैं कि खाना मिलने के नाम पर काम करने को तैयार हैं। यह हमारी सैल्फ रैस्पैक्ट के खिलाफ है। आप मेहरबानी कर के इस स्कीम का नाम बदल दीजिये। जैसा आपने विलिंग्डन हस्पताल का नाम डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल किया है, किसी और हस्पताल का नाम कृपलानी हस्पताल किया है और कुटुम्ब कल्याण बनाया है, इसी तरह से इसका नाम भी बदल दीजिये। यह फूड फार वर्क बहुत खराब चीज है, इसका प्रचार नहीं होना चाहिये।

यदि फूड फार वर्क के लिये लोग काम करने को आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग गरीब हैं। खाना खरीदना चाहते हैं, तो उनकी पर्चेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिये। फूड फार वर्क पर आपको पूरा ध्यान नहीं देना चाहिये।

• यह कहना कि फूड कार्पोरेशन सब करप्शन है फला है तो मेरी कांस्टीटुएन्सी में भी 7, 8 जगह फूड कार्पोरेशन खुले हैं एक दो जगह पर और खोलने का था। खाली मैं लैटर लिखता हूं कि वैइंग सैंटर और पर्चेजिंग सैंटर खुलें निजामाबाद आन्ध्र प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम०पी० इन्हें बुरा भला कहने को आते हैं वह खुद एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मैं कर सकता हूं तो दूसरे एम०पी० भी कर सकते हैं उसके वास्ते पार्लियामेंट का फोरम और समय बर्बाद नहीं होना चाहिये।

कौन ऐसा व्यक्ति है वह जैनरल मैनेजर हो या कोई और अफसर कि अगर कोई पार्लियामेंट का मम्बर डट कर कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो फिर भी वैसा करने की हिम्मत करे? हम लोग तो आपोजीशन में हैं जब हम लोगों की बात चलती है तो आप लोगों की गवर्नमेंट तो सैंटर और स्टेट्स में है आपकी बात क्यों नहीं चलती है? इन बातों की शिकायत यहां पर नहीं आनी चाहिए। मिनिस्टर साहब या फूड कार्पोरेशन के मैनेजर को एक लैटर लिखना ही काफी है। फूड कार्पोरेशन हो या कोई और संस्था हो ऐसा नहीं हो सकता है कि वह पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज की बात को न माने। आखिर इसमें हमारा कोई पर्सनल गेन तो नहीं है। हम किसानों के नुमायंदे हैं। हम यही चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए उनकी लूट खसूट नहीं होनी चाहिए और उन्हें व्यापारियों के चंगुल से बचाना चाहिए। ये काम करने के लिए हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं। अगर हम लोगों की बात वहां नहीं चलती है तो मिनिस्टर साहब को कहने से वह आदमी वहां से जा सकता है सस्पेंड और डिसमिस हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस बारे में प्रयत्न करना चाहिए।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय कृषि मंत्रालय की अनुदान-मांगों पर बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज कल कृषि के बारे में हमारे देश में आम धारणा बन चुकी है कि हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है और हम दूसरे देशों को अनाज भेजने लगे हैं। यह एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इस के लिए हम सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देना चाहते हैं। यों तो हमारे देश में जो क्लाईमेट है वह भी इस स्थिति के लिए मुख्य रुप से बहुत हद तक जिम्मेदार है जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन हमें अभी बहुत कुछ कार्य करने हैं। सब से पहले मैं फ्लड कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि हमें कृषि को बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये हैं लेकिन इस बारे में जितनी तत्परता की आवश्यकता है वह हमें नीचे के कर्मचारियों और दूसरे लोगों में दिखाई नहीं देती है जो इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार है। मैं खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम नदियों में हर साल भयंकर बाढ़ आती है जिससे कृषि को बहुत नुकसान होता है। मैं अपने जिले गोरखपुर में राप्ती घाघरा रोहिणी और नारायणी नदियों की बाढ़ के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बांध बनाने की स्कीम चालू की गई है उसे अतिशीघ्र कार्यान्वित कराये अन्यथा इस समय लोगों को बहुत क्षति उठानी पड़ती है और कृषि का बहुत नुकसान होता है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर भारत और देश के काफी बड़े हिस्से में फ्लड कंट्रोल के लिए कैप्टन दस्तूर की गारलैंड कैनाल की स्कीम पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। उन्हें संसद् सदस्यों की एक मीटिंग में बुलाया गया था जिसमें उन्होंने गारलैंड कैनाल स्कीम के बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया था। जो बातें उन्होंने बताई थीं अगर वे सब ठीक हैं तो हम कह सकते हैं कि गारलैंड कैनाल के बनने के बाद न केवल बाढ़ पर नियंत्रण हो जायेगा बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है। इस लिए इस स्कीम पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। योजना मंत्रालय की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था और कहा था कि सरकार उसके बारे में कार्य कर रही है। लेकिन यदि वह बहुत ही यूजफुल स्कीम है तो देखना चाहिए कि उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये।

फ्लड कंट्रोल के अलावा दूसरी बात मैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने जब कभी भी इस सवाल को सदन में उठाया है बराबर यह कहा है कि शुगर इंडस्ट्री में तमाम मिल मालिक हमारे किसानों का और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। उस शोषण से मुक्ति के लिए और साथ ही उस पर पूरी तरह से एक नियंत्रण स्थापित रखने के लिए जिस से कभी उस की कमी न होने पाये शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए।

लैंड रिफार्म के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लैंड रिफार्म की जो स्कीम चलाई गई है उस में अभी भी ठीक ढंग से जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है। इस में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी इस में तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। तमाम गांवों के अंदर सीलिंग के बाद जमीन निकली हुई है लेकिन उस का ठीक ढंग से बंटवारा नहीं हुआ है। जिस की जमीन निकली हुई है वही लोग उस पर खेती भी कर रहे हैं। इसलिए आज जो कृषि के कार्य में लगे हुए मजदूर हैं उन की दशा सुधारने के लिए और साथ ही भूमिहीनों की दशा को भी सुधारने के लिए उस भूमि के बंटवारे पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उस में किसी प्रकार की कमी करना देश के गरीब लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा जब कि हमारी सरकार वचनबद्ध है कि गरीबों का हित करेंगे।

[श्री हरीकेश बहादुर]

वनों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे पहाड़ों के अन्दर जो जंगल काटे जा रहे हैं या काटने की जो योजनाएं हैं उन्हें तुरन्त रोकना चाहिए। हमें नये जंगल लगाने चाहिए न कि ऐसी जगहों से जंगल काट लेने चाहिए खास तौर से पहाड़ों में जंगल काट लेने से जो भू-स्खलन होता है उस से कितनी हानि उठानी पड़ती है। अभी भागीरथी में भू-स्खलन के बाद जो एक बहुत बड़ी चट्टान आ कर रुक गई थी उस से कितना खतरा पैदा हो गया था यह हमें पता है। तो जंगल काटने से इस तरह की घटनाएं होती हैं इसलिए बजाय जंगल काटने के नये जंगल लगाने की दिशा में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

इर्रीगेशन फैसिलिटीज के बारे में यह जान कर के हमें प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन हमें इस दिशा में भी बहुत तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को जहां केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए पैसे देती है वहीं उसे पैसे दे कर ही अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो जाना चाहिए बल्कि बराबर राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव भी डालने की कोशिश करते रहना चाहिए कि राज्य सरकारें इस काम को पूरी तेजी से करें। अगर इर्रीगेशन फैसिलिटीज ठीक ढंग से नहीं दी जायगी तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और हम आत्म निर्भरता के जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बतायी हैं। बात बहुत उत्साह-वर्द्धक है। बहुत तेजी से यह काम हो रहा है और खास तौर से यह जो फूड फार वर्क स्कीम चली है उस में तमाम गांवों के अन्दर लिंक रोड्स बन रही हैं और दूसरे तरह के भी कार्य हो रहे हैं लेकिन उन कार्यों में जिस तरह की तेजी होनी चाहिए वह नहीं है क्योंकि हम ने देखा है कि सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं वे लोग उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन के न ध्यान देने के बावजूद भी क्योंकि जन प्रतिनिधियों का उन पर दबाव रहता है इसलिए काफी काम हुआ है। अगर उस मशीनरी को स्ट्रीम लाइन करने की व्यवस्था की जा सके तो वह भी करना चाहिए और सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए।

इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह संगठन हमारे देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नये अनुसंधान करने के लिए बनाया गया था और इस ने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह पता नहीं चलता कि यह संस्था कृषि उत्पादन के लिए बना है या सूसाइड के नये नये तरीके ढूंढने के लिए। हमेशा ही वहां पर सूसाइड होता रहता है और नये नये तरीके से होता है। कभी कोई गले में फन्दा लगा लेता है कभी कोई ऊपर से कूद जाता है कभी कोई तीसरी मंजिल से कूदता है कभी कोई चौथी मंजिल से कूदता है। इस तरह के तमाम कार्य वहां पर हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि वहां पर क्या कारण है जो इस प्रकार की बातें होती हैं। कहा जाता है कि आई० सी० ए० आर० में वैज्ञानिकों के गुट बन हुए हैं और वे एक दूसरे से इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा में रहते हैं कि एक दूसरे का पांव खींचने में लगे रहते हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि सही तरीके से वहां उनको प्रोमोशन वगैरह मिले और जो सुविधाएं आवश्यक हैं वह मिले। इस पर ध्यान देना चाहिये।

पोटैटो रिसर्च इंस्टीच्यूट जो है उस के बारे में मैं ने एक पत्र लिखा था माननीय मंत्री जी को 23 नवम्बर 1978 को। वह पत्र उन्होंने एकनालेज किया है। उस के बाद उस में क्या हुआ यह कुछ नहीं पता चला। वहां के निदेशक के बारे में मैंने कुछ आरोप लगाए थे जो मुझे मिले थे। वह मैंने उन को भेजे थे। मुझे लगता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई अन्यथा माननीय मंत्री जी ने हमें सूचित किया होता। इस प्रकार से तमाम लोगों के बारे में जैसा कि अभी भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग कोई बात बताते नहीं हैं तो हम बताते हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उससे बड़ी निराशा होती है। जहां तक माडर्न बेकरी का सम्बन्ध है वहां पर कोई ब्रिगेडियर थे पहले वे मैनेजिंग डायरेक्टर उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। उनके खिलाफ तरह तरह के चार्जेज थे। शायद सी बी आई के द्वारा भी इन्क्वायरी हुई थी। उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है—इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। सम्भवतः कोई कार्यवाही हुई हो नहीं है। आज माडर्न बेकरी की स्थिति यह है कि उसकी यूटि-लाईजेशन कैपेसिटी लगातार घटती चली जा रही है। मंत्रालय की ओर से जो किताब दी गई है उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं किन्तु उसकी स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। उसमें केवल नौकरशाही का ही बोल बाला है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कम्पनी पेय-77 का उत्पादन भी कर रही है लेकिन यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि पेय-77 का कंजम्शन उस मात्रा में नहीं हो रहा है जितना कि दूसरे पेयों का है। कम्पनी अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी का नहीं बना पा रही है जिस क्वालिटी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी उद्देश्य थे जिनके लिए आप काम करना चाहते थे लेकिन आज वे सारे काम बन्द हो गए हैं।

दिल्ली मिल्क स्कीम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको कम्पनी के रूप में बदलने की योजना बना रही है जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों में क्षोभ व्याप्त है। वे यह समझते हैं कि कुछ नये तरीके के उपकरण आयेंगे और कम्पनी बना कर कुछ इस प्रकार के काम किए जायेंगे जिनमें तमाम लोगों का रेट्रेन्चमेण्ट होगा। तो इसको बचाने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एफ सी आई के गोदामों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षेप में, जो प्वाइंट्स मैंने लिख रखे हैं उनको बता रहा हूं ताकि मंत्री जी उन पर ध्यान दे सकें। एफ सी आई के गोदामों के

लिए वर्ल्ड बैंक ने लगभग 360 करोड़ रुपया दिया है लेकिन अभी तक उस काम की शुरुआत ठीक ढंग से नहीं हुई है। खास तौर से रूरल एरियाज में कहीं एफ सी आई के गोदाम नहीं बन रहे हैं। यदि उत्पादन बढ़ा है तो उस का रखने के लिए जगह भी चाहिये। हमेशा अनाज सड़ता है और हमेशा इस सदन में तरह तरह की बातें आती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस के अलावा बोरों की कमी की बात भी कही जा रही है। यदि बोरे नहीं होंगे तो उस को कैसे रखा जायगा ? यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोपाउड रेलवे लाइनइन रूरल एरियाज के बारे में रेल मंत्री जी ने कहा था कि वहां कृषि फार्म है जहां कृषि की काफी पैदावार होती है वहां रेलवे लाइन बनाएंगे। मझे पता नहीं रेल मंत्रालय की ओर से कोई पत्र आप के पास आया है या नहीं जिसके आधार पर आप बता सकें कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे लाइन बनाई जायगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जो रामपुर काठगोदाम लाइन है वहां पर कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। रामपुर काठगोदाम की पहले से ही प्रापाउड लाइन थी लेकिन उस को रोक दिया गया है। उस का रेलवे बनाने नहीं जा रही है। इसलिए कृषि मंत्री जी को कहना चाहिये कि रेलवे ने अगर इस तरह की कोई योजना बनाई है तो उस रेलवे लाइन को फौरन बनाना चाहिये।

गेहूं वगैरह की प्राइस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कृषक जो कुछ भी पैदा करते हैं उस का उचित मूल्य उन को मिलना चाहिये। उस का क्या प्रबन्ध हो रहा है उस के बारे में मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये। खाद के दाम तो जरूर कम किए गए हैं। पहले भी कुछ कम हुये थे। अनाज के दाम भी कुछ बढ़ाए गए हैं लेकिन उस के बावजूद कृषक महसूस करता है कि उस को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। मझे उम्मीद है कि मंत्री जी अपने जवाब में इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। किसानों को राहत देने के लिए वे खास तौर से कुछ योजनायें बनायेंगे। अन्त में पुन दोहरा देना चाहता हूं कि फ्लड कण्ट्रोल के ऊपर वह विशेष रूप से ध्यान दें क्यों कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हमेशा बाढ़ से जलमग्न हो जाता है और उस में बड़ी क्षति होती है।

SHRI K. MALLANNA (Chitradurga): Madam Chairman, at the outset I want to congratulate the Agriculture Minister for having tried to help the agriculturists in the country. 60 per cent of the agricultural families are living below the poverty line. Government have introduced some measures in order to improve their economic condition in the rural areas, like the Food for Work Programme, Drought-Prone Areas Programme, Desert Area Development Programme, Small Farmers Development Agency, Tribal Area Development Programme and Hilly Area Development Project, apart from the Antyodaya or village development These are the measures taken by the Government to ameliorate or improve the working conditions of the rural folk.

Madam Chairman, I am coming from a constituency which has been declared as a backward area by the Planning Commission and almost all of my constituency is covered by the DPAP programme and also by Small Farmers Development Agencies (SFDA). Both these programmes are Centrally sponsored schemes. These schemes are introduced just to help the rural folk, i e, the very oppressed and depressed class in the existing rural society.

Madam Chairman, the drought-prone area in the country covers nearly 74 districts in 13 States. That means, it covers 12 per cent of the total population In terms of area it covers 5.66 lakh square kilometres, that is, 20 per cent of this area I find now that for the year 1979-80 it has been allotted Rs. 59 44 crores I feel it is very insufficient because the Planning Commission has declared more than 200 districts as backward areas under the drought-prone area programme. Madam the idea behind this is to tap the underground water and to irrigate these areas with underground water and river water. They have taken up soil conservation, then horticulture and so many other programmes to improve and provide jobs to the rural people, namely, the small farmers and the agriculturists

Madam Chairman, under the IRD programmes that is the Integrated Rural Development programmes, the DPAP and SFDA programmes are included. Unfortunately they have not planned anything except mentioning about some soil conservation and some afforestation. Planning should be made according to the situation of the area. Take, for example, my constituency.

[Shri K. Mallanna]

Though it is declared as under drought-prone area programme, they want to dig up the underground water. There is a big river called Bhadra going by the side of my constituency If Bhadra water is taken to my constituency, it covers about 12 to 13 taluks. Then if all the 12 or 13 taluks are irrigated by this Bhadra project, I think what the Government has thought to improve this under the DPAP programme will be successful It is only by investing money on the minor irrigations, that too which cost above Rs 50,000, that success can be achieved. But nothing is mentioned about minor irrigations, about the tubewell's and borewells. If we request the agency to take up a tube well or bore well, they will say it does not come under minor irrigation, and so it cannot be taken up under DPAP But then, how can you tap underground water without tube wells or bore wells? So, it is only a name sake

In the DPAP areas, agro-based industries should be started They are said to be encouraging horticulture, sericulture, piggery, poultry etc, but it is all only in name because implementation is not properly done I want the Ministry to take up these things intensively.

So far as advance of loans to these programmes is concerned the banks are giving a lot of trouble and causing a lot of inconvenience to the poorer section of the society. Though a subsidy of 30 to 60 per cent is given to agricultural labourers and farmers, the nationalised and local banks are not coming forward to help these poor people. So, I request the hon. Minister to look into the matter and give them easy loans

Unfortunately, though these programmes are meant for the economic development of the poorer sections, they have not been properly implemented. I suggest that agricultural centres should be started at least in the DPAP areas like the industrial centres which have been started in the city and town areas to help small-scale and other industries.

The poor ryots and agricultural labourers have no house or shed to rear poultry. When they ask for a loan, the bank people enquire if they have got a shed or a house, and that too scientifically constructed. They say they cannot afford it, and the bank people do not give the money.

Similarly, sericulture requires well-built weather-proof houses for the cocoons to be reared properly, but small farmers owning two or three acres of land are unable to build these houses, and the bank people are not giving them money, with the result they are unable to take to this industry

If at all there is any programme to help the rural folk, it is the dairy farming programme Here also, the bank people reject loan applications on the ground that the ryots have no proper cow sheds I would request the hon Minister to consider all these things and to establish agricultural centres in the rural areas.

I want to stress one more point. As far as the milk societies are concerned, we have to consider the pricing policy. In my State, the State Government, has, with great difficulty, introduced in certain pockets a scheme called Karnataka Dairy Scheme, under which the minimum price fixed for milk is Rs. 1 35 per litre. In Gujarat it is Rs. 1.65. I do not know about other States. The cost of the inputs are rising. The cost of feeding the cattle has gone up. The cost of buffaloes and cows has also gone up. So, they are not able to maintain the cattle. It is very difficult to purchase milch animals because they are very costly. So, I would request the hon. Minister to fix up the minimum price for the milk because that would help many people in the rural areas. It would also give employment to many people. Easy availability of manure would enable them to improve the fertility of the land.

Then I would come to the marketing facilities in the rural areas. Under DPAP programmes, poor ryots and agriculturists are being given loans to purchase buffalows and cows. But they are not finding market for the milk So, they are unable to repay the loans advanced to them. So, I would request the Minister to take the necessary steps to improve the marketing facilities If they are really keen to improve the economic condition of the small and marginal farmers, they have to establish agricultural centres, fix the minimum price for their produce and also improve the marketing facilities

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, अभी जो बहस चल रही है, उस के बारे में सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों से सम्बन्ध रखने वाली इस बहस में तीन तरह के लोग है, जिन्होंने हिस्सा लिया है। एक तो वास्तव में किसान है, जो गांव में खेत की मेंढ पर खड़ा हो कर अपनी खेती करता है। दूसरा वह है, जो कोठी शहर में रखता है लेकिन उस का फार्म देहात में है और वह भी अपने आप को किसान कहता है और तीसरे ऐसे लोग हैं जो एअर-कण्डिशण्ड मकानों में गद्दों पर बैठ कर केवल किसानों से सम्बन्धित कुछ किताबें पढ़ कर ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और वे भी अपने आप को किसान समझते हैं।

सही मायने में गांव की समस्या के बारे में ऐसे लोग विचार करते हैं जिन्होंने गांव को कभी देखा नहीं, जिनके घर की औरतों को भादों की अंधेरी रात में टिहुना भर कीचड़ हेल कर कभी सड़क के किनारे पाखाने पर नहीं बैठना पड़ा, वह कभी गांववाली औरतों की कठिनाई के बारे में नहीं जान सकते। आज भी गांव में बसने वाली करोड़ों ऐसी औरतें हैं, जिनको 12 घण्टे तक पाखाने को अपने पेट में सड़ा कर रखना पड़ता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनके पाखाना जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्यास्त होता है तो गांव के बाहर जब पाखाने को जाती है और सड़क के किनारे पर पाखाने पर बैठती है, उस समय कोई राही रास्ते से निकलता है तो आधा पाखाना पेट में लेकर खड़ी हो जाती है। गांव में बसने वाली उन करोड़ों औरतों के बारे में वही जान सकता है जिस ने कभी उस वातावरण को देखा हो, वहां पला हो, जिसको उस वातावरण की असलियत का ज्ञान हो। आजाद भारत में गांव में बसने वाली करोड़ों महिलाओं के पाखाना जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई और न जनता राज्य में ही उस तरफ कोई दृष्टि है और न उसको सुधारने की चिन्ता है।

जिस देश में माताएं रोगिणी होंगी, रोगिणी के पेट से कभी स्वस्थ संतान पैदा नहीं हो सकती, देश की संतान मां के पेट से ही रोगिणी होगी, उस संतान से कभी देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अगर सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो गांव की करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पहले उनके पाखाने की व्यवस्था करनी होगी।

आज हम खेती पर चर्चा करते हैं। खेती के लिये जो लोग पिस रहे हैं, एक तरफ सरकारी तंत्र है और दूसरी तरफ व्यापारी। इस व्यापारी और नौकरशाही की चक्की में खेती पिस रही है। कबीरदास ने कहा था—

चक्की चलते देख कर दिया कबीरा रोय,
दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय।

व्यापारी की बात जब हम करते हैं तो उसको क्यों नहीं बढ़ावा मिलेगा? व्यापार में लाइसेंस, परमिट, घूस, तरक्की, मुनाफा और फाइव-स्टार होटल सब कुछ है लेकिन खेती में न लाइसेंस, न परमिट, न घूस और न खेती करने वालों के पास फाइव-स्टार होटल जहां वह मौज कर सके। जहां सुख और सुविधाओं का अम्बार है, वहां व्यापार की तरक्की होगी, खेती में यह सुख-सुविधाएं नहीं हैं इसलिए किसानों की उपेक्षा होती रहेगी। आज जब यह कहते हैं कि जनता सरकार ने बहुत ज्यादा किया, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में गांव के प्रति, किसानों के प्रति कुछ ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देख लें कि शहरों में बसने वाले जो मुट्ठीभर आदमी हैं, जिनके हाथ में समाचार पत्र हैं और दूसरे साधन हैं वही आज वित्त मंत्री के खिलाफ और इस बजट के खिलाफ हंगामा खड़ा किये हुए हैं कि यह बजट महंगाई का बजट है और फला है।

मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों में आपने गांव के लिए क्या किया है यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी और दूसरे लोग कहते हैं कि गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया गया है, गांव पर बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन हैरत में पड़ जाता हूं जब इनका दिया हुआ इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण देखता हूं जिसमें लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर जहां कृषि और समस्त क्षेत्र पर 14.7 प्रतिशत खर्च किया गया था, वहां 1978–83 की योजना में जो इन्होंने दर्शाया है वह 13.7 प्रतिशत है। यह आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं का दिया हुआ है। यह कहते हैं कि खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां 11.7 प्रतिशत खेती पर व्यय था वहां 78–83 वाली प्रस्तावित योजना में इसे घटाया गया है जिसका प्रारूप अभी तैयार नहीं है। उसमें 13.7 प्रतिशत है और 1978–79 वाले परिव्यय में बताया है कि 15.0 है। सिंचाई में जहां चौथी योजना में 8.6 प्रतिशत बताया गया है वहां 1978–83 वाली योजना में 11.5 है, केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि यह बता रहे हैं। 1978–79 में जो 10 प्रतिशत इन्होंने खर्चे में रखा है जब कि 1978 से 83 वाली योजना में 1 प्रतिशत कमी है।

उद्योग में जहां चौथी पंचवर्षीय योजना में 18.2 प्रतिशत इन्होंने रखा था वहां 1978–83 की

(श्री हुकम देव नारायण यादव)

योजना मे 19 2 प्रतिशत है। यहा भी जो बडे उद्योग है, उसके अनुसार अगर चौथी पच वर्षीय योजना के मुकाबले इनकी जो योजना बनन जा रही है उसमे इन्होंने 1 2 प्रतिशत ज्यादा खर्च रखा है और कृषि में 1 प्वाइण्ट कम कर के रखा है। यह इनकी सर्वेक्षण की किताब में प्रकाशित हुआ है।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर मे वित्त मत्री ने नवम्बर, 1978 तक बैंको द्वारा दिय गय कर्जों के बारे म ये आकडे दिये कृषि 11 5 प्रतिशत लघु उद्योग 11 6 प्रतिशत बडे उद्योग 39 6 प्रतिशत। हिन्दुस्तान के लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते है और 80 10 प्रतिशत लोग गावो मे बसते है। कृषि पर निर्भर करने वाले लगभग 70 प्रतिशत लोगो का केवल 11 5 प्रतिशत बैंक ऋण दिये गये जब कि बडे उद्योगो को 39 6 प्रतिशत दिये गये। ये आकड क्या दर्शाते है? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम खेती की तरफ बढ रहे है और बडे उद्योगो मे एकाधिकार को खत्म करने के लिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ रहे है। लेकिन बैंको का दृष्टिकोण यह बताता है कि सरकार आर्थिक विकेन्द्रीकरण और खेती की तरफ नहीं बढ रही है क्योकि कृषि को कम ऋण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय माननीय सदस्य दो मिनट मे समाप्त करे।

श्री हुकम देव नारायण यादव : अन्य सदस्यो को 15, 15 मिनट दिय गये है। मुझे थोडा समय और दिया जाय।

सभापति महोदय नही माननीय सदस्य दो मिनट मे समाप्त कर दे।

श्री हुकम देव नारायण यादव जिस देश मे खेती पर भार जितना कम होता है वह देश उतना ही धनवान होता है। क्या कृषि मत्रालय द्वारा इस दिशा मे कोई कार्यवाही की जा रही है कि खेती पर से भार को कम किया जाय? खेती पर भार तब तक कम नही होगा जब तक कि कुटीर उद्योगो को बढावा नही दिया जायगा। रूस मे कुल आबादी का 31 9 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है अमरीका मे 4 0 प्रतिशत ब्रिटेन मे 2 8 प्रतिशत और जापान मे 20 7 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है लेकिन भारत मे जनसख्या का 69 7 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर करता है।

यह दर्शाता है कि जिस देश मे खेती पर जितनी कम जनसख्या का भार है वह देश उतना ही मालदार और खुशहाल है लेकिन जिस देश मे खेती पर ज्यादा जनसख्या का भार है वह देश उतना ही गरीब है। अगर हम भारत जैसे गरीब देश के आगे बढाना चाहते है उसकी तरक्की करना चाहत है तो खेती पर से भार को कम कर के अधिक से अधिक लोगो को कुटीर उद्योगो की तरफ ले जाना होगा। लेकिन कुटीर उद्योगो का विकास तब तक नही हो सकता है जब तक कि हम यह तय न करे कि जिन वस्तुओ का निर्माण मनुष्य के हाथो से हो सकता है उनका उत्पादन बडे कारखाना मे नही होगा।

मेरे सामने प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे मे भारत सरकार के ये आकडे है —

	1955-56	1977-78
	किलोग्राम	किलोग्राम
खाद्य तेल	2 5	3 9
चीनी	5	7 2
सूती कपडा	11 4 मीटर	11 8 मीटर

इससे पता चलता है कि जहा 1955-56 म कपडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 11 4 मीटर थी वहा 1977-78 मे वह घट कर 11 मीटर रह गई। एक तरफ रुई के दाम रकम हो रहे है और दूसरी तरफ कपडे के दाम बढे रहे है।

18 hrs

गावो के सुधार की बात कही जाती है मगर श्री जार्ज फर्नांडीस उद्योग मत्री ने कहा है कि नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन अपने उत्पादन मे से केवल 40 प्रतिशत मोटा और साधारण कपडा बनाता है। मै निवेदन करना चाहता हू कि जिस देश म 60 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते है और 80 फीसदी लोग गावो मे रहत है वहा की नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन का दृष्टिकोण यह होना चाहिय कि वह अपने उत्पादन का 60 या 80 फीसदी मोटा और साधारण कपडा तैयार करे। पैसा करने पर ही गाव वालो के तन पर कपडा हो सकता है। इस लिए अगर सरकार किसानो और गाव वालो के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे इस दिशा मे सोचना होगा।

1971-72 मे कृषि उत्पादो का सूचकाक 100 4 था और थोक कीमतो का सूचकाक 105 6 था। 1971-72 से लेकर दिसम्बर 1979 तक थोक कीमतो का सूचकाक निरन्तर बढता चला गया है और यही स्थिति विनिर्मित उत्पादो के सूचकाक की रही है जो लगातार बढता रहा है। कृषि के सूचक अक हास की ओर गए है। अप्रैल 1977 मे जहा दूसरी वस्तुओ का सूचकाक 184 था वहा कृषि का 172 था। 1978 मे जहा दूसरी वस्तुओ का सूचकाक 184 पर ही खडा है वहा कृषि उत्पादन की वस्तुओ का सूचकाक 172 से घट कर 169 पर चला आया है। तो लगता है कि कृषि उत्पादन की वस्तुओ का सूचकाक ह्रास की ओर चला जा रहा है और दूसरी वस्तुओ का सूचकाक बढता चला जा

रहा है। जब तक उस का रोका नहीं जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए।

---

18 02 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

POSTAL ACCOUNTS IN HARYANA

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) सभापति महोदया, 12-3-79 का प्रश्न संख्या 284 का जो उत्तर दिया गया है उस के बारे में मैं यह चर्चा चलाना चाहती हूं। उस दिन सवाल के जवाब में जो बताया गया उस में यह कहा गया कि 50 हजार रुपये से ऊपर के जो डिपाजिट्स 1974 में हरयाने के पोस्ट आफिसेज में किए गए उस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। मैं उस दिन बराबर पूछती रही कि कुल मिला कर 74, 75 और 76 तीन सालों में इस प्रकार के कितने लोगों ने डिपाजिटस किए थे और कितनों के बारे में जांच अभी तक हो गई है। मुझे जो मालूमात मिली है उस के मुताबिक 1974-75 और 76 में लगभग 712, पचास हजार रुपये के ऊपर के डिपाजिटस हरयाना के पोस्ट आफिसेज में हुए। इस के बारे में देखने लायक चीज तो यह है कि उस में कई डिपाजिट्स ऐसे हैं कि वहां 30 मार्च को डिपाजिट किया, 2 अप्रैल को पैसा उसी एकाउंट में से वापस ले लिया, 29 मार्च को डिपाजिट किया और 2 अप्रैल को वापस ले लिया या फिर 31 मार्च को डिपाजिट किया और 3 अप्रैल को ले लिया। ऐसे ही तीन चार दिन के लिए इतनी बड़ी रकम डिपाजिट कर के जो वापस ले ली गई उसमें कई व्यक्तिगत डिपाजिट्स भी हैं, कई म्यूनिसिपैलिटीज के हैं, कई पुलिस इंसपेक्टर्स के हैं तहसीलदार के हैं, डी एम्स के हैं, कोआपरेटिव मिल्स के हैं, जिला परिषदों के डिपाजिट्स हैं, कई तरह के डिपाजिट्स इस प्रकार के हैं और इस के बारे में दिसम्बर, 1977 से इस सरकार के पास लगातार कई शिकायतें आई हैं, इसके बावजूद भी अभी तक इन की जांच पूरी नहीं हुई है यह हमारी शिकायत है।

उस दिन के सवालों के जवाब में कम्यूनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस में केवल 13 केसेज हैं जिन में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी, उस दिन भी मैं बार-बार कह रही थी कि जो 10 फरवरी, 1978 के करेक्ट में आया है, उस में जो लिस्ट आई है और जो पचास नाम आए हैं उस में से 13 केसेज ऐसे हैं कि जहां पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स वायोलेट हुए हैं लेकिन उस के साथ साथ बाकी कई डिपाजिट्स के केसेज हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुल मिला कर कितने ऐसे केसेज हैं। केवल करेक्ट में जो पचास केसेज दिए गए हैं उन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 74, 75 और 76 सालों में कुल मिला कर कितने एकाउंट ऐसे खोले गए, कितनों के बारे में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन हुआ और उन के बारे में अभी तक क्या हुआ?

मंत्री महोदय उस दिन बार बार कहते रहे हैं कि जांच चल रही है, ऐक्शन ले रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की बातें वह करते रहे। मेरा यह कहना है कि जब 77 साल से यह बात चल रही है और अब काफी बातें सामने आ गई हैं, इनकम टैक्स विभाग भी इस के बारे में तलाशी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 2 मार्च 1979 को कंवर लाल गुप्त जी के अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1762 का जो जवाब दिया गया है उस में 1974 साल के 5 लाख के ऊपर के जो डिपाजिट्स हैं, उन के 85 कैसेज के नाम दिए गए हैं। मुझे खेद है कि इस लिस्ट में भी नाम दिया है, कितना डिपाजिट रखा उस की तारीख दी है लेकिन उस का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि यह डिपाजिट फिर से वापस कब लिए गए, कब विदड्रा किए गए, क्या एकाउण्ट था इस की तारीख नहीं है। इस से ज्यादा शक होता है। दो तीन दिन के लिए पांच लाख आठ लाख दस लाख ऐसा एमाउण्ट रखा गया। किस के नाम से रखा गया, क्या बेनामी एकाउण्ट थे, इस के बारे में तीन केसेज के बारे में तो उस दिन भी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा था कि ये बेनामी एकाउण्टस हैं, ऐसा लग रहा है—आर पी सी का पांच लाख का डिपाजिट, श्री एन के गंग, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हरयाना गवर्नमेंट का पांच लाख का डिपाजिट और श्री कश्मीरी लाल, दि दून स्टूडेंट आफ डेलही यूनिवर्सिटी का 1 करोड़ 35 लाख का डिपाजिट। मैं कहना चाहूंगी कि केवल 74 साल के बारे में ही आप मत कहिये, 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में लगातार हरियाणा के पोस्ट आफिसेज में इस प्रकार के एकाउण्ट्स खोले गए। ऐसा लग रहा है कि इस का उपयोग बेनामी एकाउण्ट्स खोल कर कुछ राजनैतिक कामों के लिए हो रहा था। तो क्या यह बात सही नहीं है? इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। कहां तक इस की जांच हुई है, यह मैं जानना चाहूंगी।

तीसरी बात यह है कि जो जांच अभी तक हुई उस के आधार पर क्या आप ने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन के ऊपर कोई ऐक्शन लिया? आप ने कहा है कि तीन पोस्ट मास्टर इन्वाल्व्ड हैं। उस दिन भी आप ने यह कहा था। तो इस में ऐक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस से ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो शक पैदा हुआ है वह बिल्कुल वाजिब है। तीन दिन के लिए, 6, 8 या 10 लाख कोई नहीं रखता है। कुछ न कुछ इस में दाल में काला है। असलियत क्या है वह सदन की जानने की इच्छा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप कृपा कर के पूरी तरह से बताएं। उस दिन जैसा लग रहा था कि तेरह केसेज ही हैं, उन में से कितनी पर ऐक्शन ले रहे हैं या लेने का विचार चल रहा है, इस प्रकार की बात आप मत करें। मतलब 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में कितने एकाउण्ट्स थे